सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

समुत्थानशील भारत - आपदा मुक्त भारत

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

समुत्थानशील भारत - आपदा मुक्त भारत

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट एनआईडीएम 2022–23

कॉपीराइट © 2023, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली

प्रकाशक

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार),
प्लॉट नंबर 15, पॉकेट–3, ब्लॉक–बी,
सेक्टर–29, रोहिणी, दिल्ली–110042

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

दृष्टिकोण

''भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान बनना और क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी संस्थानों में से एक के रूप में पहचान स्थापित करना। सभी स्तरों पर आपदा निवारण और तैयारी की संस्कृति को विकसित करना और उसे बढ़ावा देकर आपदा-मुक्त भारत निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना''

(18 अप्रैल 2007 को आयोजित संस्थान (निकाय) की पहली बैठक से ली गई पंक्तियां)

विषय सूची

		पेज संख्या
अध्याय 1	सिंहावलोकन	1
अध्याय 2	संगठनात्मक व्यवस्था	7
अध्याय 3	प्रशिक्षण कार्यक्रम	15
अध्याय 4	परियोजनाएं	25
अध्याय 5	ज्ञान प्रबंधन और जागरुकता गतिविधियाँ	39
अध्याय 6	कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन/आमने-सामने कार्यक्रम	55
अध्याय 7	वित्त और लेखा	107
अध्याय 8	अनुलग्नक	133

nidm
Resilient India - Disaster Free India

राजेन्द्र रत्नू, भा. प्र. से.
कार्यकारी निदेशक

Rajendra Ratnoo, IAS
Executive Director

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
National Institute of Disaster Management
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
प्लॉट नं. 15, ब्लॉक बी, पॉकेट 3,
सेक्टर 29, रोहिणी, दिल्ली - 110042
Plot No. 15, Block B, Pocket 3,
Sector 29, Rohini, Delhi-110042



कार्यकारी निदेशक के लेखन पटल से

भारत में, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों एवं अनोखी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपदाएँ बार-बार घटित होती रहती हैं। ऐसी विनाशकारी घटनाओं से भारतीय आबादी के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापक अनुभव और ज्ञान की विकसित होती रूपरेखा के आधार पर, पिछले कुछ वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा शमन पर जागरूकता फैलाने के प्रयास में एनआईडीएम के आवश्यक योगदान को शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, एनआईडीएम को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन और नीति प्रचार के कार्यों की मुख्य जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। एनआईडीएम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय एजेंडा के शीर्ष पर लाने तथा विभिन्न स्तर पर हितधारकों, विशेषकर राज्य सरकार के संस्थानों के बीच डीआरआर पर ज्ञान की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आपदा जोखिम प्रबंधन को सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर विकास योजना में आसानी से समाहित करने के लिए भारत सरकार ने व्यापक संवाद के लिए अन्य हिस्सेदारों जैसे मीडिया, अंतरराष्ट्रीय संगठन, एनजीओ, अन्य वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक मल्टी-स्टेकहोल्डर नेशनल प्लेटफार्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (NPDRR) का गठन किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ''परिवर्तित जलवायु में स्थानीय प्रतिरक्षा का निर्माण'' विषय पर एनपीडीआरआर की तीसरी बैठक, 10-11 मार्च 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रधानमंत्री के एजेंडा 10 पर विशेष ध्यान देने के साथ आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय प्रतिरक्षा मजबूत बनाने के

विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और इसके साथ ही, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिसास्टर रिस्क रिडक्शन (SFDRR), पेरिस क्लाइमेट समझौता और सतत् विकास लक्ष्यों ((SDGs) के एकीकृत क्रियान्वयन में उनके महत्व पर भी चर्चा हुई।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर माननीय प्रधानमंत्री के दस सूत्रीय एजेंडा 6 के अनुसरण में, एनआईडीएम द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों का नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) स्थापित किया गया है। यह शिक्षा, नवीन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को बढ़ावा देने, क्षमता विकास की सुविधा के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए), आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030), और सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) पर वैश्विक मुद्दों के लक्ष्यों की दिशा में एक कदम है, और स्थानीय जोखिमों और विभिन्न आपदाओं से प्रभावित समुदाय के सबसे कमजोर वर्गों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए निर्णय लेने में योगदान देता है।

महामारी के दौरान, एनआईडीएम ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, वेबिनार, ऑनलाइन कार्यशालाएं/सम्मेलन/सेमिनार आदि के माध्यम से प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और टीओटी कार्यक्रमों की श्रृंखला को लगातार मुहैया कराया और आयोजित किया। एनआईडीएम ने अब आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर और प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करके परिसर के अंदर और बाहर आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित किया है।

वार्षिक रिपोर्ट उन कार्यक्रमों और गतिविधियों की झलक प्रस्तुत करती है जिन्हें एनआईडीएम ने प्रारंभ किया और जिन कामों को संस्थान द्वारा नई अंतर्दृष्टि के साथ बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया, और समाज के विभिन्न वर्गों तक ले जाने का प्रयास किया गया। हमारा दृष्टिकोण आपदा की रोकथाम और तैयारियों के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करके एक आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है। मैं इस प्रयास में गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी विभागों एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दिए गए सहयोग एवं समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं।

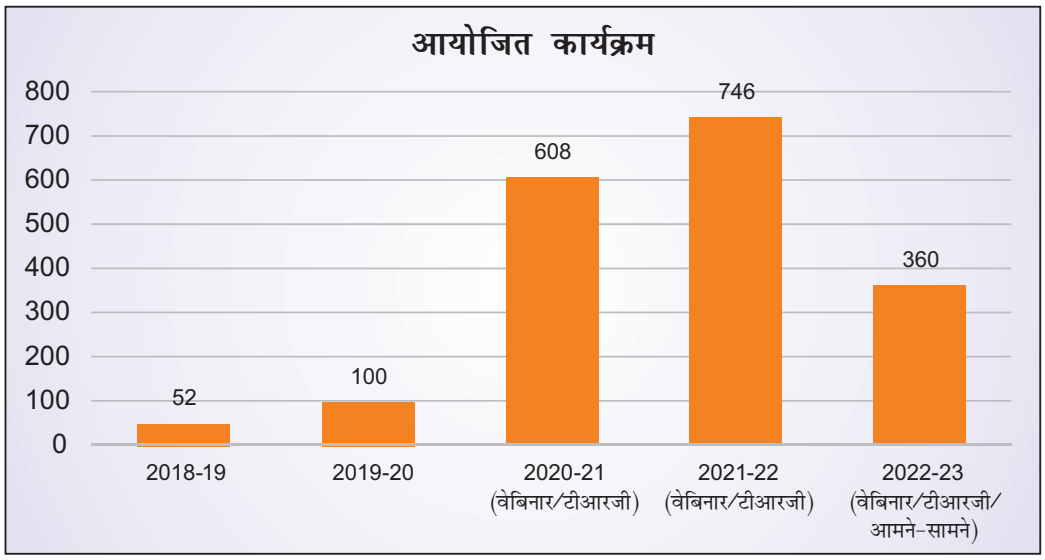
एनआईडीएम प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से एक आपदा प्रतिरोधी समुदाय के निर्माण के संयुक्त प्रयास में योगदान देना जारी रखेगा ताकि व्यक्ति अकेले या सामूहिक रूप से आपदा के लिए तैयार हो सकें।

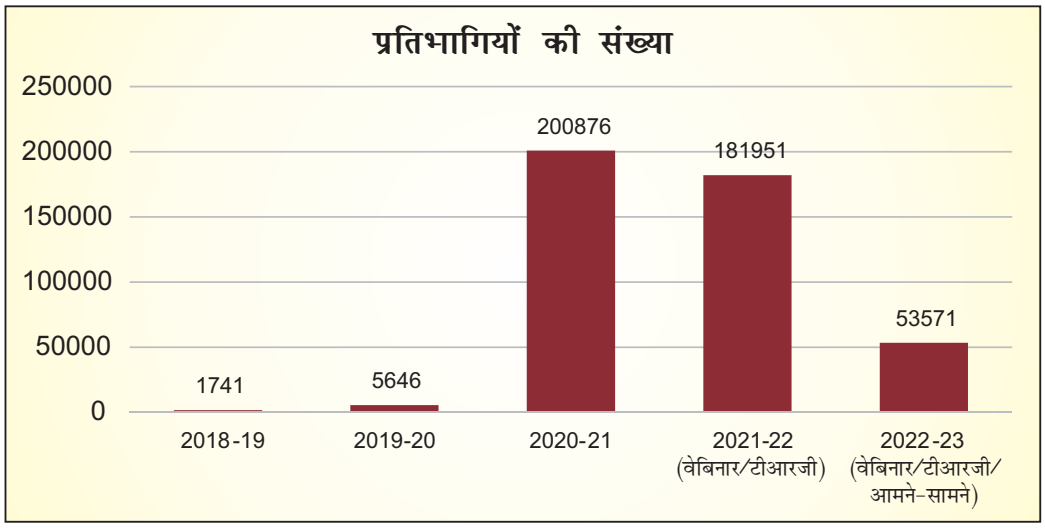


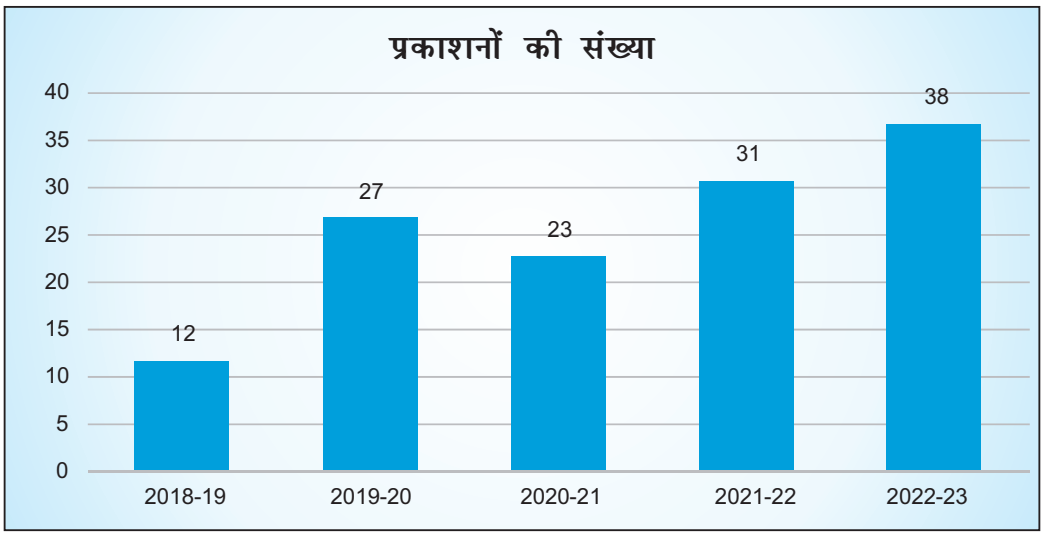
(राजेन्द्र रत्नू)

गतिविधियों की समीक्षा

इस साल, 154 वेबिनार आयोजित किए गए और उनमें 24154 प्रतिभागी शामिल हुए। इसके बाद, 80 तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिनमें 21717 प्रतिभागी शामिल हुए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आयोजित वेबिनारों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समग्र वृद्धि हुई। 126 आमने-सामने कार्यक्रम और 19 वर्कशॉप आयोजित किए गए, जिनमें 7700 प्रतिभागी शामिल थे। 2022-23 में, 31 राज्यों/संघों को कवर किया गया। 2022-23 में एनआईडीएम द्वारा कुल मिलाकर 38 प्रकाशन प्रकाशित किए गए। एनआईडीएम द्वारा पिछले कुछ सालों में विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी वृद्धि का संक्षिप्त ब्योरा ग्राफिक्स के माध्यम से नीचे दर्शाई गई है।






प्रकाशनों की संख्या
40
35
30
25
20
15
10
5
0
12
27
23
31
38
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
2022-23

अध्याय 1

सिंहावलोकन

सिंहावलोकन

1.1 संस्थान के बारे में

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन 30.10.2006[1] को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को आपदा प्रबंधन नीतियों, निवारक तंत्र और शमन उपायों[2] के संबंध में आपदा प्रबंधन प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करने के क्षेत्र में योजना बनाने और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र से 16 अक्टूबर, 2003 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में पुनः अधिकारिक नामकरण के बाद से एनआईडीएम सभी स्तरों पर आपदा नियंत्रण और इसके लिए तैयार रहने की संस्कृति का विकास करके तथा इसे बढ़ावा देकर एक आपदा जागरुक भारत तैयार करने के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है।

1.2 प्रबंधन संरचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नियम, 2006 के अनुसार, संस्थान के 2 निकाय हैं, नामतः, संस्थान और शासी निकाय। संस्थान में 42 सदस्य होते हैं, जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों के सचिव, मौजूदा राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान एवं तकनीकी संगठनों के अध्यक्ष साथ ही प्रमुख वैज्ञानिक एवं डीआरआर विशेषज्ञ शामिल हैं। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री संस्थान के अध्यक्ष हैं। एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य करता रहा है।

संस्थान की शासी परिषद् में 15 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और गृह सचिव उपाध्यक्ष[3] हैं। संस्थान के दैनिक प्रशासन का संचालन कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है।

संस्थान के निम्नलिखित शैक्षणिक विभाग हैं:-

- सुशासन एवं समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)
- आपदा प्रतिक्रिया एवं रिकवरी प्रभाग (डीआरआरडी)
- भौगोलिक-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)

---

[1]एनआईडीएम का गठन 30.10.2006 से एस.ओ. 1862(ई) द्वारा किया गया है।
[2]आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 42(8)
[3]एनआईडीएम नियम, 2006 की धारा 6

- आपदा समुत्थानशील संरचना प्रभाग (आरआईडी)
- सीबीआरएन और साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)
- पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईसीडीआरएम)

इसके अलावा, संस्थान के 21 केंद्र और 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं।

1.3 मिशन

- नीति निर्माण में सहायता देकर सरकार के लिए एक विचारक मंडल के रूप में कार्य करना;
- निम्नलिखित द्वारा आपदाओं के दुष्परिणामों और प्रभावों को कम करने में सहायता देना;
  - o प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेवाओं की योजना बनाना एवं उन्हें बढ़ावा देना;
  - o अनुसंधान, प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करना;
  - o आपदा के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करने और राहत के लिए पद्धति विकास और सुविज्ञता को प्रोत्साहित करना;
  - o जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी हितधारकों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना;
  - o सभी संबंधितों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सांस्थानिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण;
  - o नेटवर्किंग और सूचना, अनुभव और सुविज्ञता के आदान-प्रदान को सुगम बनाना[4]।

1.4 कार्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थान को निम्न कार्य[5] सौंपे गए हैं:-

- आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, अनुसंधान और प्रलेखन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना का निर्माण और कार्यान्वयन;
- राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करने में सहायता प्रदान करना;
- विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रदान करना;
- राज्य स्तरीय नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे के निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सहायता के रूप में राज्य सरकार और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करना;
- शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षणिक सामग्रियों का विकास;
- कॉलेज या स्कूल के शिक्षकों और छात्रों, तकनीकी कर्मियों और बहु-जोखिम न्यूनीकरण, तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों से जुड़े अन्य लोगों सहित हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना;
- उपरोक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए देश के भीतर और बाहर अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, व्याख्यानों, सेमिनारों को आयोजित करना और सुगम बनाना;

---

[4]प्रबंधन समिति की पहली बैठक की कार्यसूची

[5]आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 42(9)

- पत्रिकाओं, शोध पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान करना और पुस्तकालयों की स्थापना और रख-रखाव आदि;
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक तथा प्रासंगिक अन्य सभी विधि सम्मत कार्य करना;
- केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का निष्पादन;

1.5 प्रमुख क्षेत्र

1.5.1 प्रशिक्षण

i. **आमने-सामने प्रशिक्षण:** एनआईडीएम सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापक विषयों और क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न विषयों पर परिसर में और परिसर के बाहर दोनों जगह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

ii. **वेब आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण:** यह संस्थान आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विशेष विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। उपयोगकर्ता रजिस्टर करके ऑनलाइन अध्ययन पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं।

iii. **स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम:** संस्थान ने वेब आधारित स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जिसके लिए, कोई भी, किसी भी समय लॉग-ऑन कर सकता है और इन पाठ्यक्रमों के अध्ययन से सीख सकता है।

iv. **कार्यशाला, सेमिनार, परामर्श:** संस्थान आपदा प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन, कान्फ्रेंस का आयोजन करता है।

1.5.2 अनुसंधान और प्रलेखीकरण

एनआईडीएम देश में होने वाली बड़ी आपदाओं का प्रलेखीकरण करता है ताकि इसके प्रबंधन से सबक लिया जा सके और इन मामलों के अध्ययन का प्रयोग प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए संसाधन सामग्री और अनुकरण अभ्यास के लिए किया जा सके।

1.5.3 नीति अध्ययन और सहायता

ज्ञान और अनुसंधान संस्थान होने के नाते एनआईडीएम गृह मंत्रालय, एनडीएमए और अन्य हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर के दिशा-निर्देश, नीतियां और योजनाएं आदि तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। एनआईडीएम राज्य स्तर की नीतियां, रणनीतियां, आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार करने में राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों तथा हितधारकों के क्षमता निर्माण और उनके (राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों) द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता भी प्रदान करता है।

1.5.4 ज्ञान एकीकरण

एनआईडीएम नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, शोध, प्रलेखीकरण आदि के लिए कार्यक्रम आधारित गतिविधियों पर कई राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ संस्थानों के साथ सहयोग द्वारा ज्ञान एकीकरण करता है।

*****

अध्याय 2

संगठनात्मक व्यवस्था

संगठनात्मक व्यवस्था

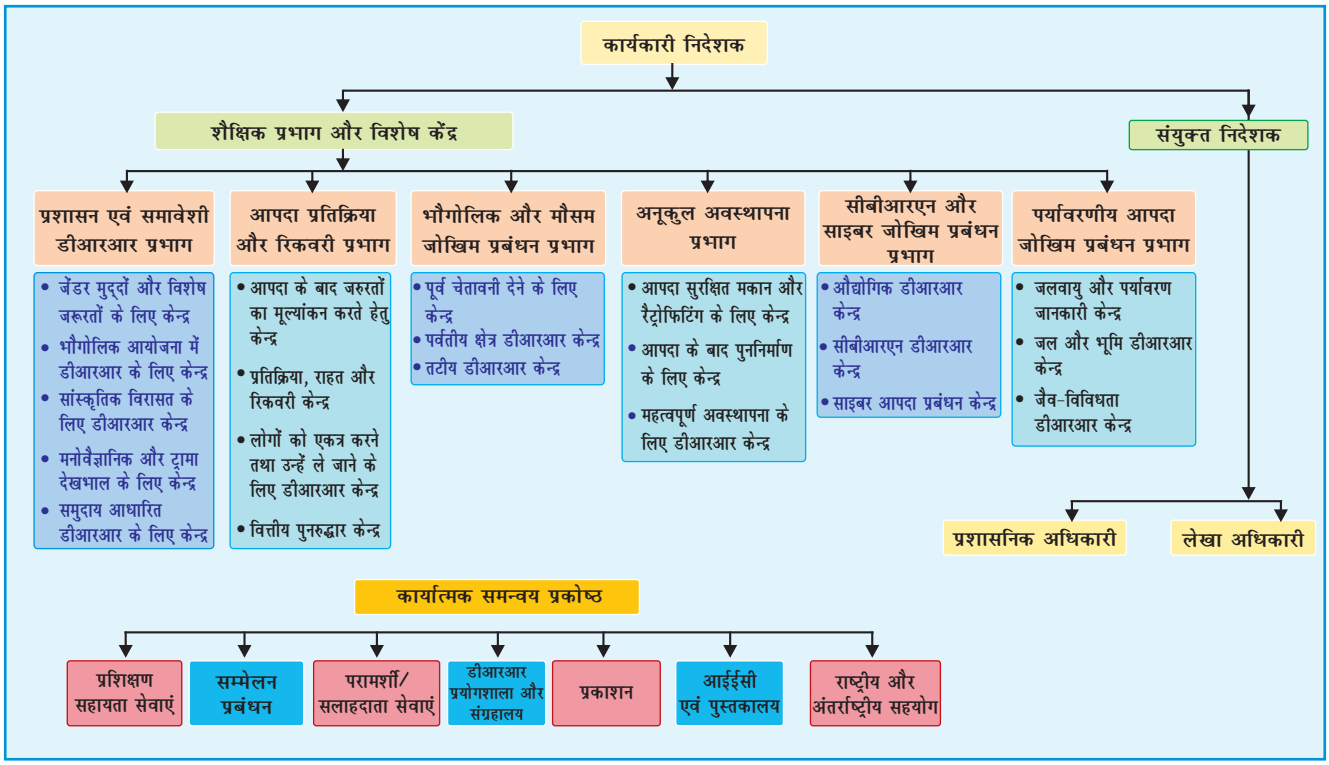
केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, और कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य सचिव हैं। संस्थान में 42 सदस्य हैं, जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों के अध्यक्षों के अलावा प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और व्यवसायी शामिल हैं, **(अनुलग्नक–I: संस्थान के सदस्यों की सूची)**

संस्थान की एक शासी परिषद् है जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और केंद्रीय गृह सचिव संस्थान के शासी परिषद् के उपाध्यक्ष हैं।

(अनुलग्नक–II: संस्थान के शासी परिषद् के सदस्यों की सूची)

संस्थान के छः प्रभाग और 21 विशेष केंद्र हैं जिनकी सहायता के लिए 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं। (चित्र 2.1)

2.1. संगठनात्मक ढांचा



चित्र 2.1 एनआईडीएम की नियोजित शैक्षणिक और कार्यात्मक संरचना

तालिका 2.1: एनआईडीएम के कार्यकारी अधिकारी

क) कार्यकारी निदेशक

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री, राजेन्द्र रत्नू, आईएएस	कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम (10.02.2023 से आज तक)
2.	श्री ताज हसन, आईपीएस	कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम (अतिरिक्त प्रभार) (30.01.2022 से 10.02.2023)

ख) संयुक्त निदेशक

क्र.सं.	नाम	अवधि
3.	श्री सुरेन्द्र ठाकुर	संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम, दिल्ली (08.12.2022 से आज तक)
4.	श्री पी. एस. रेड्डी	संयुक्त निदेशक (दक्षिणी परिसर) (24.02.2023 से शुभारंभ)

ग) परामर्शदाता

क्र.सं.	नाम	अवधि
5.	श्री सुरेन्द्र ठाकुर	परामर्शदाता (मानव संसाधन / प्रशासन) (11.09.2019 से 07.10.2021 तक) परामर्शदाता एवं संयुक्त निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) (08.10.2021 से 07.12.2022 तक)

तालिका 2.2: प्रभागवार एनआईडीएम की संकाय सूची

1. सुशासन और समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)		
डॉ. संतोष कुमार		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	लैंगिक मुद्दों और विशेष आवश्यकताओं के लिए केंद्र (जीआईएन)	डॉ. अजिन्दर वालिया, एसोसिएट प्रोफेसर (05.05.2022 से प्रभावी)
ii.	भौगोलिक आयोजना में डीआरआर के लिए केंद्र (जीपीएल)	---
iii.	सांस्कृतिक विरासत केंद्र (सीएचआर)	---
iv.	मनोवैज्ञानिक तथा ट्रॉमा देखरेख केंद्र (पीटीसी)	डॉ. अजिन्दर वालिया, एसोसिएट प्रोफेसर (05.05.2022 से प्रभावी)
v.	समुदाय आधारित डीआरआर केंद्र (सीबीडीआरआर)	

2. आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रभाग (डीआरआरडी)		
डॉ. संतोष कुमार		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन केंद्र (पीडीएनए)	डॉ. संतोष कुमार, प्रोफेसर एवं प्रमुख
ii.	प्रतिक्रिया, राहत एवं रिकवरी केंद्र (आरआरआर)	श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर
iii.	जन एकत्रीकरण और परिवहन डीआरआर केन्द्र (एमसीटी)	श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर
iv.	वित्तीय पुनरुद्धार केंद्र (एफआर)	
3. भू-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)		
डॉ. सूर्य प्रकाश		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	पूर्व चेतावनी संचार केंद्र (ईडब्लयूसी)	---
ii.	पर्वतीय क्षेत्र डीआरआर केंद्र (एचएडीआरआर)	---
iii.	तटीय डीआरआर केंद्र (सीडीआरआर)	---
4. समुत्थानशील अवसंरचना प्रभाग (आरआईडी)		
डॉ. चंदन घोष		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	आपदा सुरक्षित मकान और रेट्रोफिटिंग केंद्र (डीएसएचआर)	---
ii.	आपदा पश्चात् पुनर्निर्माण केंद्र (पीडीआर)	---
iii.	महत्वपूर्ण अवसंरचना डीआरआर केंद्र (सीआईडी)	डॉ. आमिर अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर (05.05.2022 से प्रभावी)
5. सीबीआरएन एवं साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)		
डॉ. सूर्य प्रकाश (09.07.2021 से आज तक)		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	औद्योगिक डीआरआर केंद्र (आईएनडी)	---

5. सीबीआरएन एवं साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआईसीआरएमडी)		
ii.	सीबीआरएन डीआरआर केंद्र (सीबीआरएन)	---
iii.	साइबर आपदा प्रबंधन केंद्र (सीवाईडी)	---
6. पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईआरएमडी)		
डॉ. अनिल गुप्ता		प्रोफेसर एवं प्रमुख
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण केंद्र (सीआरई)	डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर
ii.	जल एवं भूमि डीआरआर केंद्र (डब्ल्यूएलडी)	डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर
iii.	वन एवं जैव-विविधता डीआरआर केंद्र (एफबीडी)	---
7. कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ		
i.	प्रशिक्षण सहायता सेवाएँ (टीसीएस)	i. सुश्री ऋतु सूद, प्रशासनिक अधिकारी
ii.	सम्मेलन प्रबंधन (सीएफएम)	
iii.	परामर्शी/सलाहकार सेवाएँ (सीएएस)	i. डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, प्रोफेसर एवं प्रमुख ii. श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर iii. सुश्री ऋतु सूद, प्रशासनिक अधिकारी
iv.	डीआरआर प्रयोगशाला एवं संग्रहालय (डीएलएम)	i. डॉ. चन्दन घोष, प्रोफेसर ii. डॉ. आमिर अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर iii. सुश्री ऋतु सूद, प्रशासनिक अधिकारी
v.	प्रकाशन (पीयूबी)	i. श्री संतोष कुमार तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष
vi.	आईईसी एवं पुस्तकालय (आईईएल)	i. श्री संतोष कुमार तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष ii. सुश्री जया, पुस्तकालय परिचारिका
vii.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एनआईसी)	i. संतोष कुमार प्रोफेसर एवं प्रमुख ii. डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, प्रोफेसर एवं प्रमुख iii. डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर

2.2 सामान्य प्रशासन

संस्थान के कार्यकारी निदेशक संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और शासी निकाय के निर्देश और मार्गदर्शन के अधीन कार्य करते हैं। कार्यकारी निदेशक की सहायता के लिए संयुक्त निदेशक, लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं। संस्थान के प्रशासन में मुख्यतया समन्वय, सांविधिक बैठकों का आयोजन, स्थापना और कार्मिक प्रबंधन, सुरक्षा, परिसर सहायता सेवाएं और कर्मचारियों का कल्याण शामिल है। यह कार्यक्रमों के अबाध आयोजन के लिए आवश्यक अवस्थापना और प्रबंधकीय

सहायता प्रदान करके संस्थान के शोध, प्रशिक्षण और परामर्शी कार्यों में मदद करता है। एनआईडीएम के कर्मचारियों की सूची **तालिका 2.3** में दी गई है।

तालिका 2.3: एनआईडीएम के कर्मचारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	सुश्री ऋतु सूद	प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री एस.एस. बिष्ट	लेखा अधिकारी
3.	श्री हेमंत कुमार	कंप्यूटर प्रोग्रामर
4.	श्री संतोष कुमार तिवारी	पुस्तकालयाध्यक्ष
5.	श्री अविनाश कुमार पाण्डेय	निजी सचिव
6.	श्री जे.एन. झा	कनिष्ठ अभियन्ता
7.	सुश्री अमृता गुप्ता	वैयक्तिक सहायक
8.	सुश्री संतोष मिश्रा	प्रशिक्षण सहायक
9.	सुश्री गीता शर्मा	प्रशिक्षण सहायक
10.	श्री राजीव कुमार	प्रशिक्षण सहायक
11.	श्री अमर सिंह	मशीन ऑपरेटर
12.	सुश्री जया	पुस्तकालय परिचारिका
13.	श्री लक्ष्मण सिंह	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
14.	श्री पंकज कुमार	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)

2.3 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

एनआईडीएम का हिन्दी प्रकोष्ठ कार्यालय के दैनिक कार्यों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए पूर्णतया सक्रिय है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में चार हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 129 अधिकारियों और कर्मचारियों ने आधिकारिक कामकाज की अनिवार्यताओं के अनुसार भाग लिया। एनआईडीएम की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित रूप से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को भेजी जाती है।

कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है, जो कार्यालय में राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए त्रैमासिक बैठक करती है। चालू वर्ष के दौरान इस कमिटी की चार बैठकें हो चुकी हैं।

सलाहकार (राजभाषा) ने सूरत गुजरात में आयोजित 'हिन्दी दिवस समारोह' और दूसरे 'अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन' में एनआईडीएम का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों के अनुरूप, एनआईडीएम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय में एक हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा भेजी गई निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसरण में कार्यालय में 14-29 सितंबर, 2022 तक 'हिन्दी पखवाड़ा' आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यालय में ''निबंध लेखन प्रतियोगिता'' एवं ''स्व-रचित कविता पाठ प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया, जिसमें 27 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित

किया गया। राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुपालन के लिए कार्यालय में राजभाषा नियमों/अधिनियमों के कार्यान्वयन हेतु चेक प्वाइंट बनाए गए हैं।

गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप, वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, हिन्दी प्रकोष्ठ इस अवधि के दौरान आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों, भाषणों, आधिकारिक वेबसाइट के महत्वपूर्ण अध्यायों, त्रैमासिक समाचार पत्र टाइडिंग्स, आईडीआरएन पुस्तिकाओं, प्रशिक्षण मॉड्यूल, आपदा प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर पुस्तकों और दैनिक सामान्य आधिकारिक कार्य की मदों के अनुवाद में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है।











*****

अध्याय 3

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपदा प्रबंधन में संलग्न पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पर जोर देना संस्थान के प्रमुख प्रयासों में से एक रहा है। इस प्रयास के रूप में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में विभिन्न क्षमता निर्माण मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की विधि के आधार पर कार्यक्रम को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

i. आमने-सामने प्रशिक्षण

ii. वेबिनार/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

iii. स्व-अध्ययन

iv. विमर्श/कार्यशालाएं

एनआईडीएम, कार्यक्रमों के संचालन की निरंतरता बनाए रखने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन के लिए, अपने कार्यकरण में ऑनलाइन मोड में कार्यक्रमों के संचालन की पद्धति को जोड़ा है। इन कार्यक्रमों को वेबिनार और ई-प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा गया है। संस्थान ने नवंबर 2021 से वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ अपने आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फिर से आरंभ कर दिया है।

एनआईडीएम आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, एनआईडीएम सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज से जुड़े संगठनों (आपदा प्रबंधन पेशेवरों), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शिक्षाविदों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों (सरकारी विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय स्वंय सेवी संगठनों) को प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

3.1 उद्देश्य

नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को मुख्य धारा में लाने के लिए कौशल प्रदान करना, एनआईडीएम का प्राथमिक उद्देश्य है। आपदा प्रबंधन कर्मियों और अन्य पेशेवरों, जो आपदा और विकास गतिविधियों में लगे हुए हैं, को केंद्रीकृत और उपयुक्त प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए, एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किए गए हैं:

- प्रभावी कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जागरुकता पैदा करना, कौशल में सुधार करना और विकास प्राधिकारियों के ज्ञान को समृद्ध करना;
- सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उभरती जरूरतों के प्रति केंद्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील बनाना;
- परिचय दौरों, मामलों के अध्ययन और विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से विकास कर्मियों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना ।

3.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने की विधि, लक्षित समूह एवं विषय-वस्तु के आधार पर वर्गीकृत की गई है।

3.2.1 वेबिनार/ऑनलाइन प्रशिक्षण/आमने-सामने कार्यक्रम

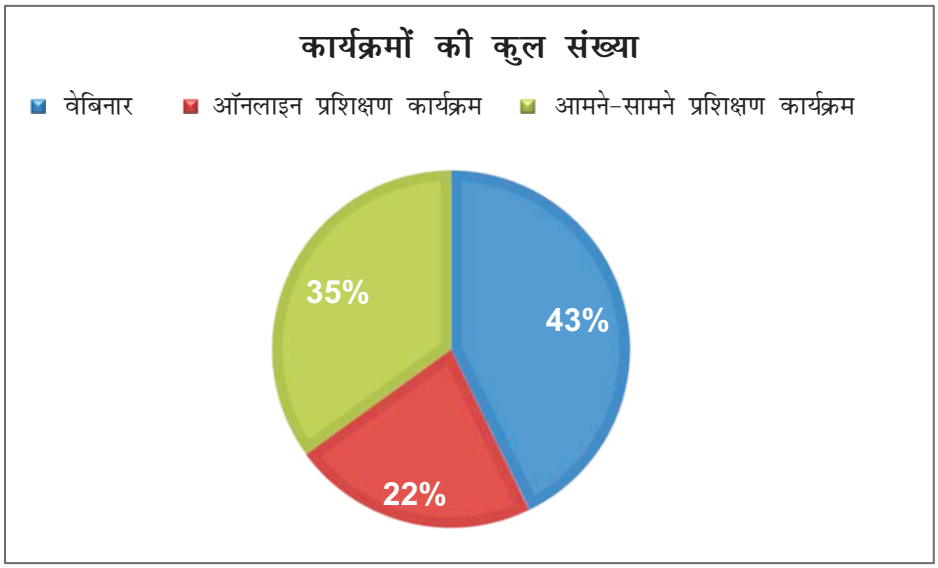
संस्थान अपने परिसर अथवा राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) / राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में आमने-सामने प्रशिक्षण पद्धति के माध्यम से व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन के लगभग सभी पहलुओं को शैक्षणिक प्रभागों के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कवर किया जाता है।

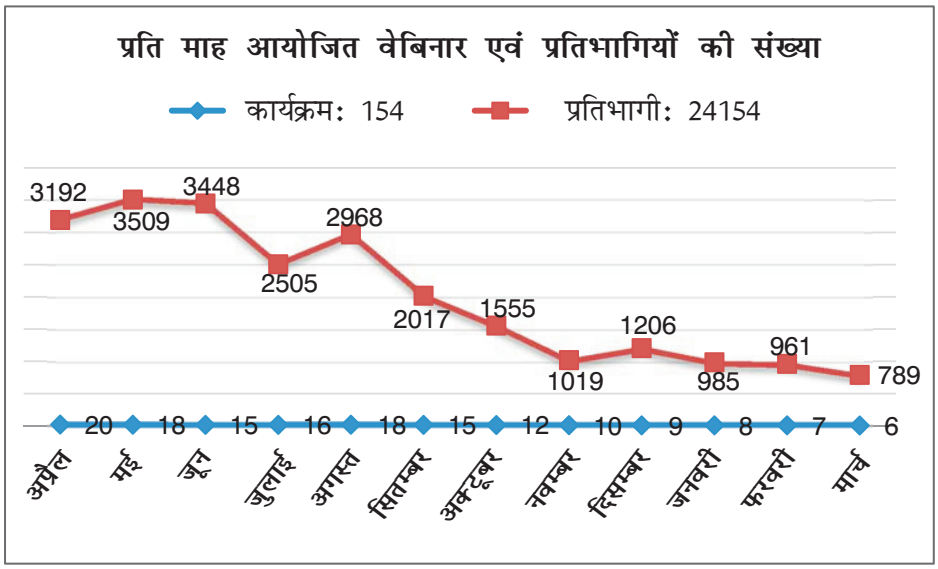
भारत सरकार निर्धारित कोविड-19 संबंधी नवाचारों का अनुपालन करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन के उद्देश्य से एनआईडीएम ने वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और नवंबर 2021 से आमने-सामने कार्यक्रमों को भी फिर से शुरू किया।

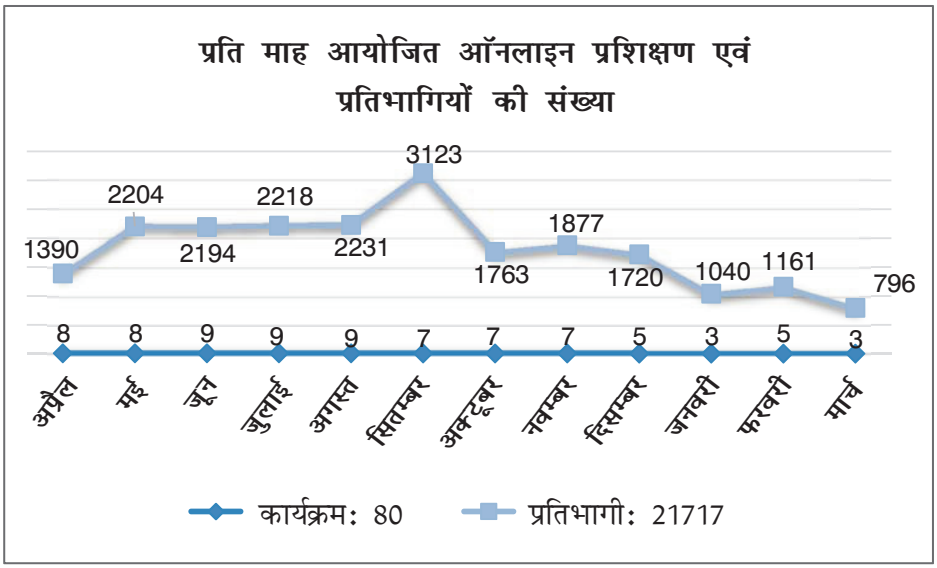
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 154 वेबिनार आयोजित किए गए और जिनमें 24154 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 21717 प्रतिभागियों के लिए 80 तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 126 आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 7700 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए आयोजित वेबिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समग्र रूप से वृद्धि हुई।

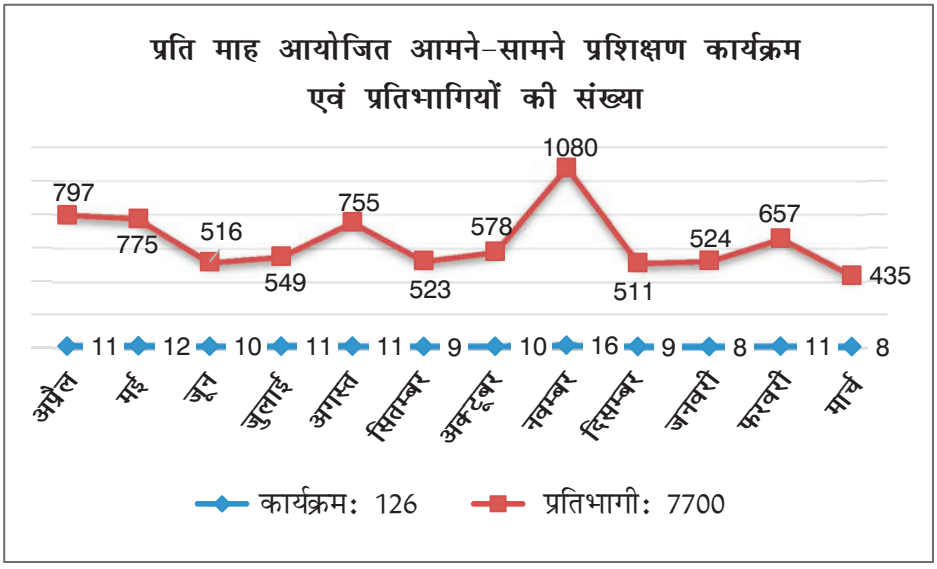
तालिका 3.1: वर्ष 2022-23 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

वेबिनार		ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम		आमने-सामने कार्यक्रम	
कुल वेबिनार की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या	कुल ऑनलाइन कार्यक्रम	कुल प्रतिभागियों की संख्या	कुल कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या
154	24154	80	21717	126	7700




प्रति माह आयोजित वेबिनार एवं प्रतिभागियों की संख्या
कार्यक्रम: 154
प्रतिभागी: 24154
3192
3509
3448
2505
2968
2017
1555
1019
1206
985
961
789
20
18
15
16
18
15
12
10
9
8
7
6
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
जनवरी
फरवरी
मार्च


प्रति माह आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं
प्रतिभागियों की संख्या
1390
2204
2194
2218
2231
3123
1763
1877
1720
1040
1161
796
8
8
9
9
9
7
7
7
5
3
5
3
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
जनवरी
फरवरी
मार्च
कार्यक्रम: 80
प्रतिभागी: 21717


प्रति माह आयोजित आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम
एवं प्रतिभागियों की संख्या
797
775
516
549
755
523
578
1080
511
524
657
435
11
12
10
11
11
9
10
16
9
8
11
8
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
जनवरी
फरवरी
मार्च
कार्यक्रम: 126
प्रतिभागी: 7700

3.3 प्रशिक्षण विधि

उपलब्ध कराये जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और साथ ही कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण विधियों में शामिल हैं:

- व्याख्यान सह-विचार-विमर्श
- केस अध्ययन प्रस्तुतियाँ
- कार्य का अभ्यास
- सामूहिक वाद-विवाद/अभ्यास
- पैनल चर्चा
- अनुकरण एवं भूमिका निर्वहन
- टेबल टॉप अभ्यास

3.4 प्रतिभागियों का विवरण

चूंकि एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन में लगे विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को शामिल किया गया है अत: प्रशिक्षुओं की प्रोफाइल को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है;

- सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारी);
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू);

  शिक्षाविद् (शोधकर्ता, वैज्ञानिक, स्कूल शिक्षक एवं विश्वविद्यालय संकाय);
- ज्ञान भागीदार संस्थान;
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार (सरकारी विभाग, यूएन एजेंसियां, आईएनजीओ);
- अवसंरचना व्यवसायिक (इंजीनियर, वास्तुकार, निर्माण एजेंसियां आदि);
- नागरिक समाज संगठन (आपदा प्रबंधन व्यववसायिक)

3.5 ई-लर्निंग

3.5.1 ऑनलाइन पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्रों में हितधारकों के बीच विश्लेषणात्मक कौशल और पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के साथ सभी स्तरों पर जागरुकता और तैयारी के स्तर को बढ़ाना है। एनआईडीएम का ऑनलाइन कार्यक्रम एक अद्वितीय क्षमता निर्माण का उपाय है, जो मूडल (MOODLE) आधारित वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रतिभागियों को एक सामान्य चर्चा मंच पर अपने मत, विचार एवं सूचनाओं विश्व स्तर पर साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम प्रख्यात विषय विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन बातचीत करने और पेशेवरों के मार्गदर्शन में पाठ्यक्रम विषयों के विभिन्न पहलुओं को सीखने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। संबंधित पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के ज्ञान स्तर को 'पाठ्यक्रम असाइनमेंट के मूल्यांकन' और 'पाठ्यक्रम परियोजना के समापन' जैसे निर्धारित मापदंडों के माध्यम से मापा जाता है, जिसके

बाद उन्हें सफल घोषित किया जाता है और एनआईडीएम द्वारा जारी ''पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाणपत्र'' से सम्मानित किया जाता है।

कुल मिलाकर, एक समर्पित पोर्टल https://elearning.nidm.gov.in के माध्यम से 10 ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें से ''व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचा'' ''बुनियादी पाठ्यक्रम'' है जो आपदा की मूलभूत अवधारणाओं और अनुप्रयोगों पर जानकारी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 9 ''विषयगत पाठ्यक्रम'' भी उन प्रतिभागियों को उपलबध कराए जाते हैं जो मूल पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं–

I. समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (सीबीडीआरएम);

II. भूकंप जोखिम न्यूनीकरण (ईआरआर);

III. जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम (सीसीडीआर);

IV. क्षति और पुनर्निर्माण की आवश्यकता का आकलन (डीआरएनए);

V. आपदा रिकवरी और पुनर्निर्माण के लैंगिक पहलू (डीएडीआरआर);

VI. जोखिम संवेदनशील भूमि उपयोग योजना (आरएसएलयूपी);

VII. जोखिम पहचान, आकलन और विश्लेषण (आरए);

VIII. सुरक्षित शहर (एससी); तथा

IX. आपदाओं के आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्तीय रणनीतियाँ (एफए)

व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (बेसिक) पाठ्यक्रम की अवधि छह सप्ताह (1.5 महीने) है, और विषयगत पाठ्यक्रमों के लिए, यह चार सप्ताह (एक महीना) है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम पोर्टल पर 12.03.2023 तक विजिटर्स की संख्या 1,03,417 है। पाठ्यक्रम सामग्री पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए उनके संबंधित पाठ्यक्रम प्लेटफार्म पर आसानी से उपलब्ध हैं, जिसे ऑफलाइन संदर्भ के लिए भी डाउनलोड किया जा सकता है।

शैक्षणिक वर्ष 2022–23 में, नीचे दी गई तालिका में बताए अनुसार कुल 18 ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 353 प्रतिभागियों ने अपने संबंधित पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

क्रमांक	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम संख्या
1.	व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचा	4
2.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	1
3.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण	1
4.	जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम प्रबंधन	1
5.	क्षति और पुनर्निर्माण की आवश्यकता का आकलन	2
6.	आपदा रिकवरी और पुनर्निर्माण के लैंगिक पहलू	2
7.	जोखिम संवेदनशील भूमि उपयोग योजना	2
8.	जोखिम पहचान, आकलन और विश्लेषण	2

क्रमांक	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम संख्या
9.	सुरक्षित शहर	1
10.	आपदाओं के आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्तीय रणनीतियाँ	2
	कुल	**18**

कोविड काल के पश्चात, एनआईडीएम आपदा संबंधी ज्ञान प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को और विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

3.5.2 स्व अध्ययन कार्यक्रम

एनआईडीएम का स्व-अध्ययन कार्यक्रम (एसएसपी) ई-लर्निंग की एक स्व-गतिशील प्रणाली है जिसमें सभी संबंधित हितधारकों को बिना किसी समय और स्थान की सीमा के आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को अपनी गति से सीखने के लिए प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान की जाती है। उपयोगकर्ता बिना किसी मानवीय सहायता के प्रस्तावित विषयों पर स्वत: ज्ञान प्राप्त करने के लिए पोर्टल https://ssp.nidm.gov.in/में लॉग इन कर सकते हैं। एनआईडीएम का स्व-अध्ययन कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों के ज्ञान को बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ है।स्व-अध्ययन कार्यक्रम में 24.01.2022 से 31.03.2023 तक आगंतुकों की संख्या 2048 रही है।

एनआईडीएम द्वारा स्व-अध्ययन पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित 10 स्व अध्ययन मॉड्यूल पेश किए जा रहे हैं:

क्रमांक सं.	स्व अध्ययन मॉड्यूल
1.	आपदा प्रबंधन की मूल बातें
2.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन
3.	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए एक मार्गदर्शिका
4.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय
5.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय
6.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन का सामान्य अवलोकल
7.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन
8.	स्कूल सुरक्षा
9.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय
10.	औद्योगिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय

3.6 इंटर्नशिप कार्यक्रम

हर वर्ष, एनआईडीएम को शैक्षणिक/शोध/प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों/शोधकर्ताओं से, विशेषकर गर्मी के महीने में, इंटर्नशिप के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। इंटर्नशिप के उद्देश्य हैं:-

- संबंधित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर करने वाले इच्छुक व पात्र उम्मीदवारों को समग्र आपदा प्रबंधन प्रणाली और इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना ।
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के छात्रों को आपदा प्रबंधन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और शोध में व्यवहारिक अनुभव लेने में मदद करना।
- छात्रों को उनके कौशल के परीक्षण के लिए नवाचार और नए विचारों तथा तकनीकों को शामिल करने का पर्याप्त अवसर देना।
- औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, व्यवसायिक संस्थानों को एनआईडीएम और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी देना।
- एनआईडीएम में इंटर्नशिप के लिए एक नीति तैयार तथा अनुमोदित करके इस प्रक्रिया को औपचारिक बनाया गया है। इंटर्नशिप के लिए आवेदन खुले विज्ञापन के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके बाद बहु-स्तरीय चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पूरे देश से विभिन्न विषयों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों से इंटर्न शोध कार्य के लिए चुने जाते हैं।
- वर्ष 2022-23 में, 69 इंटर्न नियमित इंटर्नशिप (नॉन-पेड) के लिए आए और 6 इंटर्न को भुगतान के आधार पर ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए चुना गया।

*****

अध्याय 4

परियोजनाएं

परियोजनाएं

4.1 राष्ट्रीय पर्यावरण वन और जलवायु आपदा प्रबंधन योजना (एनईएफसी-डीएमपी)

एनआईडीएम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 के तहत वैधानिक अधिदेश का उपयोग करके पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण वन और जलवायु आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहयोग कर रहा है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

क) मंत्रालय और उसके विभागों/प्रतिष्ठानों के तहत बुनियादी ढांचे, परिसंपत्तियों, संपत्ति और संसाधनों की आपदाओं और चरम घटनाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करना,

ख) यह सुनिश्चित करना कि गतिविधियां (भौतिक विकास और व्यवस्थित प्रथाओं/संचालन सहित) आपदाओं से खतरों के जोखिम और कमजोरियों में वृद्धि न करें।

ग) यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय/क्षेत्र के तहत संचालित गतिविधियां/कार्यक्रम और योजना आपदाओं और चरम घटनाओं के जोखिम के प्रति समुत्थानशीलता संवर्धन करें, और

घ) यह सुनिश्चित करना कि मंत्रालय और संबद्ध क्षेत्र और घटक सभी स्तरों पर किसी भी आपदा या आपात स्थिति से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं।

परियोजना में शामिल गतिविधियाँ:

- आपदा जोखिम क्षमता की संवेदनशीलता का विश्लेषण पर कार्यशालाओं का आयोजन;
- क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन;
- कार्य समूह की बैठकों का आयोजन;
- साझाकरण/प्रसार कार्यशाला (आधा दिन);
- क्षमता निर्माण कार्यशाला (2 दिन); तथा
- प्रशिक्षण मैनुअल और विषयगत पेपर तैयार करना।

अब तक प्रदेय: 31/03/2023

- एनईएफसी-डीएमपी अंतिम रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंप दिया गया है।
- प्रशिक्षण मैनुअल एवं विषयगत पेपर तैयार किये गए।

वित्त पोषण एजेंसी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

4.2 आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (आयुष-डीएमपी)

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का आयुष-डीएमपी प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे एनआईडीएम अपने ईसीडीआरएम के माध्यम से लागू कर रहा है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य



यह परियोजना आयुष मंत्रालय की आपदा तैयारियों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, और एनआईडीएम इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

परियोजना की प्रदेयताएँ:

- आयुष मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना: यह योजना भारत में आयुर्वेद, योग और प्रोंतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों के लिए आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगी।
- आयुष-डीएमपी के प्रयोजन में मदद करने वाले प्रशिक्षण मैनुअल: प्रशिक्षण मैनुअल आपदा के स्थिति में आयुष-डीएमपी को कैसे लागू किया जाए, इस पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसमें भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल, और आपदा प्रबंधन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी शामिल होगी।
- आपदा तैयारियों के सुधार में आयुष मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका: यह प्रोजेक्ट आयुष मंत्रालय की आपदा तैयारियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संकट के समय इन चिकित्सा प्रणालियों पर आश्रित लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने में मदद करता है।

परियोजना के तहत 01.04.2022 और 31.03.2023 के बीच की गतिविधियाँ

- परियोजना के तहत 13 जुलाई 2022 को (कार्य समूह समिति) और एचआरवीसीए (आपदा जोखिम क्षमता की संवेदनशीलता का विश्लेषण) पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, आयुष मंत्रालय,भारत सरकार के लिए आपदा प्रबंधन योजना (आयुष-डीएमपी) की तैयारी पर चर्चा हुई।
- परियोजना टीम ने एक मसौदा डीएमपी तैयार किया है, जिसे मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

वित्त पोषण एजेंसी: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

4.3 आपदा और स्वास्थ्य केंद्र (सीडीएच), आपदा संबंधी स्वास्थ्य मुद्दों पर उत्कृष्ट केंद्र

आपदा एवं स्वास्थ्य केंद्र (सीडीएच) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) में स्थापित एक उत्कृष्टता केंद्र है जो आपदा से संबंधित मानव स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित है। इसने जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति भारत की तैयारियों और समुत्थानशीलता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सीडीएच ने सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्रियों की एक श्रृंखला भी विकसित की है जिसमें पोस्टर, वीडियो, जीआईएफ, और वे वीडियो शामिल हैं जो, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, अस्पताल के मजबूत बुनियादी ढांचेऔर आपदा तैयारी जैसे विषयों को कवर करते हैं।

प्रोजेक्ट की प्रस्तुतियाँ:

- सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री जिसमें आपदा जोखिम में कमी, अस्पताल के बुनियादी ढांचे की मजबूती और आपदा तैयारी जैसे प्रमुख आपदा-संबंधी मुद्दों पर पोस्टर, वीडियो, जीआईएफ और वीडियो शामिल हैं।





- विषयगत दस्तावेज जो इस बात पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि भारत में अस्पताल आपदाओं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी और प्रतिक्रिया कैसे कर सकते हैं। ये हैं - 'आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति अस्पताल के बुनियादी ढांचे की मजबूती', 'भारत में अस्पतालों के लिए आपदा जोखिम मूल्यांकन उपकरण को बढ़ावा देना' और 'आपदा जोखिम को कम करने के लिए अस्पतालों की प्रक्रियात्मक, संरचनात्मक, गैर-संरचनात्मक और कार्यात्मक तैयारियों के संबंध में निगरानी ढांचा''।

01/04/2022 से 31/03/2023 तक की प्रस्तुतियाँ:

- ''आपदाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव'' पर प्रशिक्षकों का विकास कार्यशाला 18 अक्टूबर, 2022 को आयोजित किया गया। भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य और जिलेके नोडल अधिकारियों को ध्यन में रखकर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- ''जलवायु संबंधी आपदाएं और स्वास्थ्य: भविष्यवादी दृष्टिकोण एवं आगे की रुपरेखा'' पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के साथ संयुक्त कार्यशाला का आयोजन 23 सितंबर, 2022 को आयोजित किया गया। यह कार्यशाला जलवायु परिवर्तन से संबंधी आपदाओं से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के समाधान के लिए रणनीति विकसित करने पर केंद्रित थी।

वित्त पोषण एजेंसी: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

4.4 राष्ट्रीय रसायन और पेट्रो रसायन आपदा प्रबंधन योजना (एनसीपीसी-डीएमपी)

रासायनिक और पेट्रोरसायन उद्योगों के तेजी से विकास के कारण हाल के वर्षों में रासायनिक और पेट्रोरसायन खतरों की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि हुई है।आपदाओं और मौसम की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए भारत के रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र की समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एनआईडीएम अपने ईसीडीआरएम के माध्यम से रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी), रसायन और उर्वरक मंत्रालय (एमसीएंडएफ), भारत सरकर के लिए 'राष्ट्रीय रसायन और पेट्रोरसायन आपदा प्रबंधन योजना (एनसीपीसी-डीएमपी) की तैयारी में सहायता कर रहा है।'

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

अ) आपदाओं और चरम घटनाओं से विभागों/प्रतिष्ठानों के तहत बुनियादी ढांचे, परिसंपत्तियों, संपत्ति और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना,

ब) यह सुनिश्चित करना कि गतिविधियाँ (भौतिक विकास और व्यवस्थित प्रथाओं/संचालन सहित) आपदाओं के जोखिमों और कमजोरियों को न बढ़ाएँ,

स) ऐसा सुनिश्चित करना कि गतिविधियाँ/कार्यक्रम और योजनाएं आपदा और व्यापक विनाश के खतरे के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दें, और

द) ऐसा सुनिश्चित करना कि विभाग और संबंधित क्षेत्र और तत्व सभी स्तरों पर किसी भी आपदा या आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हों।

अद्यतन गतिविधियाँ: 31/03/2023

- 12 अप्रैल 2022 को आपदा प्रबंधन योजना के अंतिम मसौदे पर सचिव, डीसीपीसी के साथ चर्चा ।
- ''राष्ट्रीय विकास क्षेत्र के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति: भारत में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स के लिए दृष्टिकोण और रुपरेखा'' शीर्षक से विषयगत पेपर तैयार किया गया है ।
- ''रसायन और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आपदा, जोखिम और प्रतिरोध'' पर प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया गया है ।



डीसीपीसी, नई दिल्ली में आयोजित चर्चा बैठक की झलकियाँ



एनडीएमए के समक्ष एनसीपीसी-डीएमपी के अंतिम मसौदे पर प्रस्तुति (वर्चुअल मोड के माध्यम से)

वित्तीय एजेंसी: रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग (डीसीपीसी), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार।

4.5 बहु-जोखिम पर्यावरण में समुत्थानशीलता और सतत् विकास के लिए जलवायु अनुकूल योजना (सीएपी-आरईएस)

इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से भारतीय हिमालय क्षेत्र (उत्तर-पूर्व का विशेष संदर्भ), तटीय क्षेत्र और मध्य-पश्चिमी क्षेत्रों में संबंधित संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा व्यापक उपयोग के लिए ज्ञान और प्रशिक्षण सहायता प्रणाली सहित क्षमता निर्माण को विकसित करना और कार्यान्वित करना है। परियोजना के 5 प्रमुख विषय हैं: (ए) हरित विकास और आपदा जोखिम में कमी; (बी) समुत्थानशील कृषि; (सी) समुत्थानशील स्वास्थ्य; (डी) आपदा राहत और रिकवरी के दौरान जलवायु रोधन; और (ई) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पर्यावरण नीति।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

- आपदा समुत्थानशीलता के लिए चरम घटनाओं और जलवायु जोखिम प्रबंधन के संबंध में वैज्ञानिक नीति-नियोजन-अभ्यास इंटरफेस का विश्लेषण करना।
- ज्ञान एवं क्षमता अंतराल का आकलन करना

- ज्ञान संग्रह के रूप में केस स्टडीज और सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और संकलन करना
- कमियों और चुनौतियों को दूर करने के लिएय आपदा जोखिम प्रबंधन को जलवायु क्रियाकलापों के साथ या इसके विपरीत, ज्ञान साझा करने वाले मंचों, नीति संक्षेपों, पत्रिकाओं एवं लेखों के माध्यम से नीतियों का विश्लेषण एवं प्रयोग का समर्थन और प्रचार करना
- क्षमता अंतराल विश्लेषण और ज्ञान आधारित संग्रह के परिणाम का उपयोग करके प्रशिक्षण रणनीति और डिजाइन, प्रशिक्षण मॉड्यूल, निर्देश मैनुअल, संदर्भ पठन सहित प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के लिए टूलकिट विकसित करना, और
- महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जैसे नीति निर्माताओं, प्रशिक्षकों और शोधकर्ताओं की ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण की क्षमता को विशेष तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ाना।

31/03/2023 तक की प्रस्तुतियाँ:

- **प्रकाशित तकनीकी रिपोर्ट**

(i) कॉर्पोरेट कार्बन प्रबंधन और ईएसजी रिपोर्टिंग: प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा हरित विकास और जलवायु क्रियाओं के लिए कॉर्पोरेट निवेशों की अंदरूनी जानकारी; (ii) आपदा प्रबंधन में व्यापक दृष्टिकोण एवं भूमिका: पारंपरिक अवधारणाओं के पार क्रियान्वयन ढांचाओं की दिशा में आगे बढ़ना; (iii) भूमिगत नगरीकरण: भारत के शहरी भविष्य के लिए भूमिगत स्थानों की भूमिका पर पुनर्विचार करना; (iv) भारतीय शहरों में पानी की समस्या: एक व्यवस्थात्मक विफलता या बदलते जलवायु का कहर; और (v) आपदा प्रबंधन योजना के लिए प्राकृतिक आधारित समाधान: जिला आपदा प्रबंधन योजना के लिए एक मार्गदर्शिका।



- **आयोजित की गई सम्मेलन/राउंड-टेबल/संगोष्ठियाँ एवं कार्यवाहियां:**

(i) स्थानीय जलवायु समुत्थानशीलता पर स्तरीय नीति वार्ता की रुपरेखा: विजन 2050 एवं सीएपी-आरईएस (डीएसटी-भारत सरकार की परियोजना) के तहत 2100 एलओसीसी-आरईएस; (ii) आपदा जोखिमों को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान के रूप में आर्द्रभूमि पर कार्यशाला; (iii) समुत्थानशीलता एवं स्थिरता शिखर सम्मेलन: विजन 2047; (iv) आपदा जोखिमों को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) के रूप में आर्द्रभूमि संरक्षण पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला ।



- **प्रकाशित प्रशिक्षण मॉड्यूल**

  i) जलवायु परिवर्तन और चरम घटनाओं के जोखिम में कमी पर प्रशिक्षण मैनुअल; ii) जलवायु प्रूफिंग आपदा राहत और पुनर्प्राप्ति; iii) डीआरआर के लिए हरित विकास और संसाधन दक्षता पर प्रशिक्षण मैनुअल: हरित अर्थव्यवस्था एवं समुत्थानशील विकास

वित्तीय एजेंसी: भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)

4.6. एनआईडीएम-यूनिसेफ: डीआरआर और टूलकिट (आईईसी) तैयारी के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार प्रशिक्षण पैकेज-प्रगति पर है।

व्यवहार परिवर्तन को लंबे समय से मुख्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है जिसके लिए आपदा तैयारी और विकास हस्तक्षेप का लक्ष्य होना चाहिए। जब व्यक्तियों और समुदाय अपने निर्णयों में आपदा प्रस्तुति और जोखिम संकट का अभ्यास अपनाते हैं, तो उनकी प्रतिरोधक्षमता मजबूती प्राप्त करती है, और उनके पास परिवर्तित परिस्थितियों के लिए समायोजन करने के साधन होते हैं और संवर्द्धन को कम करने और सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य जारी रहता है।

इस साझेदारी का कुल उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाताओं को सशक्त बनाना है ताकि वे सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के महत्व और मूल अवधारणाओं को समझ सकें और रोकथाम, शमन और तैयारियों से लेकर संकट प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति तक आपदा जोखिम प्रबंधन के सभी रूपों में एसबीसीसी को एकीकृत करने की क्षमता हासिल कर सकें।

31.03.2023 तक मुख्य प्रस्तुतियां:

- एसबीसीसी 90 मिनट का मॉड्यूल जिसे विभिन्न डीआरआर पर प्रशिक्षणों के साथ मिलाया जा सकता है। मॉड्यूल के अंदर 60 मिनट को एसबीसीसी के मूल अवधारणाओं के लिए समर्पित किया गया है।
- बाढ़, चक्रवात, भूकंप और सार्वजनिक स्वास्थ्य नामक 4 अलग-अलग आपदाओं की विशिष्ट एसबीसीसी आवश्यकताएं भी विकसित की गई हैं।
- विभिन्न प्रकार की आपदाओं (जिन्हें ऊपर उल्लिखित किया गया है) के लिए मुख्य क्षेत्रीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा, बाल संरक्षण आदि के महत्वपूर्ण व्यवहारिक संदेशों के साथ एसबीसीसीटूलकिट का कार्य जारी है।

प्रमुख भागीदार: संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ)

4.7 संकटकाल में भोजन और पोषण की आवश्यकताएँ: भारत में आपातकालीन राहत, प्रतिक्रिया और तैयारी रणनीतियों का एकीकरण पर एनआईडीएम-विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) की परियोजना

जलवायु परिवर्तन से जलवायु संबंधी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है, जिससे खाद्य असुरक्षा और खाद्य प्रणालियों के टूटने का अधिक जोखिम पैदा हो रहा है। चूँकि जलवायु संबंधी प्राकृतिक आपदाएँ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के चार आयामों पर खतरा पैदा करती हैं। यदि एसडीजी-2 लक्ष्यों को सतत् रूप से प्राप्त करना है, तो तीनों चरणों- राहत, प्रतिक्रिया और तैयारियों की नीति और संस्थागत ढांचे में खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई है। सरकारों के प्रयास से सभी स्तरों पर क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश और भागीदारों के बीच निरंतर उन्नयन और सुधार के लिए उदारता और प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, डब्ल्यूएफपी इंडिया के कंट्री डायरेक्टर और एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक के बीच आपदाओं और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के बीच अंतर-संबंधों के महत्व की पहचान के लिए एक परामर्शी बैठक हुई, जिसमें आपातकालीन स्थिति, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भोजन और पोषण रणनीतियों के लिए दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण पैकेज विकसित करने पर सहमति हुई।

इसे तीन चरणों में हासिल किया जा रहा है; पहले चरण में कमियों का विश्लेषण और दिशा-निर्देशों और पाठ्यक्रम का विकास किया जाएगा, अंतिम चरण में संचालन और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के अवसरों की खोज की जाएगी। चरणों का वर्णन नीचे दिया गया है:

प्रथम चरण: भारत के ईपीआर पैकेज में भोजन और पोषण रणनीतियों के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास।

द्वितीय चरण: आपात स्थिति में भोजन और पोषण आवश्यकताओं के लिए क्षमता सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण में सहायता

तृतीय चरण: अन्य देशों के लाभ के लिए आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया में खाद्य और पोषण पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के परामर्श का आयोजन।

4.8 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम)

माननीय प्रधानमंत्री के दस सूत्री कार्यक्रम में से एजेंडा 6 के अनुसरण में, एनआईडीएम द्वारा आपदा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारत विश्वविद्याल एवं संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) की स्थापना की गई है। आईयूआईएनडीआरआर- एनआईडीएम, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक मुद्दों, सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचा (2015-2030) और सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में कदम है, जो शिक्षा, नवाचार प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को बढ़ावा देने, क्षमता विकास को सुगम बनाने और स्थानीय खतरों के समाधान के लिए निर्णय लेने में सहायक है, साथ ही विभिन्न आपदाओं के प्रभावित समुदाय के सबसे वंचित वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान करता है।

आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम का दृष्टिकोण राष्ट्रों और समुदायों को शिक्षा, ज्ञान सृजन, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और प्रसार के माध्यम से आपदा के प्रति सुरक्षित और प्रतिरोधी बनाने का सपना है। नेटवर्क का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के बीच आपस में जानकारी का आदान-प्रदान करना और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समूह विकसित करना भी है।

आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएमके मुख्य उद्देश्य:

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और संबंधित क्षेत्र में कार्यान्वयन उन्मुख शिक्षा और अनुसंधान में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता में वृद्धि करना;
- देश भर के विभिन्न राज्यों में शिक्षा और नीति के बीच इंटरफेस के लिए एक मंच प्रदान करना;
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ज्ञान उत्पादों का दस्तावेजीकरण, विकास और प्रसार करना;
- उच्च शिक्षा (स्नातकोत्तर शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहना) में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना और एक साथ काम करना (द्विपक्षीय या बहुपक्षीय रूप में)
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्र आधारित और नीति उन्मुख अनुसंधान पर सहयोग करना
- सामान्य हित के मामलों और विषयों पर विश्वविद्यालयों के बीच परामर्श, सूचना का आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना

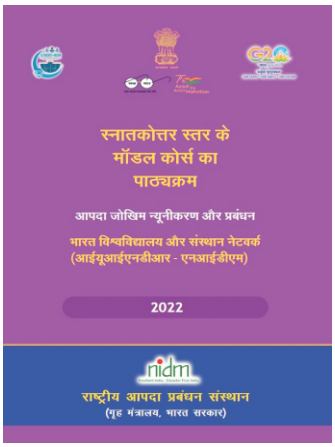
मुख्य परिणामों में शामिल हैं:

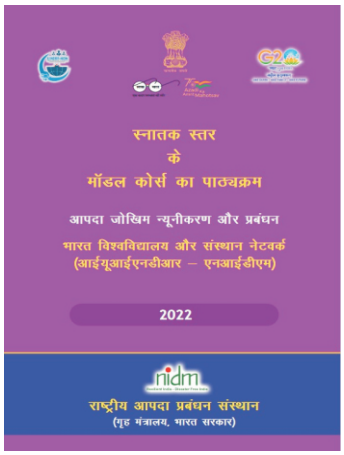
- यूजीसी ने स्नातक कार्यक्रम के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर फाउंडेशन कोर्स, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर सर्टिफिकेट कोर्स और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम द्वारा विकसित मॉडल पाठ्यक्रम को अधिसूचित किया है।
- बिहार राज्य ने फाउंडेशन कोर्स पर मॉडल पाठ्यक्रम अपनाया और बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मौजूदा नए शैक्षणिक सत्र से फाउंडेशन कोर्स लागू करने का निर्देश दिया।
- 254 विश्वविद्यालय और संस्थान आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम के हिस्से हैं।

दिनांक 31/03/2023 तक की विस्तृत गतिविधियाँ

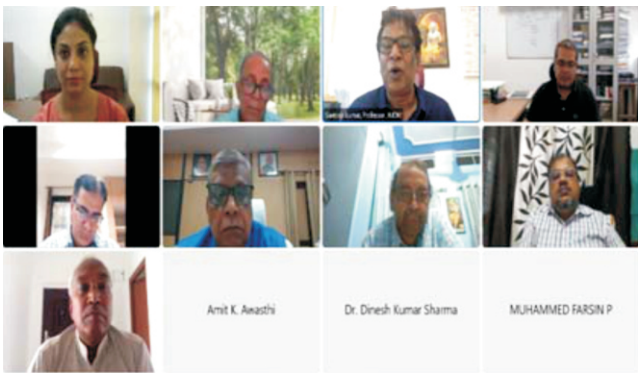
• आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सशक्तिकरण

भारत में उच्च शिक्षा के एक विषय के रूप में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक फाउंडेशन कोर्स पाठ्यक्रम विकसित किया है, जिसे हिन्दी भाषा में एक फाउंडेशन कोर्स मॉडल के रूप में स्नातक डिग्री कार्यक्रम के हर विषय में एकीकृत किया जा सकता है, जो भारत के हिन्दी भाषी राज्यों के लिए एक शिक्षण सहायता/गाइडबुक के रूप में उपयोगी होगा। ।



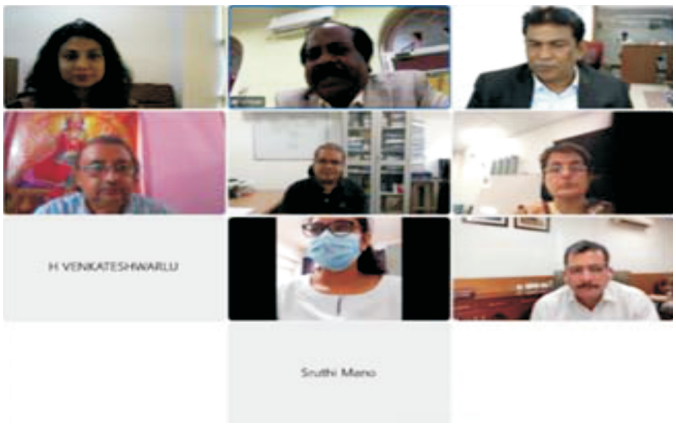


भारत के हिन्दी भाषी राज्यों में डीएम विषय के प्रभावी और उचित कार्यान्वयन के उद्देश्य से, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने शिक्षाविदों के लिए एक हैंडबुक/गाइडबुक के विकास का प्रस्ताव रखा, जो विभिन्न धाराओं में विषय के एकीकरण के लिए एक शिक्षण सहायता/गाइडबुक के रूप में उपयोगी होगा।



मॉड्यूल और पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई का खाका तैयार करने के लिए एक कोर ग्रुप समिति का गठन किया गया था। कोर ग्रुप की पहली बैठक 17 अगस्त 2022 को हुई थी। हैंडबुक के लिए एक टेम्पलेट कोर ग्रुप सदस्य द्वारा डिजाइन किया गया था और फाउंडेशन कोर्स के विभिन्न अध्यायों पर सामग्री लेखन के लिए विशेषज्ञों के साथ साझा किया गया था। देश भर के विशेषज्ञ डीआरआर के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और क्षेत्र के अनुसार हैंडबुक के विकास में भाग ले रहे हैं।

आपदा प्रबंधन विषय को नेट परीक्षा में शामिल करने के लिए यूजीसी, कुलपतियों, आईआईटी और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई। डीएम के क्षेत्र में पेशेवरों को विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर डीएम विषय के प्रभावी कार्यान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई और डीएम विषय को नेट परीक्षा में एकीकृत करने की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई।





- 10 दिसंबर, 2022 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के सहयोग से आपदा प्रबंधन पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और संकायों को आपदा प्रबंधन के मुद्दों और संबंधित घटकों पर संवेदनशील बनाना था।

- **आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम की सदस्यता**

नेटवर्क को मजबूती देने के लिए, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने सदस्यता के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है। आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम, यूनिवर्सिटियों/ संस्थानों को नेटवर्क की सदस्यता के लिए एक-एक कर आमंत्रित कर रहा है और मंजूरी के बाद, सदस्यता को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा जिसे आईयूआईएनडीआर-एनआईडीएम के तहत सदस्यों की सूची पर क्लिक करके देखा जा सकता है। वर्तमान में सदस्यता उच्च शिक्षा के विभिन्न यूनिवर्सिटियों और संस्थानों के लिए खुली है और नेटवर्क में शामिल होने के लिए कोई शुल्क लागू नहीं होता है। अब तक, देश भर में 254 विश्वविद्यालय और संस्थान इस नेटवर्क का हिस्सा हैं।

वित्तीय एजेंसी: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

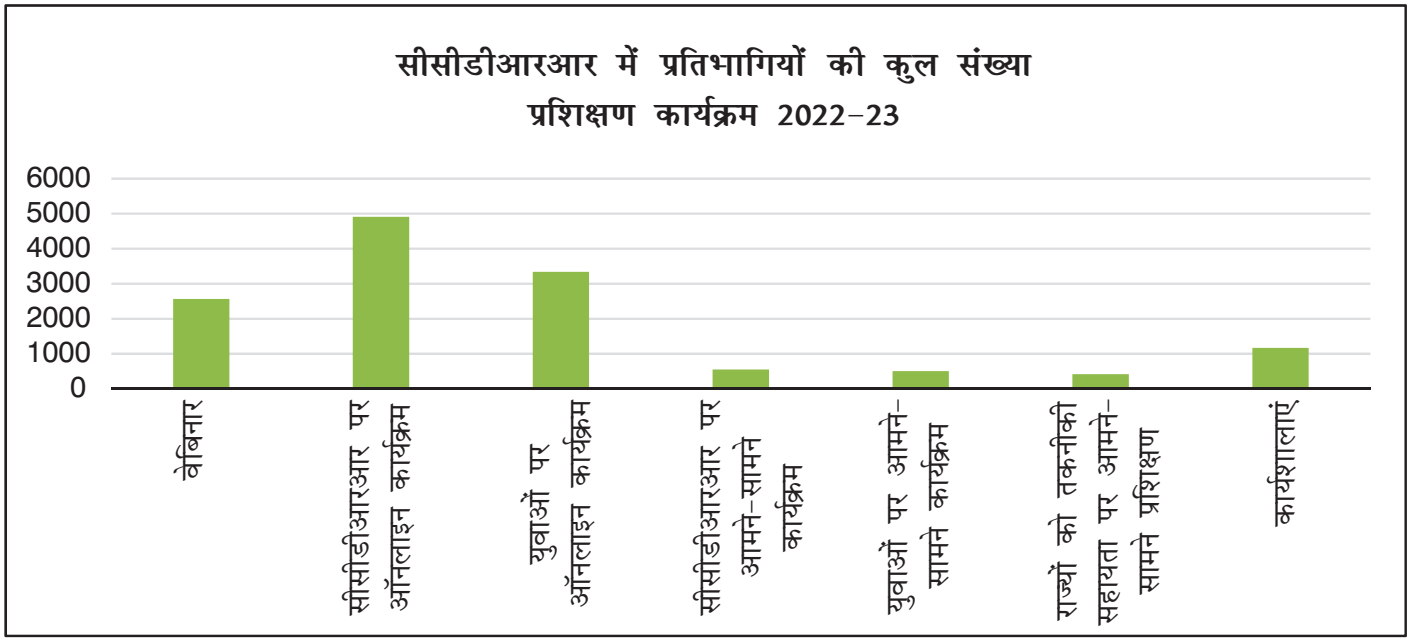
4.9 बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर), एनआईडीएम

सीसीडीआरआर केंद्र का मुख्य उद्देश्य: सीसीडीआरआर केंद्र का उद्देश्य बच्चों, किशोरों, युवाओं एवं महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन सहित आपदाओं के प्रभावों को रोकने, उसके लिए तैयार करने और कम करने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्थानों की क्षमता में वृद्धि करना है। केंद्र का लक्ष्य देश में विकलांगता समावेशन और लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित मुद्दों को मुख्यधारा में लाना भी है।

31/03/2023 तक की प्रस्तुतियां

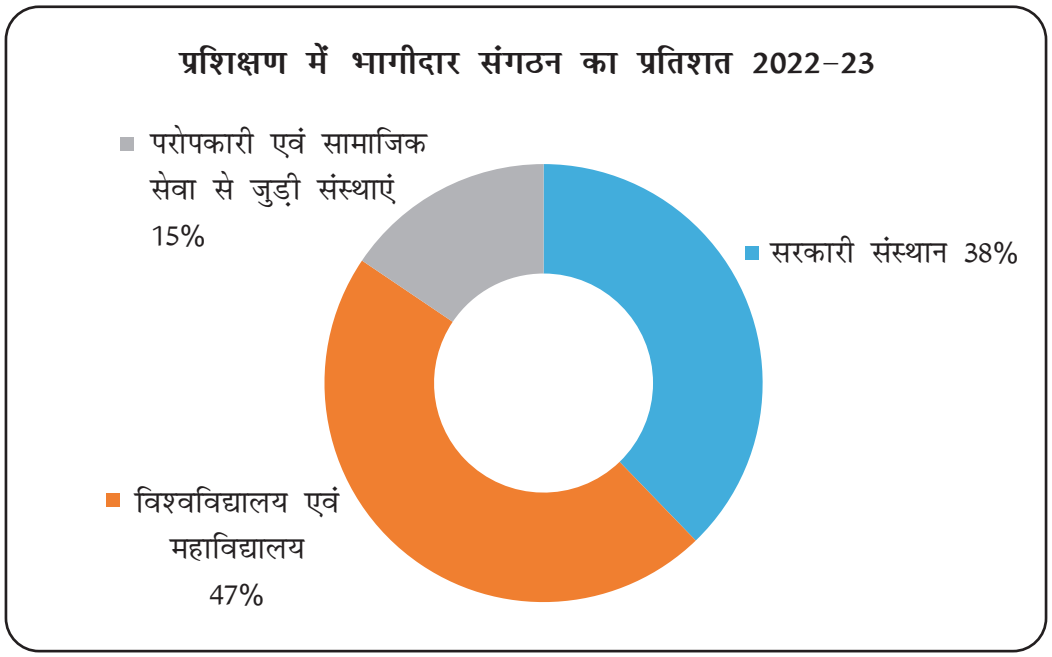
- **प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/वेबिनार**

क्रमांक	कार्यक्रम के प्रकार	कार्यक्रम की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	रुचि व्यक्त करने वालों की संख्या	बाहर से बुलाए गए व्यक्तियों की संख्या
1	वेबिनार	6	2567	3016	25
2	सीसीडीआरआर पर ऑनलाइन कार्यक्रम	8	4909	5120	28
3	युवाओं पर ऑनलाइन कार्यक्रम	9	3337	4573	28
3	सीसीडीआरआर पर आमने-सामने कार्यक्रम	8	555	611	30
4	युवाओं पर आमने-सामने कार्यक्रम	6	511	536	22
5	राज्यों को तकनीकी सहायता पर आमने-सामने प्रशिक्षण	7	421	444	23
6	कार्यशालाएं	6	1172	2888	15
	कुल	**50**	**13472**	**17188**	**171**



- **संगठनों और संस्थानों के साथ सम्बन्ध**

सीसीडीआरआर ने वैश्विक और स्थानीय स्तर के अनुभवों और ज्ञान को एक साथ लाने, युवाओं, बच्चों और महिलाओं से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण आउटपुट के साथ स्थायी सहयोग बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विभिन्न भागीदार संगठनों के साथ नेटवर्क और सहयोग किया है। वर्ष 2022-23 में, सीसीडीआरआर केंद्र ने आपदा जोखिम प्रबंधन योजना और शमन में बाल केंद्रित मुद्दों और चिंताओं को सबसे आगे लाने के लिए लगभग 45 संगठनों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि के साथ भागीदारी की। लगभग 17 (38%) सरकारी संगठनय 21(47%) विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान एवं परोपकारी और नागरिक समाज संगठन 7(15%) ने केंद्र के साथ आमने-सामने प्रशिक्षण, एक दिवसीय वेबिनार वार्ता/कार्यशाला आयोजित करने के लिए भागीदार संगठन के रूप में सहयोग किया। (जैसा कि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है)।



वित्तीय एजेंसी: संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ)

4.10 एनआईडीएम (दक्षिणी परिसर)

एनआईडीएम ने आंध्र प्रदेश कृष्णा जिले में कोंडापावुलुरू गांव, गन्नावरम मंडल में अपना दक्षिणी परिसर स्थापित किया है। परिसर में सरकारी अधिकारियों के लिए जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्तर के आमने-सामने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। भारत के विभिन्न हिस्सों से प्रतिनिधि/अधिकारी कैंपस कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

अद्यतन तस्वीरें इस प्रकार हैं:



*****

अध्याय 5

ज्ञान प्रबंधन और जागरुकता गतिविधियाँ

ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता गतिविधियाँ

5.1 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)

आईडीआरएन की शुरुआत गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार-यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003 में की गई थी। आईडीआरएन के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को वर्ष 2008 से आईडीआरएन की निगरानी और रख-रखाव का दायित्व सौंपा है। आइडीआरएन एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह उपकरण, मानव संसाधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति के संबंध में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है, जो जिला स्तर पर संबद्ध विभागों और एजेंसियों के पास उपलब्ध है ।

आईडीआरएन पोर्टल को https://idrn.nidm.gov.in पर स्थानांतरित कर दिया गया है और जून 2020 से इसे नए डिजाइन और संवादात्मक रूप के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। नया आईडीआरएन वेब पोर्टल नवीनतम वेब तकनीकों और प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता, जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है, जो समझने में आसान है। यह संवादात्मक, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल, सुरक्षित और धीमे इंटरनेट कनेक्शन पर भी कार्य निष्पादन जैसी विशेषताओं से सुसज्जित है।

एनआईसी की भूमिका-आईडीआरएन पोर्टल एनआईसी सर्वर पर स्थापित किया गया है

आईडीआरएन की निगरानी और रखरखाव वर्तमान में एनआईडीएम द्वारा केंद्रीयकृत रूप से की जाती है। एनआईडीएम की भूमिका उपयोगकर्ता प्रशासक, विकास और तकनीकी रखरखाव, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता तक सीमित है। एनआईडीएम डेटा संग्रह या अद्यतनीकरण में शामिल नहीं है।

आई.डी.आर.एन कैसे कार्य करता है

राज्य प्राधिकारियों की भूमिका- राज्य राहत विभाग/आपदा प्रबंधन/एसडीएमए आईडीआरएन में आंकड़ों को अद्यतन बनाने के लिए डीएम/डीसी के साथ समन्वय करते हैं।

जिला प्राधिकारियों की भूमिका- जिला स्तर पर आंकड़ों के संग्रह और उन्हें अद्यतन रूप देने के कार्य को सुगम बनाने के लिए जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट प्राधिकृत अधिकारी होता है। आंकड़ों के संग्रह का प्रारूप सभी सम्बद्ध विभागों और एजेंसियों को जिला प्रशासन द्वारा भेजना होता है और एक या दो सप्ताह में उसे एकत्र करना होता है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा तकनीकी सेवाओं का उपयोग करते हुए जिला स्तर पर आंकड़ों की प्रविष्टियां की जानी चाहिए।

आईडीआरएन पोर्टल का उपयोग- सभी उपलब्ध संसाधनों की अद्यतन जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए कोई भी, किसी भी आपात स्थिति के दौरान आईडीआरएन पोर्टल का उपयोग कर सकता है जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान जानमाल की क्षति और संपत्ति तथा अन्य बुनियादी ढांचे की क्षति को कम करने में अत्यंत सहायक होगा। आईडीआरएन पर संसाधन मदों की सूची देखने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है।

5.2 एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस

एनआईडीएम ने अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। आपदा तैयारी के लिए इन प्रशिक्षुओं का पता लगाने में सरकारों/हितधारकों की मदद करने के लिए इन प्रशिक्षणों, प्रशिक्षुओं और प्रतिभागियों का पूरा डेटाबेस ऑनलाइन रखा गया है। यह जानकारी एनआईडीएम की बेवसाइट URL: http://nidm.gov.in/trainee.asp पर 2009 से उपलब्ध है।

5.3 सूचना प्रसार

5.3.1 पुस्तकालय:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का पुस्तकालय अपने संकाय/कर्मचारियों, भारत और विदेशों के शोधार्थियों, एनआईडीएम द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/डिप्लोमा कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और अन्य अतिथि संकाय और उपयोगकर्ता की सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन और शिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है।

एनआईडीएम पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख नीचे किया गया है–

- पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा अन्य पठन सामग्री का अधिग्रहण
- संदर्भ और संप्रेषण कार्य
- परिसंचरण कार्य
- पुस्तकालय स्वचालन

5.3.2 दस्तावेजीकरण और प्रकाशन

सूचना को एक संसाधन के रूप में माना जाता है, जो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। एक परिसंपत्ति के रूप में सूचना के मूल्य को इसके प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से सर्वोच्च स्तर तक लाया जाता है। प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आपदा प्रबंधन और विकास संबंधी जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए निरंतर आधार पर ठोस प्रयास करना एनआईडीएम के अधिदेशों में से एक है।

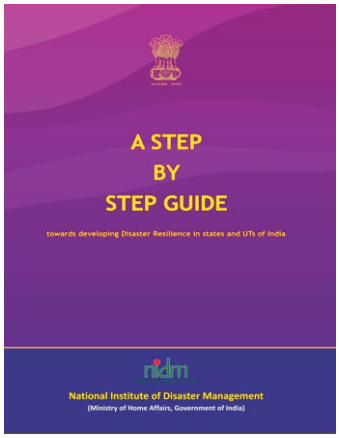
सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री

संस्थान को आपदा प्रबंधन और संबंधित पहलुओं पर सूचना प्रसारित करने का अधिदेश प्राप्त है। अधिदेश को पूरा करने में, संस्थान नियमित रूप से एक त्रैमासिक समाचार पत्रिका (टाइडिंग्स) और विभिन्न प्रकाशन प्रकाशित करता है। विभिन्न आपदाओं और उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी और जागरूकता पैदा करने के लिए, एनआईडीएम नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता पैदा करने वाले संदेशों के साथ आईईसी सामग्री प्रकाशित करता है जिसे विभिन्न वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में रखा जाता है। ये उपकरण एनआईडीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें http://nidm.gov.in./iec.asp पर देखा जा सकता है। एनआईडीएम द्वारा विकसित आईईसी सामग्री का आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न हितधारकों द्वारा एनआईडीएम को समुचित श्रेय देते हुए स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है और व्यापक प्रसार के लिए विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एनआईडीएम द्वारा मुद्रित प्रकाशनों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

प्रकाशन

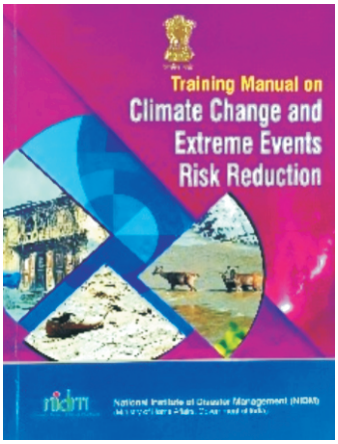
प्रशिक्षण मॉड्यूल

i. भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आपदा समुत्थानशीलता विकसित करने की दिशा में चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका



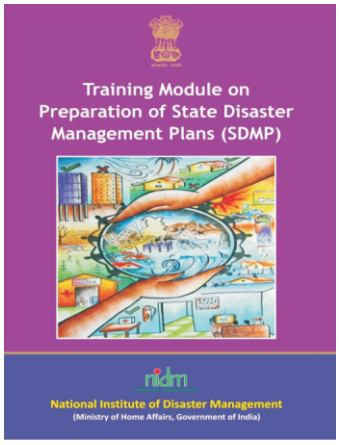
यह चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका अब प्रसिद्ध डीएम ढांचे के आलोक में भारत में राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की आपदा समुत्थानशीलता में सुधार के कदमों पर विस्तार से बताती है जिसमें आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों की सभी सूचीबद्ध जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन कार्य में लगे संस्थानों, समुदायों और व्यक्तियों की पहचान की जाती है। यह वर्तमान आपदा प्रबंधन ढांचे और संबंधित अधिदेशों में सुधार और निर्माण करता है। यह मार्गदर्शिका एमएचए-यूएनडीपी रिपोर्ट में दर्ज आपदाओं और उप-विषयों तक ही सीमित है।

ii. जलवायु परिवर्तन और चरम घटनाओं के जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण मैनुअल



इस मैनुअल को विशेष रूप से प्रशिक्षुओं को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर), जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) के बारे में जानकारी प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों की क्षमता का निर्माण करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। यह मैनुअल जलवायु और मौसम से संबंधित चरम घटनाओं और समग्र ज्ञान और कौशल के बारे में अवधारणाओं और समझ पर प्रशिक्षण गतिविधियों में मदद करता है जिससे कि भीषण आपदाओं से निपटने के लिए समय रहते कदम उठाकर उससे बचने के उपाय किए जा सकें और नुकसान को कम किया जा सके। इसमें पांच मॉड्यूल हैं और इसे पांच दिन के पाठ्यक्रम के लिए व्यवस्थित किया गया है, जिसमें सीखने के लिए रोचक गतिविधियां, केस स्टडीज, और मैनुअल के समग्र ढांचे का समर्थन करने वाले उपकरण शामिल हैं।

iii. राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) की तैयारी पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

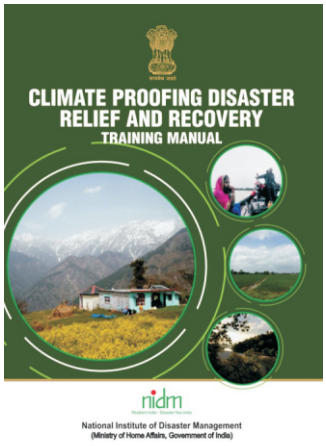


भारत कई तरह के खतरों से प्रभावित देश है और यह नियमित रूप से किसी न किसी संकट से जूझता रहता है। इस को ध्यान में रखते हुए, राज्य और जिला स्तर पर प्रशासन के प्रति बेहतर योगदान करने वाली क्षमताओं का निर्माण करके लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सकता है। एक आपदा प्रतिरोधी राष्ट्र बनने के लिए भौतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक कारकों से होने वाले नुकसान को कम करना अनिवार्य है।

भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राज्य स्तर पर डीआरआर एजेंडा और आपदा प्रबंधन योजना को बढ़ावा देने और लागू करने में प्रमुख भूमिका है, यह प्रणालीगत तरीकों से जोखिम मूल्यांकन, रोकथाम-शमन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, क्षमता और संसाधनों की रिकवरी के लिए रणनीतिक और नियोजित दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) मॉड्यूल पर यह प्रकाशन एनडीएमए द्वारा विकसित एसडीएमपी

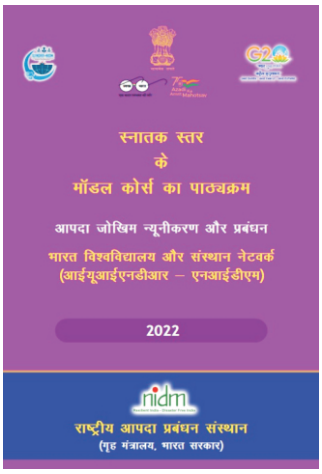
दिशा-निर्देशों को प्रशिक्षण मॉड्यूल में बदलने का एक प्रयास है, जिसका उपयोग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के एकमात्र उद्देश्य के लिए एक मार्गदर्शक उपकरण के रूप में अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी में किया जाएगा।

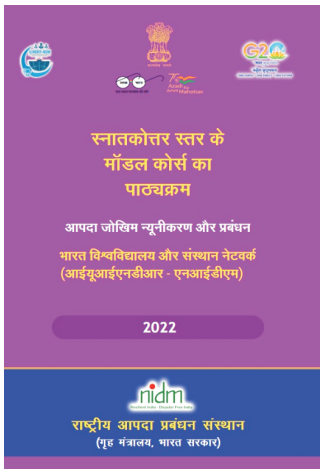
iv. जलवायु प्रूफिंग आपदा राहत और पुनर्प्राप्ति (प्रशिक्षण मैनुअल)



क्लाइमेट प्रूफिंग डिजास्टर रिलीफ एंड रिकवरी पर यह प्रशिक्षण मैनुअल सावधानीपूर्वक तैयार मैनुअल के पांच मॉड्यूल में विचार-विमर्श किए गए अद्वितीय दृष्टिकोणों का पालन करते हुए तैयारी के उपायों में सहायता करता है। इस मैनुअल में i) जलवायु प्रूफिंग आपदा प्रबंधन, ii) आपदा और पर्यावरणीय स्थिरता, iii) सतत् आपदा राहत, iv) सतत् आपदा रिकवरी, v) हरित राहत और रिकवरी पर बहुत महत्वपूर्ण मॉड्यूल शामिल हैं। इस मॉड्यूल का उद्देश्य आपदा राहत और पुनर्प्राप्ति उपायों के प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण विकसित करना है ताकि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह मैनुअल आपदा के बाद की स्थितियों में राहत और पुनर्प्राप्ति उपायों में सुधार के लिए हरित दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

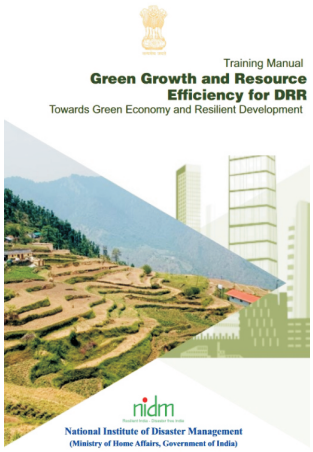
v. स्नातकोत्तर स्तर/स्नातक स्तर के लिए मॉडल पाठ्यक्रम





आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन में स्नातक से पहले और स्नातकोत्तर स्तर के लिए यह मॉडल पाठ्यक्रम आपदा प्रबंधन में करियर के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाठ्यक्रम एक प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रदान करता है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्नातक डिग्री के पहले वर्ष के पूरा होने के बाद, छात्रों को डीआरआरएम पर एक प्रमाणपत्र मिलेगा और दो साल के बाद, आपदा प्रबंधन से संबंधित एक विशेष क्षेत्र में डिग्री प्राप्त होगी। छात्र प्रमाणपत्र कार्यक्रम के साथ एक वर्ष के बाद बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है और यूजीसी द्वारा अगले निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी विशेष क्षेत्र में अंडर ग्रेजुएट डिग्री के दूसरे वर्ष में फिर से शामिल हो सकता है। पाठ्यक्रम को यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार नई शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप डिजाइन किया गया था।

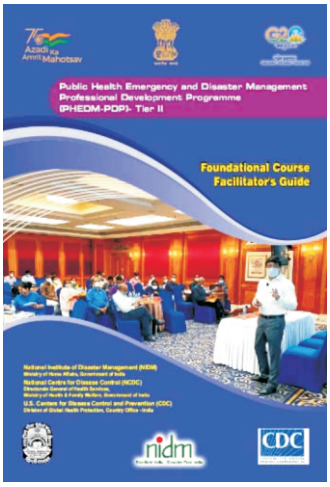
vi. हरित अर्थव्यवस्था और समुत्थानशील विकास की दिशा में डीआरआर के लिए हरित विकास एवं संसाधन दक्षता पर प्रशिक्षण मैनुअल



''डीआरआर के लिए हरित विकास और संसाधन दक्षता'' पर प्रशिक्षण मैनुअल बहु-खतरा पर्यावरण (सीएपी-आरईएस) में समुत्थानशील और सतत् विकास के लिए जलवायु अनुकूल परियोजना के एक भाग के रूप में तैयार किया गया है और इसे भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), के समर्थन से (एनआईडीएम) के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मैनुअल हरित विकास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उप-विषयगत क्षेत्र में ज्ञान की कमी और

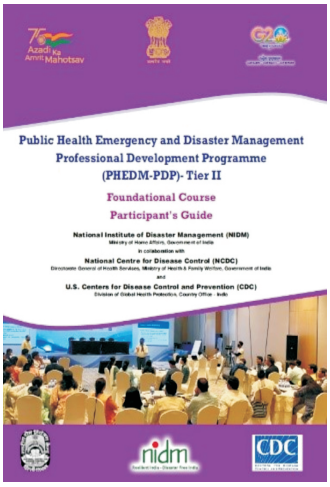
क्षमता निर्माण की जरूरतों को समझता है। मॉड्यूल का फोकस अनुकूलन के माध्यम से तैयारियों को बढ़ावा देना है। यह मैनुअल प्रशिक्षुओं को हरित विकास के विषयों, दृष्टिकोणों और मार्गों की बुनियादी समझ और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में इसके अनुप्रयोग के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह मैनुअल सतत् विकास की समझ विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शन और ज्ञान दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, और विकास के सभी क्षेत्रों में हरित विकास प्राप्त करने के मार्गों के लिए कार्बन तटस्थता दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

vii. जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम-पीडीपी)-टियर II (फाउंडेशनल कोर्स, फैसिलिटेटर गाइड)



एनआईडीएम, एनसीडीसी और सीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल 'जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम-पीडीपी)-टियर II (फाउंडेशनल कोर्स, फैसिलिटेटर गाइड)' जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन की नींव को कवर करता है (राज्य और जिला स्तर पर क्षमता विकसित करने के लिए पीएचईडीएम सिद्धांत, अवधारणाएं, प्रक्रियाएं, उपकरण, प्रथाएं और मार्गदर्शन शामिल हैं।) यह जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन सिद्धांतों पर चर्चा करने और आपातकालीन परिचालन केंद्र के कामकाज का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने पर भी केंद्रित है। मॉड्यूल उन चिकित्सकों, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के लिए डिजाइन किया गया है जो कई क्षेत्रों में काम करते हैं जो सभी प्रकार की आपात स्थितियों और आपदाओं के स्वास्थ्य जोखिमों और परिणामों को कम करने में योगदान करते हैं।

viii. जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम-पीडीपी)-टियर II, (फाउंडेशनल कोर्स, प्रतिभागी गाइड)

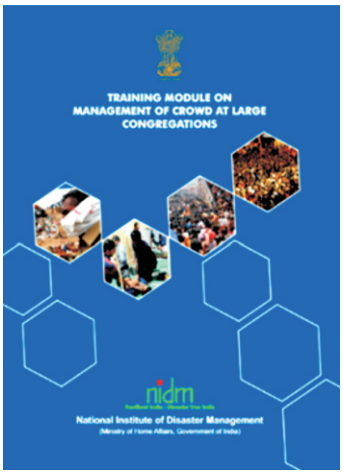


एनआईडीएम, एनसीडीसी और सीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 'जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम-पीडीपी) - टियर II, (फाउंडेशनल कोर्स, प्रतिभागी गाइड)' पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य जन स्वास्थ्य के बारे में आपातकालीन प्रबंधन ढाँचे, कर्मचारी और कार्यक्रम तत्वों को गहन जानकारी प्रदान करना है। वर्तमान प्रतिभागी की मार्गदर्शिका एक टियर-II प्रशिक्षण पैकेज प्रदान करती है जो राज्य और जिला स्तर पर क्षमता विकसित करने के लिए जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) सिद्धांतों, अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, उपकरणों, प्रथाओं और मार्गदर्शन की नींव को कवर करती है।

ix. बड़ी सभाओं में भीड़ के प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

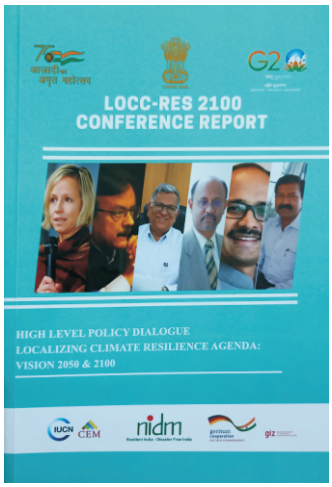
हाल ही में देखा गया है कि न सिर्फ भगदड़ की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं से जानमाल के नुकसान में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न हितधारकों जैसे- प्रशासक, कार्यक्रम आयोजक आदि का प्रशिक्षण और जागरूकता सृजन के माध्यम से क्षमता निर्माण कर भीड़ के कारण होने वाली आपदाओं (भगदड़) के जोखिम को कम करने में निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस पहलू पर प्रशिक्षण अभी तक देश में शुरू नहीं किया गया है, इसलिए एनआईडीएम ने विभिन्न भीड़

प्रबंधन उपकरणों के माध्यम से भगदड़ के जोखिम को कम करने के तरीकों के बारे में संबंधित एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण पहलू पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने की पहल की है। इस पहलू पर प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए संस्थान ने यह मॉड्यूल विकसित किया है। मॉड्यूल का उद्देश्य भगदड़ के संबंध में तैयारियों और प्रतिक्रिया की विभिन्न प्रथाओं के बारे में प्रशासकों, पुलिस और अन्य हितधारकों सहित प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाना और उन्हें ऐसी घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए ऐसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए तैयार करना है।



कार्यवाही

i. सम्मेलन रिपोर्ट: उच्च स्तरीय नीति संवाद स्थानीयकरण जलवायु समुत्थानशील एजेंडा: परिकल्पना 2050 और 2100 एलओसीसी-आरईएस



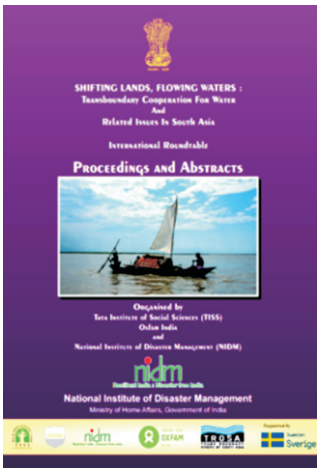
आईपीसीसी की हालिया छठी मूल्यांकन रिपोर्ट ने न केवल मानव विकास में दीर्घकालिक समुत्थानशीलता के लिए तत्काल कार्रवाई की गारंटी दी है, बल्कि भविष्य के जोखिमों की जटिलता के बारे में भी आगाह किया है। दूरगामी यानी 2050 और 2100-जलवायु चुनौतियों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए आगे की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी स्तरों पर एक बड़े विज्ञान-नीति-अनुसंधान इंटरफेस की आवश्यकता होती है। इसमें मौजूदा एसएंडटी और नीति ढांचे को मजबूत करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया गया है। 'एलओसीसी-आरईएस 2100 यानी स्थानीयकरण जलवायु समुत्थानशील एजेंडा: 2050 और 2100 विजन' भविष्य के जलवायु मुद्दों और चुनौतियों को समझने की दिशा में एक कदम है। इस उच्च स्तरीय नीति संवाद के दौरान चर्चा और विचार-विमर्श 2050 के बाद के डीआरआर और जलवायु प्रतिरक्षा अनुकूलन एजेंडे के लिए एस एंड टी के लिए प्रमुख प्रवेश बिंदु प्रदान करने का प्रयास करता है।

ii. जलवायु जोखिम प्रबंधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान-नीति-अभ्यास इंटरफेस की कार्यवाही

यह रिपोर्ट जलवायु जोखिम न्यूनीकरण पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान-नीति-अभ्यास इंटरफेस पर आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन पर केंद्रित है, जो पीएम के एजेंडा 10 के आइटम 5 को लागू करने के लिए अकादमिक और वैज्ञानिक समुदाय की प्रतिबद्धता की पहचान करने का एक प्रयास है, यानी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। रिपोर्ट ने हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच ज्ञान साझा करने को बढ़ावा दिया और जोखिम मूल्यांकन की समझ को बढ़ाने और जोखिम मूल्यांकन को कार्रवाई, जोखिम-संवेदनशील निवेश में शामिल करने के लिए जोखिम मूल्यांकन में निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने में मदद की। दस्तावेज को व्यवसाय निरंतरता योजनाओं में डीआरआर को शामिल करने से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया था।



iii. भूमि के बदलाव, जल बहाव: दक्षिण एशिया में पानी और संबंधित मुद्दों के लिए सीमा-पार सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन



वर्तमान कार्यवाही जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज (जेटीएसडीएस), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस), मुंबई; ऑक्सफैम इंडिया; और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा 'बदलती भू स्थितियां, बहते पानी: दक्षिण एशिया में सीमांत जल प्रबंधन' विषय पर आयोजित चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का कार्यकारी सारांश प्रदान करती है। इसके अलावा, अध्ययन विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण की समझ का पता लगाता है जो हाशिए एवं जल पर निर्भर कमजोर समूहों की बेहतरी के लिए रचनात्मक संवाद की सुविधा के माध्यम से खाई को पाटने के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यवाही में विवरण शामिल हैं जो स्वीकार करते हैं कि दक्षिण एशिया में नीति के निर्धारण को समावेशी एवं जन-केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ तटीय क्षेत्रों में जल संसाधनों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे की दिशा में अपने एजेंडे को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें प्रस्तुत पत्रों के सार भी शामिल हैं।

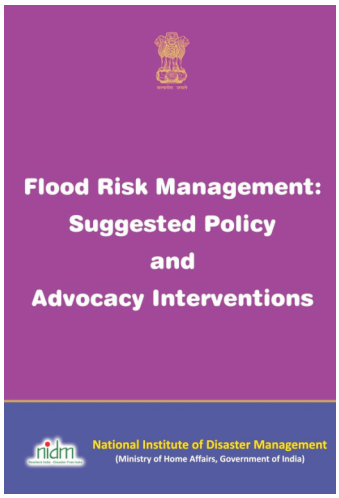
iv. ''कोविड-19 के दौरान और उसके बाद जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन: भारत में समुत्थानशील कार्यबल, प्रणाली और बुनियादी ढांचे का निर्माण'' पर साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला की सारांश रिपोर्ट।



'कोविड-19 के दौरान और उसके बाद जन स्वास्थ्य आपदा और आपदा प्रबंधन: भारत में समुत्थानशील कार्यबल, प्रणाली और बुनियादी ढांचे का निर्माण' पर साप्ताहिक श्रृंखला की यह सारांश रिपोर्ट जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं से निपटने में क्षमताओं में वृद्धि के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचे और दिशा-निर्देशों को बढ़ावा देने के लिए एक कदम था। यह रिपोर्ट अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए प्राप्त ज्ञान के बारे में जागरूकता फैलाएगी और जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करेगी। 24 वेबिनारों की श्रृंखला पीएचईडीएम से संबंधित विभिन्न विषयों पर आधारित है।

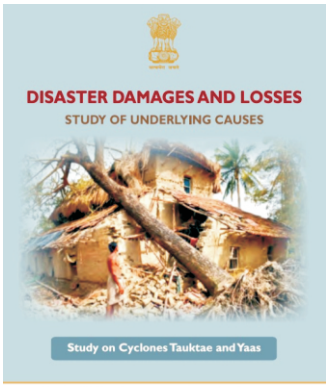
घटनाओं का अध्ययन

i. बाढ़ जोखिम प्रबंधन: नीतिगत सुझाव एवं हस्तक्षेप की पैरवी



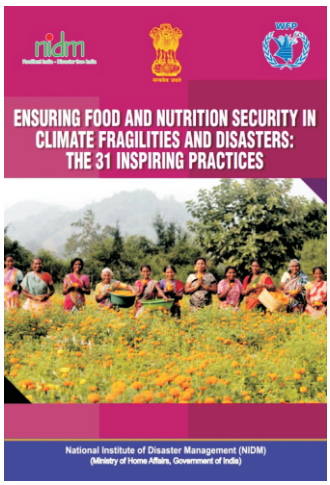
यह दस्तावेज भारत में बाढ़ प्रबंधन के लिए एक नई रूपरेखा का सुझाव देता है। यह जलाशय, बांध और बेसिन के लिए बाढ़ जोखिम और आपदा प्रबंधन के लिए एक कार्य योजना का भी प्रस्ताव करता है जिसमें एक एकीकृत जलाशय, बांध और नदी बेसिन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना शामिल है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बाढ़ जोखिम का आकलन करेगा। एक सफल मूल्यांकन के बाद, एक बाढ़ प्रबंधन योजना विकसित और अपनाई गई है। एकीकृम जलाशय, बांध और नदी बेसिन प्रबंधन प्राधिकरण (आईआरडीआरबीएमए) बाढ़ पूर्व चरण से लेकर बाढ़ के बाद की स्थिति तक बाढ़ जोखिम प्रबंधन के हर चरण में एक अभिन्न भूमिका निभाता है।

ii. आपदा से क्षति एवं नुकसान- अंतर्निहित कारणों का अध्ययन (चक्रवात ताउते और यास पर अध्ययन)



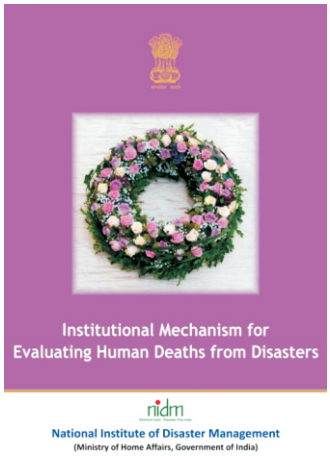
इस अध्ययन का उद्देश्य उन कारकों का विश्लेषण करना और समझना है जिसके कारण चक्रवात ताउते और यास ने लोगों की जान ली और इसके अलावा तैयारियों को मजबूत करने के लिए जिन सिफारिशों की पहचान की गई है। नुकसान का निष्पक्ष विश्लेषण करने और प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट नुकसान के संभावित कारणों की पहचान करने के लिए, चक्रवाती घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के छह डोमेन तैयार किए गए हैं: क) मानव जीवन की क्षति एवं हानि, ख) क्षति एवं आजीविका की हानि, ग) आवास संरचनाओं को नुकसान घ) भौतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान ड.) सामाजिक बुनियादी ढांचे को नुकसान और च) पर्यावरण को नुकसान.

iii. जलवायु में तीव्र बदलाव एवं आपदाओं में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना: 31 प्रेरक प्रथाएँ



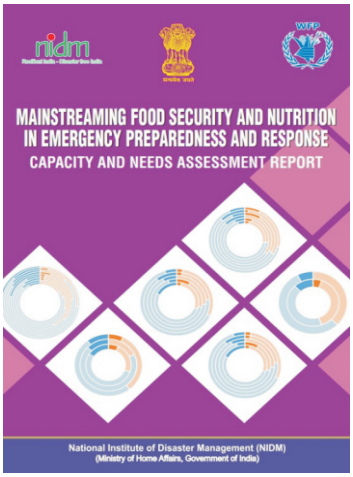
जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के विभिन्न प्रभावों के बीच, सबसे बुरी तरह प्रभावित प्रक्रियाओं में से एक वह प्रक्रिया है जो खाद्य सुरक्षा को रेखांकित करती है। सदियों से, आपदाओं पर प्रतिक्रिया देने की भारत की रणनीति राहत-उन्मुख दृष्टिकोण से आई है। हालाँकि, हाल के दिनों में, रोकथाम, शमन और तैयारियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन ढांचे में तात्कालिक रणनीतियों को जोड़ने में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में विभिन्न सुधारों और पहलों ने प्रदर्शित परिणामों के साथ स्पष्ट प्रबंधन और परिचालन लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के बीच अंतर्संबंध और समानांतर स्थितियों में खाद्य सुरक्षा को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह सार-संग्रह पूरे एशिया में कई सिद्ध और नवीन समाधानों पर प्रकाश डालता है और सहायक एजेंसियों द्वारा अपनाए गए विभिन्न मुकाबला तंत्रों का सार भी प्रदान करता है। उत्तरजीवी समुदायों के रूप में आपदा के दौरान भोजन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एक परिप्रेक्ष्य जो भोजन की उपलब्धता और राहत से परे हैं। इसलिए, आबादी को अनुकूलन रणनीतियों का अभ्यास करने के साथ-साथ समुत्थानशील होने की क्षमता बनाने में सक्षम बनाने की दृष्टि से कृषि, प्रौद्योगिकी, भोजन, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रदर्शित समाधानों और रणनीतियों पर जानकारी साझा करने के लिए यह संग्रह तैयार किया गया है। आपातकालीन स्थिति में भोजन से संबंधित चुनौतियों पर काबू पाने में मदद मिली है और साथ ही आगे स्केलिंग और प्रतिकृति का अवसर भी मिला है।

iv. आपदाओं से मानव मृत्यु के मूल्यांकन के लिए संस्थागत तंत्र



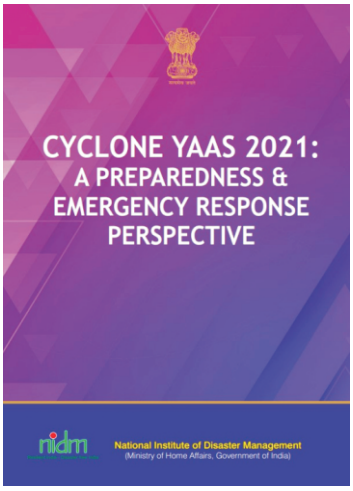
यह अध्ययन चार राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसने दो चक्रवातों यानि ताउते और यास के कारण मानव जीवन पर आपदा के प्रभाव के मूल कारण की पहचान करने में मदद की है। यह मानव जीवन पर पड़ने वाले इन प्रभावों के पीछे होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों की भी पहचान करता है। साथ ही यह अध्ययन डीआरआर में सुधार के लिए मानव जीवन पर आपदा प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए राज्यों/जिला स्तर पर एक संस्थागत तंत्र का सुझाव देता है। इसके अलावा, अध्ययन से उपयुक्त प्रशिक्षण और जागरूकता तथा आईईसी सामग्री विकसित करने में मदद मिलेगी।

v. आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण को मुख्य रुप से जोड़ना (क्षमता और आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट)



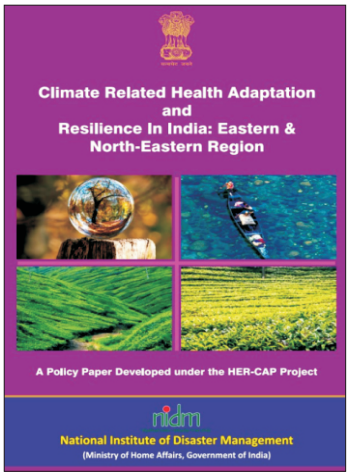
बदलते जोखिम परिदृश्य के साथ, यह और कुछ नहीं बल्कि जरूरी है कि क्षमता-मजबूतीकरण के प्रयासों को एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जाए ताकि किसी भी अचानक या उभरती मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए मानवीय संरचनाओं को लगातार अद्यतन और मजबूत किया जा सके। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के तकनीकी सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने क्षमता अंतराल के साथ-साथ वर्तमान और अव्यक्त क्षमताओं की पहचान करने के उद्देश्य से क्षमता आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है ताकि क्षमता को बढ़ाया जा सके। आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया (ईपीआर) कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए मजबूत ढांचे को और अधिक रणनीतिक बनाया गया है। यह अध्ययन स्वयं में एक प्रारंभिक बिंदु है, जिससे मौजूदा क्षमताओं और कमियों की समझ में सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन लंबे समय तक, एक अधिक रणनीतिक स्तर पर।

vi. चक्रवात यास 2021: तैयारी एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया परिप्रेक्ष्य



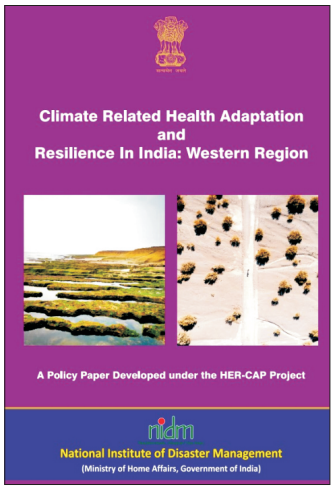
26 मई 2021 को, भीषण चक्रवाती तूफान ''यास'' ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी, जिससे बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, यह तबाही मुख्य रूप से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के अधिकांश जिलों में देखने को मिली। चक्रवात ऐसे समय में आया जब भारत में आपदा प्रबंधन प्रणालियाँ, विशेष रूप से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ, कोविड-19 महामारी की घातक दूसरी लहर के प्रबंधन में अत्यधिक व्यस्त थीं। इस आपदा का केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बहुत ही पेशेवर तरीके से जवाब दिया गया। चक्रवात के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों ने ऐसे मुद्दों को जन्म दिया है जिन पर विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से बहु-खतरे वाले परिदृश्यों में। यह दस्तावेज सभी महत्वपूर्ण हितधारकों से कालानुक्रमिक तरीके से चक्रवात 'यास' पर प्रकाश डालता है और मूल्यवान सबक सामने लाता है।

vii. भारत में जलवायु संबंधी स्वास्थ्य अनुकूलन एवं समुत्थानशीलता: पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र



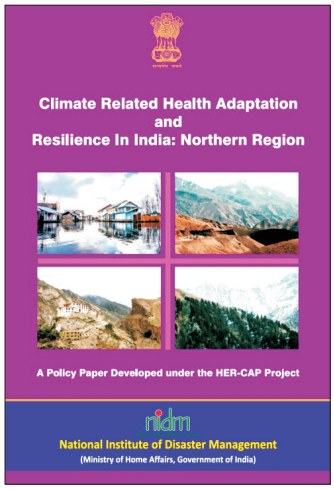
यह बहुत स्पष्ट है कि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दोनों क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि हुई है, और वर्षा का वितरण कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक कम हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी, पेरी-शहरी और गाँव में जलप्लावन और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यह वेक्टर जनित बीमारियों को जन्म देता है। दूसरी ओर, बढ़ता प्रदूषण श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों को जन्म दे रहा है। यह नीति पत्र जलवायु परिदृश्य को बदले बिना, ऐसे स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने और इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के सूक्ष्म तरीकों का वर्णन करता है।

viii. भारत में जलवायु संबंधी स्वास्थ्य अनुकूलन और समुत्थानशीलता: पश्चिमी क्षेत्र



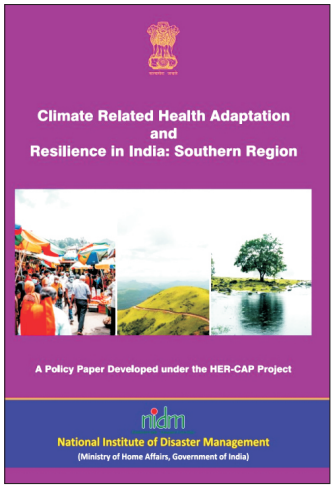
भारत के पश्चिमी भाग, भारत के शुष्क क्षेत्र में स्थित हैं। भौगोलिक स्थिति, जलवायु परिस्थितियों और अन्य कारकों के कारण, इन क्षेत्रों और मानव स्वास्थ्य पर जलवायु का प्रभाव अन्य भागों से भिन्न होता है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, शिक्षा और सामाजिक संरचना जैसे कई मापदंडों के कारण प्रत्येक क्षेत्र और राज्य की अनुकूलन क्षमता भिन्न होती है। यह नीति पत्र पश्चिमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विशेषज्ञों के साथ गहन परामर्श के बाद इन सभी मौजूदा और आगामी समस्याओं और उनके शमन उपायों और लचीलापन नीति को शामिल करता है।

ix. भारत में जलवायु संबंधी स्वास्थ्य अनुकूलन और समुत्थानशीलता: उत्तरी क्षेत्र



यह स्पष्ट है कि बाढ़ प्रभावित उत्तरी क्षेत्र अपनी विशिष्ट कृषि-भू-पारिस्थितिकी के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और रखरखाव स्वास्थ्य समस्याओं के निवारक पहलुओं को मजबूत करने में सहायक होगा। फ्रंट-लाइन पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण से ग्रामीण, पेरी-शहरी और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समुत्थानशीलता विकसित करने में मदद मिलेगी। यह पेपर जलवायु परिदृश्य को बदले बिना ऐसे स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने और समुत्थानशील बनाने का एक सूक्ष्म तरीका बताता है।

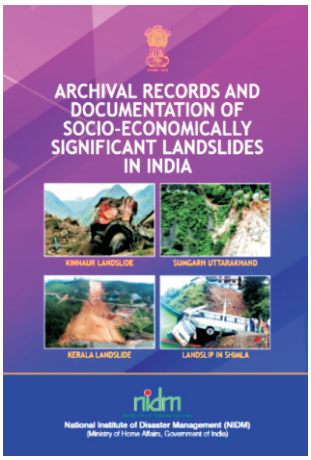
x. भारत में जलवायु संबंधी स्वास्थ्य अनुकूलन और समुत्थानशीलता: दक्षिणी क्षेत्र



दक्षिणी राज्यों में, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, अप्रवासन, भूमि उपयोग में परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट जैसे सामाजिक और जनसांख्यिकीय कारक संक्रामक रोगों के हालिया पुनरुत्थान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। विभिन्न आपदाओं के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों में स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वच्छता की हानि, आश्रय और सामान की हानि, जनसंख्या विस्थापन, विषाक्त जोखिम, और भोजन की कमी के कारण भूख और कुपोषण के जोखिम से जुड़ी बीमारियाँ शामिल हैं। यह नीति पत्र दक्षिणी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विशेषज्ञों के साथ गहन परामर्श के बाद इन सभी मौजूदा और आगामी समस्याओं और उनके शमन उपायों और समुत्थानशीलता नीति को कवर करता है।

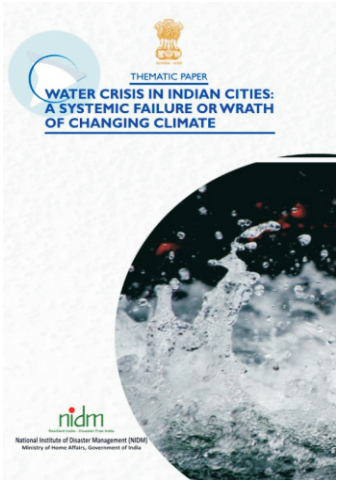
xi. भारत में सामाजिक-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भूस्खलन के अभिलेखीय रिकॉर्ड और दस्तावेजीकरण

वर्तमान दस्तावेज में, भूस्खलन को सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के स्तर, यानी निम्न, मध्यम या उच्च को परिभाषित करके विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुछ भूस्खलनों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें नाशरी भूस्खलन, खुनीनाला भूस्खलन, मालपा रॉक हिमस्खलन, द ग्रेट अलकनंदा त्रासदी, कालियासौर भूस्खलन, शेरका



डांडा, स्नोडन भूस्खलन, गंगटोक-सिलीगुड़ी रोड भूस्खलन, मराप्पलम भूस्खलन, अंबूरी भूस्खलन, जाखला की त्रासदी, लाह गांव, भेटी-पौंडार भूस्खलन, फाटा-ब्युंग भूस्खलन, वरुणावत पर्वत भूस्खलन, मुनस्यारी भूस्खलन, कपकोट भूस्खलन, आइजोल भूस्खलन, केदारनाथ भूस्खलन, केरल बाढ़ से उत्पन्न भूस्खलन, चमोली झील में बादल फटने से आई बाढ़, किन्नौर भूस्खलन और भी बहुत कुछ शामिल हैं। भारत में भूस्खलन की गंभीरता और प्रमुख आपदाओं का दस्तावेजीकरण करने के आदेश को समझने के लिए, एनआईडीएम भूस्खलन जोखिम में कमी और समुत्थानशीलता के लिए हमारी भविष्य की रणनीतियों को मजबूत करने के लिए कुछ संग्रहीत घटनाओं को रिकॉर्ड करने का प्रयास करता है।

xii. भारतीय शहरों में जल संकट: एक प्रणालीगत विफलता या जलवायु का प्रकोप



प्रकाशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और चेन्नई के महानगरीय क्षेत्र में उभरते जल संकट पर ध्यान केंद्रित करने वाले दो केस अध्ययनों पर चर्चा की गई है, क्योंकि दोनों शहरों ने हाल के वर्षों में तीव्र जल संकट का सामना किया है, जिसने हाशिए पर रहने वाले समुदाय को असमान रूप से प्रभावित किया है। यह इस संबंध में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों पर भी प्रकाश डालता है। यह प्रकाशन डीएसटी द्वारा समर्थित सीएपी-आरईएस परियोजना के तहत लाया गया है और देश के भीतर बढ़ते जलवायु परिवर्तन और भूजल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और दोहन को देखते हुए यह काफी प्रासंगिक है। यह भारत के महानगरीय शहरों- चेन्नई और दिल्ली एनसीआर में जल संकट की स्थितियों पर केंद्रित है। यह अध्ययन सक्रिय शहरी प्रबंधन के लिए रोकथाम, शमन और तैयारी के उपाय सुझाता है।

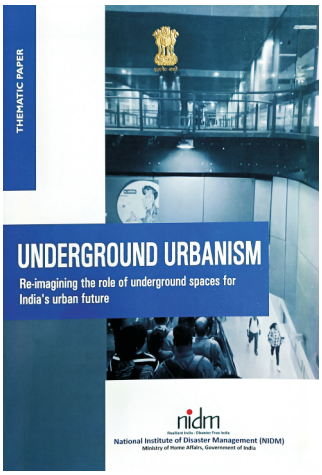


xiii. आपदा प्रबंधन में व्यापक दृष्टिकोण और भूमिका: कार्यान्वयन ढांचे की दिशा में पारंपरिक अवधारणाओं से बाहर निकलना

यह प्रकाशन आपदा प्रबंधन में व्यापक दृष्टिकोण के कार्यान्वयन की भूमिका और कार्यान्वयन ढांचे की दिशा में पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़ने पर केंद्रित है और इस विषय में केस अध्ययनों पर चर्चा करता है। यह पेपर आपदा प्रबंधन योजना में भूदृश्य दृष्टिकोण के प्रमुख पहलुओं को क्षेत्रीय योजनाओं में एकीकृत करके उजागर करने का प्रयास करता है। अध्ययन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के इर्द-गिर्द घूमता है। क) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए व्यापक दृष्टिकोण की प्रभावशीलता और ख) भूदृश्य दृष्टिकोण के प्रभावी कार्यान्वयन की विशेषताएँ।

xiv. भूमिगत शहरीकरण: भारत के शहरी भविष्य के लिए भूमिगत स्थानों की भूमिका की पुन: कल्पना

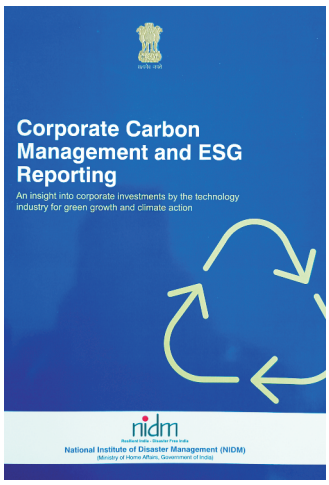
यह अध्ययन भूमिगत स्थानों की दुनिया में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह उस भूमिका पर प्रकाश डालता है जो ये स्थान निभा रहे हैं और दुनिया भर के उदाहरणों का उपयोग करके जलवायु प्रतिक्रिया और सतत् विकास में निभा सकते हैं। यह मानव



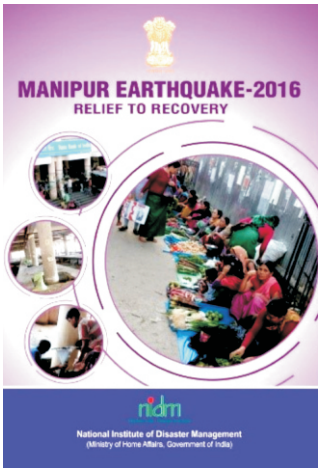
गतिविधियों और आवास के लिए उपसतह स्थानिक विकास की संभावनाओं का पता लगाने का एक प्रयास है और यह समझने की कोशिश करता है कि भूमिगत शहरीकरण एक टिकाऊ, समुत्थानशील और समावेशी भविष्य के लिए हर तरह से स्थानिक विकास का एक प्रभावी विकल्प कैसे हो सकता है। यह पेपर भारत पर विशेष ध्यान देने के साथ भूमिगत स्थानों के उपयोग के लिए प्रमुख नीति और शासन की चुनौतियों और अवसरों पर भी प्रकाश डालता है।

xv. कॉरपोरेट कार्बन प्रबंधन और ईएसजी रिपोर्टिंग: हरित विकास और जलवायु क्रियाशीलता के लिए तकनीकी उद्योग द्वारा कॉरपोरेट निवेश में एक अंतर्दृष्टि

यह अध्ययन कॉरपोरेट ईएसजी रिपोर्टिंग और कॉरपोरेट कार्बन प्रबंधन की दुनिया में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह प्रौद्योगिकी उद्योग में विश्व प्रसिद्ध कंपनियों में से पांच के उदाहरणों का उपयोग करके जलवायु क्रियाशीलता और हरित विकास में कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसे पूरा करने के लिए, कार्बन कटौती और हटाने की दिशा में कॉरपोरेट निवेश के पैमाने और दायरे के महत्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता है क्योंकि कार्बन प्रबंधन वैश्विक प्रभावों को बढ़ाने और शुरू करने के लिए व्यापक अवसर प्रदान कर सकता है। इस प्रकाशन ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ ईएसजी रिपोर्टिंग के एक घटक के रूप में कॉरपोरेट कार्बन प्रदर्शन का विश्लेषण करने की कोशिश करके परियोजना में योगदान दिया है।

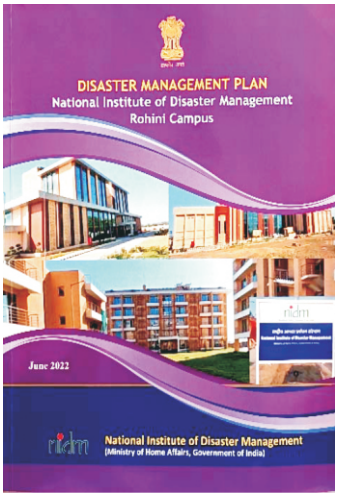


xvi. मणिपुर भूकंप–2016 राहत से पुनर्निर्माण की ओर



'मणिपुर भूकंप–2016: राहत से पुनर्निर्माण की ओर' को भूकंप के प्रभाव और उससे हुई क्षति के पैटर्न को एकत्रित करने और समझने के लिए लिखा गया है, जो भविष्य में बेहतर और मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करेगा। दस्तावेज में 2016 की घटना को विस्तार से शामिल किया गया है, जो प्रभाव से लेकर बचाव, राहत और पुनर्निर्माण तक और प्रभावित क्षेत्रों में संरचनाओं के नुकसान के आकलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें क्षति के कुछ प्रमुख मुद्दों और कारणों पर चर्चा की गई है, साथ ही आपदा के बाद शुरू की गई अच्छी प्रथाओं पर भी चर्चा की गई है, जिसमें रेट्रोफिटिंग उपाय और आगे की रूपरेखा शामिल है। वर्तमान रिपोर्ट डीआरआर पर माननीय प्रधान मंत्री के 10–सूत्रीय एजेंडे को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, जो बिंदु संख्या 9 के अनुसार, 'यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित करता है कि किसी आपदा से सीखने का अवसर बर्बाद न हो और देश में प्रमुख आपदाओं से सीख का दस्तावेजीकरण किया जाए।

xvii. आपदा प्रबंधन योजना



हाल के वर्षों में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से प्रेरणा लेते हुए, एनआईडीएम सभी स्तरों पर डीआरआर/डीआरएम को संस्थागत बनाने पर अधिक ध्यान दे रहा है। इस संदर्भ में, एनआईडीएम ने इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समिति द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद अपने रोहिणी परिसर के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है। एनआईडीएम के आपदा प्रबंधन योजना दस्तावेज में एनआईडीएम की उत्पत्ति, प्रचलित खतरों, कमजोरियों और क्षमताओं के बारे में जानकारी शामिल है। उपलब्ध जानकारी के विश्लेषण के आधार पर, खतरों से उत्पन्न स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारी, शमन और प्रतिक्रिया रणनीतियां प्रस्तावित की गई हैं। एनआईडीएम डीएम योजना तैयार करते समय एक व्यापक, समग्र और बहु-जोखिम दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह योजना दस्तावेज एनआईडीएम परिसर को एक आपदा प्रतिरोधी इकाई बनाने की दिशा में उनके प्रयासों और पहलों में सभी संबंधित हितधारकों की मदद करेगा और रोहिणी परिसर के निवासियोंध्नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करेगा।

एनआईडीएम जर्नल आपदा एवं विकास

i. आपदा एवं विकास जनवरी से जून 2022 (खण्ड 11, अंक 1)



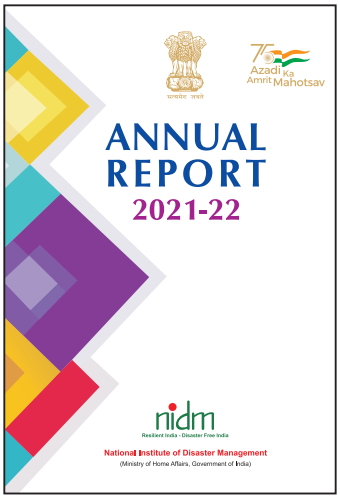
संस्थान ''आपदा एवं विकास जर्नल'' शीर्षक से एक द्वि-वार्षिक जर्नल प्रकाशित करता है। पत्रिका का पहला अंक 29 नवंबर 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रथम भारत आपदा प्रबंधन कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा जारी किया गया था। 2022 में, डिजास्टर एंड डेवलपमेंट जर्नल को यूजीसी-केयर इंडेक्सिंग प्राप्त हुई। यह अंक विभिन्न विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाले शोधों को शामिल करता है जैसे खतरे, संकट, क्षमता एवं आपदाओं का अध्ययन; आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं समुत्थानशीलता (डीआरआरएंडआर): आपदाओं के प्रभाव और उन पर प्रतिक्रिया; आपदा के बाद पुर्नप्राप्ति; समुदाय आधारित पर्यावरण, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और सुरक्षित सतत् विकास ।

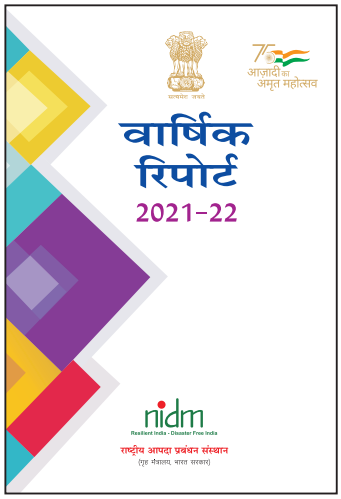


ii. आपदा एवं विकास जुलाई से दिसंबर 2022 (खण्ड 11, अंक 2)

इस अंक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं समुत्थानशीलता (डीआरआरएंडआर) के सभी पहलुओं पर शोध कार्य शामिल है जो पाठकों को प्राकृतिक खतरों, सम्बन्धित जोखिमों, तैयारियों, रोकथाम और शमन उपायों के बारे में उनकी समझ एवं ज्ञान बढ़ाने में मदद करेगी, ताकि आपदाओं में जान-माल की हानि नहीं हो और समुत्थानशील भारत का निर्माण हो ।

वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी (2021–22)

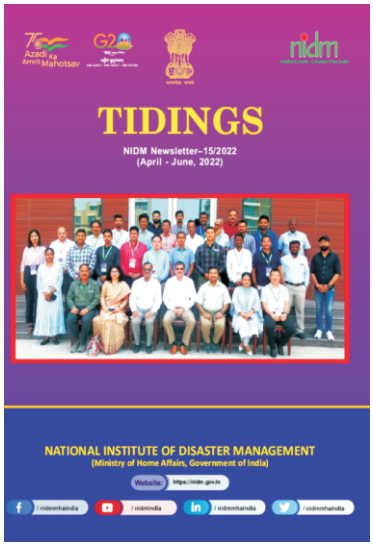


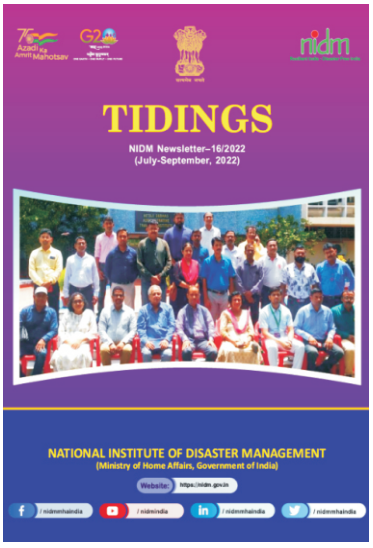


वर्ष 2021–22 के लिए एनआईडीएम की वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में संस्थान के दृष्टिकोण, मिशन, जनादेश, संरचना, कार्यों और प्रमुख उपलब्धियों का विवरण शामिल है। रिपोर्ट को आठ अध्यायों में संरचित किया गया है। अवलोकन, संगठनात्मक सेटअप, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परियोजनाएं, ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता गतिविधियां, आयोजित प्रमुख कार्यक्रम/कार्यशाला/सम्मेलन/सेमिनार और आउटरीच गतिविधियां, वित्त और लेखा; प्रशिक्षण/प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षण के प्रकार आदि के संदर्भ में गतिविधियों और प्राप्त प्रगति को सूचीबद्ध करने के अलावा। भौगोलिक, टाइपोलॉजिकल और अस्थायी रुझानों को दर्शाने के लिए उपलब्धियों को मानचित्र, चार्ट और आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पाँच अनुलग्नक हैं जिनमें एनआईडीएम और ऑफ–कैंपस में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत सूची, शासी निकाय एनआईडीएम के सदस्यों की सूची आदि शामिल हैं।

समाचार पत्रिका "टाइडिंग्स''

एनआईडीएम की समाचार पत्रिका "टाइडिंग्स'' एक त्रैमासिक प्रकाशन है। यह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं की सिफारिशों पर प्रकाश डालता है, जो एनआईडीएम द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर अग्रिम जानकारी देने के अलावा, इस समाचार पत्रिका में संकाय विकास, सफलता की कहानियों, यात्राओं और प्रतिनिधिमंडलों आदि के बारे में समाचार शामिल किए जाते हैं।







*****

अध्याय 6

कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन/आमने-सामने कार्यक्रम

कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन/आमने–सामने कार्यक्रम

6.1 प्रधानमंत्री के दस सूत्री कार्यक्रम के एजेंडा नंबर 1 और 8: आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता के लिए क्षमता वृद्धि पर कार्यशाला, 20–21 अप्रैल 2022

आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रतिरोध पर ज्ञान/सूचना साझा करने और समुदाय की क्षमता वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए डाक सेवा के अधिकारियों के लिए रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विकास परियोजनाओं और आवर्ती आपदाओं के शमन और प्रबंधन के लिए समाधान विकसित करना था। इसने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तंत्र को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया।

6.2 जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला, 01 जून 2022



कार्यशाला देहरादून, उत्तराखंड में आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन के बारे में सलाहकारों को अवगत कराना था। प्रभावी परामर्श के लिए रणनीतियों को साझा करने के अलावा, इसे एक संरक्षक की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए संरचित किया गया था। कार्यशाला में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि क्षमता निर्माण और सिस्टम को मजबूत करने में सलाहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सुझाव दिया गया कि उत्तराखंड राज्य क्षमता बढ़ाने और सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक मॉडल विकसित कर सकता है। समीक्षा के आधार पर, इसे सर्वोत्तम प्रथाओं के रूप में प्रलेखित किया जा सकता है और अन्य राज्यों के साथ साझा किया जा सकता है।

6.3 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यशाला, 27–28 जून 2022



अभिविन्यास कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं को संवेदनशील बनाना और डिजाइन करना था। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना से परिचित कराना था। प्रो. संतोष कुमार ने इस बात पर जोर

दिया कि सतत् विकास लक्ष्य उनकी चिंता का प्रमुख केंद्र बिंदु है। उन्होंने कार्यशाला में आपदा प्रबंधन योजना के प्रारूप और क्रियान्वयन के साथ-साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व की चर्चा पर जोर दिया। कार्यशाला में डीआरआर पर सेंडाई फ्रेमवर्क और पीएम 10 प्वाइंट एजेंडा की व्यापक समझ पर चर्चा की गई।

6.4 रासायनिक आपात स्थितियों के जन स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला, 30 जून-01 जुलाई 2022

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), दिल्ली द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारतीय कार्यालय के सहयोग से ''रासायनिक आपात स्थितियों के जन स्वास्थ्य प्रबंधन'' पर एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। प्रतिभागियों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और रासायनिक आपात स्थितियों के प्रबंधन में लगे अन्य अधिकारी, पहली प्रतिक्रिया समूह, जैसे एसडीआरएफ के अधिकारी, अनुसंधान संगठनों जैसे डीआरडीई, आईसीएमआर-एनआईओ, चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विशेषज्ञ, और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और नियामक शामिल हैं। कार्यक्रम में कुल 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



6.5 राष्ट्रपति भवन के लिए संग्रहालयों और विरासत भवनों के आपदा प्रबंधन पर संवेदीकरण कार्यशाला, 07-08 जुलाई 2022

कार्यक्रम की शुरुआत जीआईडीआरआर डिवीजन के प्रमुख प्रोफेसर संतोष कुमार के स्वागत भाषण से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने वर्तमान समय में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत में सांस्कृतिक विविधता तक पहुंच और आनंद को बढ़ावा देने की क्षमता है।



इसके अलावा, उन्होंने सेंदाई फ्रेमवर्क पर चर्चा की, जिसका लक्ष्य कार्बन और अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, आपदा जोखिम में कमी के लिए शासन में सुधार करना है, जिसमें

नीतियां, योजनाएं, दिशा-निर्देश आदि शामिल हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर आपदा जोखिम का प्रबंधन करना है। इस कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक स्थल के भीतर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ढांचे के तहत सांस्कृतिक विरासत की विशिष्ट आवश्यकताओं को एकीकृत करना था। इसके बाद प्रतिभागियों को एक संक्षिप्त वृत्तचित्र दिखाया गया जो 2019 में चक्रवात फनी के आगमन से ओडिशा में मची तबाही के बाद जिंदगी सामान्य होने की कहानी बयां करता था। तूफान के कारण लाखों पेड़ उखड़ गये जिससे वनस्पति की मात्रा काफी कम हो गयी। हालाँकि लोगों को सकुशल निकाल लिया गया, लेकिन बड़ी मात्रा में बुनियादी ढाँचे बर्बाद हो गए। समापन सत्र में, राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव, श्री अजय भादू, आईएएस ने कहा कि यह कार्यशाला आपदा तैयारियों के संबंध में राष्ट्रपति भवन में जागरूकता पैदा करने के लिए आंखें खोलने वाली थी।

6.6 आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला, 21 जुलाई 2022

एनआईडीएम ने रफी अहमद किदवई नेशनल पोस्ट एकेडमी (आरएकेएनपीए), गाजियाबाद में आपदा प्रबंधन पर एक दिवसीय सहयोगात्मक कार्यशाला का प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. सूर्य प्रकाश, प्रोफेसर एवं प्रमुख, जीएमआरडी, एनआईडीएम और श्री अंबेश उपमन्यु, अतिरिक्त निदेशक, आरएकेएनपीए ने की। इसका आयोजन डाक सेवा के अधिकारियों के लिए समुदाय की क्षमता वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता पर ज्ञान/सूचना साझा करने और आदान-प्रदान करने के लिए किया गया था। प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहयोग और तंत्र को मजबूत करने पर भी सुझाव दिए।

6.7 एनआईडीएम-यूनिसेफ सहयोग के तहत सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन मॉड्यूल के टूलकिट के विकास के लिए विचार शिविर, 29 जुलाई 2022

यूनिसेफ के साथ साझेदारी में एनआईडीएम ने दिसंबर 2021 में 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार' पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ किया । डीआरआर पहल को और मजबूत करने और एनआईडीएम का समर्थन करने के लिए, प्रशिक्षण सहायता और आईईसी सामग्रियों से युक्त एक व्यापक टूलकिट विकसित किया जाएगा। इसे आगे बढ़ाने के लिए 29 जुलाई 2022 को हितधारकों के साथ निम्नलिखित उद्देश्य से एक विचार सत्र आयोजित किया गया था:

- एसबीसीसी प्रशिक्षण मॉड्यूल को साझा करना।
- संचार सामग्री की समीक्षा के निष्कर्षों और अनुशंसाओं को साझा करना।
- एसबीसी उपकरणों और सामग्रियों की एक सूची को अंतिम रूप देना जिन्हें प्रशिक्षण मॉड्यूल के पूरक के लिए विकसित करने की आवश्यकता है।

कार्यशाला में एनआईडीएम, यूनिसेफ, स्फीयर इंडिया, अखिल भारतीय आपदा शमन संस्थान (एआईडीएमआई), आईडीएसपी/एनसीडीसी और यूनिसेफ के तकनीकी भागीदार एनविजन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला की प्रमुख सिफारिशें प्राथमिक रूप में 5 आपदाओं - भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और जनस्वास्थ्य आपातकाल पर केंद्रित रही ।

6.8 आपदा जोखिमों को कम करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान के रूप में आर्द्रभूमि पर कार्यशाला, 12-13 सितंबर 2022



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू क,म्बैट डेजर्टिफिकेशन के सहयोग से आपदा प्रबंधन योजनाओं के भीतर एकीकरण के लिए एनबीएस की समझ बनाने के लिए दो दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला के संयोजक प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता, इसीडीआरएम प्रभाग, एनआईडीएम और डॉ. रितेश कुमार, निदेशक, वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया थे। कार्यशाला का उद्देश्य इस दृष्टिकोण की अवधारणाओं और सिद्धांतों पर आपदा पेशेवरों को शिक्षित करने और केंद्रीय और राज्य स्तर की नीतियों, योजनाओं और योजनाओं को पहचानने की तत्काल आवश्यकता के लिए एनबीएस कॉल को मुख्यधारा में लाना था जो अभिसरण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

6.9 भारत के लिए जलवायु जोखिम मूल्यांकन दृष्टिकोण पर विशेषज्ञ वार्ता, 14 सितंबर 2022



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में जलवायु जोखिम आकलन (सीआरए) के संचालन में अनुभव के आदान-प्रदान को सक्षम बनाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जो सार्वजनिक और निजी हितधारकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करता है। कार्यशाला ने समानताओं और भिन्नताओं, अंतरालों और सीमाओं पर प्रकाश डाला और सीआरए विधियों और उपकरणों के अनुप्रयोग को मजबूत करने के साधनों की सिफारिश की। प्रतिष्ठित संगठनों के सीईओ, आईआईटी के प्रोफेसर, संयुक्त राष्ट्र संगठनों के क्षेत्र विशेषज्ञों और अन्य द्विपक्षीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

6.10 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डीएम सेल के लिए डीएम योजना की तैयारी, 22 सितंबर 2022

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030), जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, सभी विकास क्षेत्रों में जोखिमों की पहचान करने और उनका मानचित्रण करने पर केंद्रित है। भारत एक बहु-खतरा प्रवण देश है और अक्सर विभिन्न खतरों से प्रभावित होता है और इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य और जिला स्तर पर बेहतर प्रशासन में योगदान देने वाली क्षमताओं का निर्माण करके जीवन में आसानी हासिल की जा सकती है। एक आपदा प्रतिरोधी राष्ट्र बनने के लिए भौतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक कारकों से होने वाले नुकसान को कम करना अनिवार्य है। भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की डीआरआर एजेंडा को बढ़ावा देने और लागू करने में प्रमुख भूमिका है, सभी केंद्रीय मंत्रालयों और संबंधित विभागों की आपदा प्रबंधन योजना प्रणालीगत तरीकों से जोखिम मूल्यांकन, रोकथाम-शमन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, क्षमता और पुनर्प्राप्ति संसाधनों के लिए रणनीतिक और योजनाबद्ध दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है।

इस संदर्भ में, 21 सितंबर 2022 को एनडीएमए और एनआईडीएम द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के निर्माण भवन स्थित आपदा प्रबंधन सेल में एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

यह एजेंडा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आपदा प्रबंधन सेल के सदस्यों को अपनी स्वयं की डीएम योजना विकसित करने के लिए उन्मुख करना था। डीएम योजना की आगे की तैयारी के लिए अध्यायों की प्रस्तावित रूपरेखा के साथ एक विस्तृत आपदा प्रबंधन (डीएम) टेम्पलेट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम के साथ साझा किया गया था। इस कार्यशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आपदा प्रबंधन सेल के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

6.11 बाढ़ आपदाओं के विशेष संदर्भ में नाव और नौवहन सुरक्षा पर कार्यशाला, 10–12 अक्टूबर 2022

एनआईडीएम और आईडब्ल्यूएआई, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की एक संयुक्त पहल पर भारत के राष्ट्रीय अंतर्देशीय नेविगेशन संस्थान (एनआईएनआई), पटना में 10–12 अक्टूबर 2022 तक ''जल–मौसम संबंधी आपदाओं के विशेष संदर्भ में नाव और नेविगेशनल सुरक्षा'' पर तीन दिवसीय आमने–सामने कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सभी अंतर्देशीय जलमार्गों को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए मौजूदा आपदा प्रबंधन प्रणाली/योजना में शामिल करने की सिफारिशें की गई। कैप्टन महेंद्र कुमार, हाइड्रोग्राफिक चीफ, आईडब्ल्यूएआई और डॉ. रजनीश रंजन, सीनियर कंसल्टेंट, एनआईडीएम ने उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रख्यात वक्ता डॉ. रजनीश रंजन, एनआईडीएम, नई दिल्ली; कैप्टन इंद्रवीर सोलंकी, एम.डी. स्प्रिंग प्रोफेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड; कैप्टन अश्विन सोलंकी, मुख्य समुद्री अधिकारी, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, और श्री विवेक सिन्हा, आईएमडी शामिल थे।





6.12 जोखिम कम करने और समुत्थानशीलता बनाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला: पर्वतीय राज्यों में क्षमता निर्माण, 20–21 अक्टूबर 2022

मौजूदा तंत्र को मजबूत करने और आपदा जोखिम में कमी के लिए हिमालयी राज्यों के भीतर क्षमता निर्माण के लिए, डॉ. आर.एस.टी. उत्तराखंड प्रशासन अकादमी (आरएसटीयूएओए) में एक राष्ट्रीय कार्यशाला, ''जोखिम कम करना और समुत्थानशील बनाना: पर्वतीय राज्यों में क्षमता निर्माण'' मेजबान संस्था एवं एनआईडीएम, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के संयुक्त प्रयास से 20 से 21 अक्टूबर 2022 तक नैनीताल में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 300 से अधिक प्रतिभागियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, गैर–सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों के प्रतिनिधियों और



उत्तराखंड राज्य के जिला स्तर के कार्यालयों से जमीनी स्तर के हितधारकों ने भाग लिया और योगदान दिया। कार्यशाला के व्यापक विषय पर दो दिनों तक विभिन्न तकनीकी और पूर्ण सत्रों में चर्चा की गई और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों और कार्य योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया जो राष्ट्रीय डीआरआर रणनीतियों और सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ संरेखित हैं।

6.13 डीआरआर क्षमता निर्माण परामर्श कार्यशाला में प्रशिक्षक विकास (टीओटी) रणनीति, 02 नवंबर 2022

आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता निर्माण परामर्श कार्यशाला एनआईडीएम, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और प्रस्तावित पूर्ण प्रशिक्षण अकादमी के साथ इसे मुख्य उद्देश्य के रूप में टीओटी के साथ जोड़ा गया था। टीओटी में शामिल करने के लिए सरकारी प्रणाली के बाहर से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को जोड़ने और अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में उन्हें प्रशिक्षण बैच आवंटित करने में नीति और संसाधनों के मुद्दों पर चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में टीओटी (प्रशिक्षक विकास) के लिए एक रणनीतिक कार्य योजना विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था। कार्यक्रम में कुल 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6.14 जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) पर राष्ट्रीय सम्मेलन, 05 दिसंबर 2022

श्री अजय कुमार मिश्रा, माननीय राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने जन स्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) और अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के सहयोग से आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य पीएचईडीएम को समझने के लिए सूचना, ज्ञान और नवाचार के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना और क्षेत्र में हाल की प्रगति का पता लगाना है। सम्मेलन के दौरान दो दस्तावेज, जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण पैकेज-व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम-पीडीपी)-टियर II (प्रतिभागी और सुविधाकर्ता गाइड) और पीएचईडीएम पर साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला की सारांश रिपोर्ट लॉन्च की गई।





सम्मेलन की चर्चाओं में आपात स्थितियों और आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए साक्ष्य-आधारित, जन-केंद्रित, संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। चर्चा के दौरान अभूतपूर्व घटनाओं से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया गया। विचार-विमर्श में माननीय प्रधानमंत्री के दस सूत्री एजेंडे पर भी जोर दिया गया

और सुरक्षित, टिकाऊ और समुत्थानशील भविष्य के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेजीकरण और पिछली घटनाओं से सीखने को प्रोत्साहित किया गया।

कुल मिलाकर, पीएचईडीएम पर राष्ट्रीय सम्मेलन भारत की जी20 प्रेसीडेंसी की थीम, 'वसुधैव कुटुंबकम' या 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने नीति निर्माताओं, अभ्यासकर्ताओं और हितधारकों को एक साथ आने, अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने और एक सुरक्षित और अधिक समुत्थानशील भविष्य की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया।

राष्ट्रीय सम्मेलन से आगे बढ़ने का एक प्रमुख तरीका यह था कि एनआईडीएम-एनसीडीसी-सीडीसी को अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने के अलावा कर्मचारियों और प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समुदाय से लेकर नीति निर्माताओं के स्तर तक अपने संयुक्त हस्तक्षेप और पहल जारी रखनी चाहिए।

6.15 भूकंपीय माइक्रो-जोनेशन जोखिम विश्लेषण और आपदा न्यूनीकरण प्रक्रियाओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 19 जनवरी 2023

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और सिविल इंजीनियरिंग विभाग, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) ने संयुक्त रूप से 19 जनवरी, 2023 को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया के सभागार में ''भूकंपीय माइक्रोजोनेशन और आपदा शमन'' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक श्री ताज हसन (आईपीएस) थे और मुख्य अतिथि प्रोफेसर इकबाल एच. खान, संस्थापक डीन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय, जामिया थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सेमिनार के संयोजक प्रोफेसर गौहर महमूद ने की। उन्होंने माइक्रो जोनेशन की अवधारणा को संक्षेप में समझाया और ऐसे सेमिनारों के महत्व पर प्रकाश डाला।



- सेमिनार के दौरान भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीकरण और शहरी संदर्भ में भूकंपीय जोखिम शमन पर दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। सेमिनार में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से कुछ चयनित छात्रों/विद्वानों ने सेमिनार के विषय पर आधारित अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

6.16 अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम एवं संवेदनशीलता सम्मेलन 2023 (डीआरवीसी 2023), 19-21 जनवरी 2023

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल द्वारा आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, आपदा, जोखिम और संवेदनशीलता सम्मेलन 2023 (डीवीआरसी 2023) ने 19-21 जनवरी 2023 तक 5वें आपदा जोखिम और भेद्यता सम्मेलन की मेजबानी की और यह आपदा से निपटने के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञ सुझावों को एकत्रित और शामिल करके विश्वविद्यालय स्तर पर आपदा शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए आदर्श स्थान था।

सम्मेलन ने आपदा प्रबंधन के विविध पहलुओं पर काम करने वाले विशेषज्ञों को एक साथ लाया। चर्चाओं और विचार-मंथन सत्रों में शमन के लिए सुझावों के बारे में बताया गया जो भारतीय आपदा प्रबंधन नीति निर्माण पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं।

तीन दिवसीय सम्मेलन में 8 मुख्य भाषणों, 2 पूर्ण वार्ताओं, 1 आमंत्रित वार्ता और 63 पेपर प्रस्तुतियों प्रस्तुत की गई। डीआरवीसी 2023 में कुल 96 पंजीकृत प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें सरकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, अनुसंधान विद्वानों और छात्र समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे। इन सम्मेलन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा विदेश से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

6.17 आपदा के दौरान आपातकाल, आघात एवं गंभीर देखरेख की चुनौतियाँ और नवीनता (एनसीएनसीओएन-2023), 27-28 जनवरी 2023



तीसरे पीजीआईएमईआर नेशनल क्रिटिकल केयर नर्सिंग कॉन्फ्रेंस (एनसीएनसीओएन 2023) का आयोजन सोसाइटी फॉर क्रिटिकल केयर नर्सिंग और सोसाइटी फॉर इमरजेंसी, ट्रॉमा एंड डिजास्टर द्वारा एनआईडीएम, गृह मंत्रालय की अकादमिक साझेदारी के साथ 27-28 जनवरी 2023 को पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के भार्गव सभागार में किया गया था। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण आपदा तैयारी/शमन, नैदानिक विषय और अधिक प्रकार की निरंतर नर्सिंग शिक्षा और प्रतिभागियों को प्रदान की जाने वाली व्यावहारिक कार्यशाला शामिल थी। सम्मेलन में नर्सों, नर्सिंग विद्वानों, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स सहित हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया

6.18 औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन पर सम्मेलन और पुरस्कार, 28 फरवरी 2023



औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन और फिक्की-जीआईजेड पुरस्कार समारोह पर सम्मेलन 28 फरवरी 2023 को फिक्की-इंडिया और जीआईजेड के सहयोग से औद्योगिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के समुत्थानशीलता और साइबर जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ एनआईडीएम के औद्योगिक और साइबर डीआरआर एंड आर डिवीजन सीबीआरएन द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन ने उद्योगों को अपने अनुभवों और उद्योगों में समुत्थानशीलता को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।









6.19 स्कूल सुरक्षा पर कार्यशाला: चुनौतियाँ और आगे की राह, 1–2 मार्च 2023

विज्ञानप्रसार, नोएडा के सहयोग से एनआईडीएम द्वारा 'स्कूल सुरक्षा' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल 50 शिक्षकों और प्राचार्यों ने भाग लिया। कार्यशाला में स्कूल आपदा प्रबंधन योजना के विकास के साथ-साथ खतरा, जोखिम, विषम परिस्थिति और क्षमता विश्लेषण करने के लिए प्रतिभागियों के बीच कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों को खतरों को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन किट और अग्निशामक यंत्रों को बनाए रखने के बारे में भी जागरूक किया गया।



6.20 आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला, 15–16 मार्च 2023

एनआईडीएम द्वारा रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सहयोग से आपदा प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत आपदा प्रबंधन संस्थागत और कानूनी ढांचे के साथ-साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता की बुनियादी अवधारणाओं पर व्याख्या के साथ हुई। कार्यक्रम में बहु-खतरे की पूर्व चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता, विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए सुरक्षा और तैयारी के उपाय, अग्नि सुरक्षा और अग्नि शमन प्रदर्शन पर सत्र शामिल थे। प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल पाउडर आदि चलाना भी सिखाया गया।



6.21 आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. एसएफडीआरआर, एसडीजी और सीसीए के एकीकरण और मुख्यधारा में लाने के लिए क्षमता वृद्धि पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)/आपदा पश्चात तैयारी (पीडीपी), 04-08 अप्रैल 2022, भोपाल

मुख्य बातें/सिफारिशें



क. सतत् विकास (एसडी), आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) के लिए समर्पित तीन प्रमुख वैश्विक ढांचे की शुरुआत के साथ दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। नीति संक्षेप उन दृष्टिकोणों की पहचान करता है जो प्रोग्रामेटिक एकीकरण, सहयोग, क्षमता निर्माण और नवाचार के माध्यम से जमीन पर तीन प्रमुख वैश्विक ढांचे को लागू करने में बेहतर तालमेल हासिल करने में मदद कर सकते हैं।

ख. जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को अधिकतम करने के लिए अब सभी संबंधित हितधारकों से समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

ग. राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक पहलू कई देशों में सतत् विकास की कुंजी है-डीआरआर और सीसीए पर्यावरणीय अखंडता से समझौता किए बिना या आपदा जोखिम को बढ़ाए बिना अधिकांश विकासशील और कम विकसित देशों के आर्थिक विकास उद्देश्यों में सहायता कर सकते हैं।

घ. स्थानीय स्तर पर, स्थायी विकास (SD), आपदा जोखिम में कमी (DRR) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) के बीच मजबूत समन्वय संबंधित हितधारकों के बीच बड़े स्तर पर सहयोग की मांग उत्पन्न करता है। इसके लिए अनुकूलन प्रबंधन के माध्यम से संयुक्त योजना और नीतियों के निर्माण के साथ ही वास्तविक कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए भी सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय सरकारें, स्थानीय विशेषज्ञ, गैर-सरकारी संगठन और व्यापार क्षेत्रों के बीच सहयोग के माध्यम से सही नीतियों और क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

2. जिलास्तरीय योजनाओं में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, 04-08 अप्रैल 2022, डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ

मुख्य बातें/सिफारिशें



क. विकास योजना में सीसीए और डीआरआर को शामिल करने के तरीकों और दृष्टिकोणों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने सीखा कि प्रत्येक विभाग को अपने लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

ख. आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के लिए कानूनी नीति ढांचे को प्रतिभागियों ने अच्छी तरह से समझा।

ग. विकास योजनाओं और परियोजनाओं में डीआरआर को शामिल करने पर भी चर्चा की गई। क्षेत्र दौरे के दौरान इसका व्यावहारिक मूल्यांकन किया गया और प्रतिभागियों द्वारा इसे बखूबी समझा गया।

घ. वर्तमान परिदृश्य में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर मौजूदा योजनाओं/परियोजनाओं से सबक सीखा गया।

ङ. प्रतिभागियों द्वारा उचित और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ स्थानीय अनुकूलन प्रथाओं के माध्यम से जोखिम कम करने के क्षेत्र में सबक सीखा गया।

च. प्रतिभागी सेंदाई ढांचे और उसके एजेंडे को समझने में सक्षम रहे।

छ. प्रतिभागी व्यावहारिक उदाहरणों के साथ खतरे, जोखिम, भेद्यता और क्षमता विश्लेषण अवधारणाओं, उपकरणों और तकनीकों को समझने में कामयाब रहे।

3. आपदा पश्चात आवश्यकताओं का आकलन और दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)/आपदा पश्चात तैयारी (पीडीपी), 04-08 अप्रैल 2022, ओएसडीएमए, एनआईडीएम

मुख्य बातें/सिफारिशें

क. जब आपदा के बाद मूल्यांकन की आवश्यकता (पीडीएनए)आयोजित की जाती है तो सामाजिक क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।



ख. आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति में छात्रों के बीच सीखने की निरंतरता के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के प्रावधानों पर जोर दिया गया।

ग. आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 के बाद के विकास एजेंडे का पहला प्रमुख समझौता थाजो सदस्य राज्यों के विकास लाभ को आपदा के जोखिम से बचाने के लिए ठोस कार्रवाई प्रदान करता है।

घ. बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और समुत्थानशीलता की आवश्यकता पर जोर देना।

ङ. भारत को पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हैऔर सरकार को त्वरित और समग्र पुनर्वास और आपदा प्रतिरोधी पुनर्निर्माण को प्राप्त करने में अधिक प्रयास करना चाहिए।

च. छोटे देशों या छोटी आपदाओं के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक उपयुक्त हो सकती है।

छ. जब सामाजिक क्षेत्र की बात आती है, तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, वह है लक्षित जनसंख्या की आयुय जो उन्हें टीकाकरण और शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देती हैय फिर भी, संकट काल में ऐसे अवसर अवसरों का विचार नहीं किया जाता है।

4. शहरी समुत्थानशीलता के लिए शमन उपायों को समझने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण-नागरिक सुरक्षा की भूमिका, 05-09 अप्रैल 2022, डीडीएमए, दिल्ली

मुख्य बातें/सिफारिशें

क. सामुदायिक स्तर पर कमजोर आपदा प्रबंधन के पीछे कारण और कैसे नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक (सीडीवी) कार्यात्मक

और क्षेत्रीय जिम्मेदारियों के लिए संसाधन व्यक्ति हो सकते हैं।



ख. युद्धों के दौरान राष्ट्रीय आपात स्थितियों से लेकर हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान में अग्रिम पंक्ति के सामुदायिक योद्धाओं तक में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक (सीडीवी) की भूमिका।

ग. दिल्ली के संदर्भ में शहरी समुत्थानशीलता।

घ. समुदाय को खतरे, जोखिम और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करने के लिए ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाएं और स्कूल आपदा प्रबंधन योजनाएं विकसित करें।

ङ. अनर्धिंत निर्माण, बेतरतीब स्थानीय योजना और बढ़ती जनसंख्या जैसी सामाजिक कमजोरियों पर चर्चा

च. शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित करने में मुद्दों और चुनौतियों पर प्रशिक्षक के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा।

छ. शहरी पर्यावरण और आपदा जोखिम (प्रदूषण, जलभराव, परिवहन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) और शमन उपायों की पहचान करना।

ज. स्थायी प्रथाओं पर ध्यान देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर महिलाओं और नेतृत्व में सुधार के उपायों के साथ महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

5. बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम विजयवाड़ा, 18-22 अप्रैल 2022, राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परिषद्

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें / श्वसन स्वच्छता बनाए रखें / बार-बार और अच्छी तरह से हाथ धोएं।

ख) मास्क पहनने से किसी भी संभावित संक्रामक श्वसन बूंदों को रोकने में मदद मिलती है जो सांस लेने, बात करने या खांसने के दौरान निकल सकती हैं-खासकर जब सामाजिक दूरी बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो और भले ही व्यक्ति को अभी तक पता न हो कि वे बीमार हैं।

ग) सतहों पर रहने वाले नोवेल कोरोना वायरस को आगे फैलने से रोकने के लिए बार-बार छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणु रहित करें।



घ) सामाजिक दूरी को बढ़ावा देना (एक शब्द जो अत्यधिक संक्रामक बीमारी के प्रसार को धीमा करने के लिए किए जाने वाले कुछ कार्यों पर लागू होता है, जिसमें लोगों के बड़े समूहों को एक साथ आने तक सीमित करना भी शामिल है)।

ङ) कोरोनोवायरस बीमारी (कोविड-19) के बारे में बुनियादी जानकारी को समझें, जिसमें इसके लक्षण, जटिलताएं, यह कैसे फैलता है और ट्रांसमिशन को कैसे रोका जाए।

च) यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह जैसे प्रतिष्ठित स्रोतों के माध्यम से कोवड-19 के बारे में सूचित रहें।

छ) ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट प्रसारित न करें जिनमें असत्यापित या नकारात्मक जानकारी हो/विश्वसनीय स्रोतों से कोविड-19 पर जानकारी मांगें। किसी भी तनाव या चिंता के लिए मनोसामाजिक सहायता लें।

ज) खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से टीका लगवाना सबसे अच्छे उपायों में से एक है।

झ) कोविड-19 के प्रकोप के समय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना आवश्यक है।

ण) आपदा के बाद की स्थिति से लड़ने के लिए पुनर्निर्माण, पुनर्प्राप्ति, प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक तरीके प्रदान करना

6. आपदा प्रबंधन योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ एकीकृत करना, 25-27 मई 2022, यूआईआरडी, रुद्रपुर, उत्तराखंड

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) जवाबदेह प्राधिकरणों के साथ सूक्ष्म स्तरीय योजना आपदाओं में अत्यधिक महत्व रखती है।

ख) आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले कुछ उपकरणों/आकलन के लिए बुनियादी अवधारणाओं और कार्यप्रणाली की उचित समझ की आवश्यकता हो सकती है। सूक्ष्म ब्लॉक स्तर के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

ग) प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं को समझने से एक आम आदमी को भी मजबूत, आपदा प्रतिरोधी और सुरक्षित घरों के बारे में राजमिस्त्री से सवाल पूछने में मदद मिल सकती है।



घ) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) एक ही ब,क्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। जबकि डीआरआर पहलुओं का उपयोग आपदा-पूर्व परिदृश्य में किया जा सकता है, डीआरएम का उपयोग आपदा के बाद में किया जाता है। भारत में, दशकों से, मुख्य रूप से आपदा के बाद के परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है और वर्तमान में भी आपदा पूर्व (डीआरआर) पहलुओं पर काम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ङ) किसी भी आपदा परिदृश्य में खतरा-जोखिम-संवेदनशीलता और क्षमता का आकलन, सबसे उपयोगी और सुलभ समाधान तैयार करने में तेजी से मदद करता है और साथ ही डीआरआर पहलुओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाता है।

च) स्थलाकृति, पारिस्थितिकी और संस्कृति के संदर्भ में भारत की विविधता विशिष्ट स्थानों और समुदायों के लिए विशेष समाधान की मांग करती है। एक ग्राम विकास प्रबंधन योजना गांवों में समुदायों को समाधान तैयार करने और आपात स्थिति के दौरान उनका पालन करने की सुविधा प्रदान करती है।

7. दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण रणनीतियाँ, 30 मई–03 जून 2022, एमएसडीएमए, मेघालय

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र V के अंतर्गत आता है, जिससे यह मध्यम से बहुत उच्च तीव्रता के भूकंप के लिए संवेदनशील है और 8.0 से अधिक तीव्रता के भूकंप के लिए संवेदनशील माना जाता है।

ख) शिलांग पठार पर गुरुत्वाकर्षण विसंगति इसके परिवेश की तुलना में विशिष्ट रूप से सकारात्मक (40 एमजीएल) है, जो इसे पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र का सबसे असामान्य हिस्सा बनाती है।

ग) वैज्ञानिक प्रकाशनों ने चेतावनी दी है कि हिमालय क्षेत्र में कभी भी बहुत गंभीर भूकंप आने की संभावना है, जो भारत में कई मिलियन लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

घ) वैश्विक भूकंपीय खतरा आकलन कार्यक्रम के अनुसार, असम–मेघालय की सीमा पर 0.24g से 0.48g तक उच्चतम शिखर गुरुत्वाकर्षण त्वरण (पीजीए) की उम्मीद की जा सकती है– जो 1897 में आए भारत का विध्वंसकारी भूकंपीय क्षेत्र रहा है।



ङ) भूकंप के पैटर्न का पता लगाने के लिए बहुत सारे डेटा संग्रह और डेटा माइनिंग की आवश्यकता होती है। पूर्ववर्तियों के अवलोकन में निरंतर सफलता का अभाव रहा है।

च) भूकंप से होने वाले नुकसान को रोकने या कम करने में पूर्वानुमान सहायक नहीं हो सकता है क्योंकि इमारतों और अन्य संरचनाओं को खाली नहीं किया जा सकता है। यह अधिक से अधिक मानव जीवन बचाने में सहायक हो सकता है। इसके बावजूद पूर्वानुमान को संभव बनाने की कोशिशें जारी हैं.

छ) आपदा प्रबंधन पहलुओं पर काम करते समय बहु–खतरनाक –ष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

ज) निर्माण, पुनर्निर्माण राज्य के भीतर मौजूद स्थलाकृति, लिथोल,जी, कमजोरियों और क्षमताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए।

झ) यदि वृद्धि और विकास का उचित मूल्यांकन, निगरानी और योजना नहीं बनाई गई तो यह राष्ट्र के आपदा जोखिमों को बढ़ा सकता है।

ण) 'आपदा प्रबंधन' के संदर्भ में कार्यों की मुख्यधारा को एक अंतर–अनुशासनात्मक प्रयास के रूप में लिया जाना चाहिए।

8. व्यापक आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, 06–10 जून 2022, भूमि और आपदा प्रबंधन संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) जोखिम संवेदनशीलता विश्लेषण व्यवस्थित रूप से उस क्षति का मूल्यांकन कर सकता है जो संभावित आपदा पैदा कर सकती है।

ख) आपदाओं से होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता के कारणों को ध्यान में रखे।



ग) आपदा प्रबंधन टीमों के समुचित कार्य के लिए समुत्थानशीलता और गतिशीलता की आवश्यकता है।

घ) आपदा प्रबंधन खतरों को खत्म नहीं करता है लेकिन यह आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए उचित योजनाएँ बना सकता है।

ङ) आपदाओं के लिए तैयारी करने से जान बचती है और रिकवरी में तेजी आती है।

9. वन अग्नि जोखिम शमन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 15–17 जून 2022, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) जंगल की आग न केवल हिमाचल के लिए बल्कि पूरे विश्व में एक ज्वलंत मुद्दा है। जंगल की आग को नियंत्रित करने और उससे निपटने के लिए शीघ्र पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया ही एकमात्र तरीका है।



ख) जंगल की आग की निगरानी, शमन, प्रतिक्रिया और वनीकरण के लिए प्रारंभिक चेतावनी उपकरणों (IoT / LoRaWAN) के साथ भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सकता है।

ग) स्थानीय स्तर पर रोकथाम और शमन तकनीकों/तरीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

घ) स्थानीय समुदाय जंगल की आग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, हमें उन्हें जंगल की आग के नुकसान के बारे में जागरूक करना चाहिए।

ङ) वेटिवर घास, एक महत्वपूर्ण किफायती बायोइंजीनियरिंग समाधान है। जंगल की आग से लेकर जल संरक्षण तक इसका बहुआयामी उपयोग है।

च) आईआईआरएस द्वारा दैनिक आधार पर आग के आंकड़ों के बारे में नि:शुल्क डेटा प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग राज्य के अधिकारियों द्वारा जंगल की आग की चेतावनी के लिए किया जा सकता है।

छ) डीएमए और राज्य वन विभागों, अग्निशमन विभागों आदि और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

ज) वन संरक्षण को अपनी जीवनशैली के मुख्यधारा में लाने के लिए सामुदायिक जागरूकता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

झ) ग्राउंड स्टाफ के लिए जंगल की आग से निपटने के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न उपकरण, उपकरण और गियर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ण) संबंधित कर्मचारियों और वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों द्वारा वॉच टावर और फायर लाइन (आंतरिक-बाहरी) जैसे शमन उपायों पर व्यावहारिक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

10. समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन, 20-24 जून 2022, एटीआई, नैनीताल

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) सामुदायिक स्तर पर जागरूकता सृजन और सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता।



ख) अधिकतम लोगों को बचाने के लिए उचित प्रतिक्रिया हेतु आपदाओं से निपटने के लिए उचित योजना और रणनीति आवश्यक है।

ग) आपदा जोखिम में कमी के लिए जोखिम-संभावित क्षेत्रों, संवेदनशील इलाकों और विभिन्न आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है।

घ) समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीएम) आपदा प्रबंधन का एक दृष्टिकोण है जिसमें समुदाय को इस तरह शामिल किया जाता है कि वे तय करते हैं कि आपदा के जोखिम को कम करने के लिए क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।

ङ) सीबीडीआरएम स्थानीय स्तर पर जमीनी स्तर के सामुदायिक आपदा जोखिम प्रबंधन की भागीदारी को बढ़ावा देता है। प्रयासों की एक श्रृंखला की आवश्यकता है, जिसमें खतरों और आपदा जोखिम की व्याख्या स्वयं समुदाय करें, जिसमें अपनी कमियों और आपदा जोखिम में कमी को लेकर अपने स्वयं के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन शामिल है।

च) जोखिम-संभावित क्षेत्रों में रहने वाले जमीनी स्तर के समुदायों के बीच खतरों की समझ आवश्यक है। इस तरह के ज्ञान में विफलता से जमीनी स्तर पर अस्थिर आपदा जोखिम में कमी आएगी। यदि आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा स्थानीय सामुदायिक क्षमता और सामुदायिक प्राथमिकता के बारे में जागरूकता से नहीं आता है, तो प्रयास टिकाऊ नहीं होगा।

छ) स्कूलों, बच्चों, बुनियादी ढांचे और आसपास के क्षेत्रों की उचित सुरक्षा के लिए हमारी कार्ययोजना का मसौदा तैयार करके स्कूल सुरक्षा के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना को मैनुअल और मानक संचालन प्रक्रियाओं के रूप में औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है।

ज) सीबीडीआरएम दृष्टिकोण स्थानीय समुदाय को प्रारंभ में अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण के तहत, स्थानीय समुदाय न केवल योजनाओं और निर्णयों के निर्माण का हिस्सा बनता है बल्कि इसके कार्यान्वयन में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाता है।

11. आपदा प्रतिरोधी स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, 11–15 जुलाई 2022, एसपीए, दिल्ली

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) किसी भी आपदा के दौरान बीमारों की सहायता के लिए सुरक्षित और लचीला अस्पताल क्रियाशील रहना चाहिएय इसलिए उपकरण और बुनियादी ढांचे को तद्नुसार डिजाइन और नियोजित किया जाना चाहिए।

ख) अस्पताल को अपनी बैकअप बिजली और चिकित्सा गैस आपूर्ति के साथ आपदा के दौरान क्रियाशील रहने के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए।

ग) डिजाइन टीम को बाढ़ और भूकंप या साइट के अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए गहन साइट सर्वेक्षण करना चाहिए। इससे साइट चयन, डिजाइन और निर्माण में मदद मिलेगी।

घ) भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन को डिजाइन, विशेष रूप से क,लम, अग्रभाग और लेआउट में जल्दी ही लागू किया जाना चाहिए। भूकंप के प्रति अस्पताल के प्रतिरोधक क्षमता में कंक्रीट और स्तंभ अनुभागों का ग्रेड सर्वोपरि है।

ङ) संक्रमण को कम करने के लिए महामारी के बाद एचवीएसी सिस्टम के डिजाइन को निस्पंदन सिस्टम, बढ़े हुए वायु प्रवाह और अधिक संचालन योग्य खिड़कियों के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।

च) आग लगने या किसी अनियोजित घटना की स्थिति में कई निकास की अनुमति देने के लिए अस्पताल के गलियारे रैखिक के बजाय गोल होने चाहिए।

छ) डिजाइनरों को विस्तार की अनुमति देने के लिए योजना के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की अनुमति देने के लिए एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

ज) महामारी के बाद अस्पतालों के तौर-तरीकों में बदलाव किए गए हैं, डिजाइनर्स को विभिन्न रूपों में विद्युत और चिकित्सा गैस कनेक्शन लाइनें प्रदान करनी चाहिए, जिन्हें महामारी की लहर के दौरान उपयोग में लाया जा सके।

झ) अस्पतालों में भवन प्रबंधन प्रणालियों को महामारी प्रतिरोधी और चेतावनी प्रणालियों को एकीकृत करना चाहिए। इससे किसी आपदा या संक्रमण फैलने के दौरान मरीजों, कर्मचारियों और सरकारी निकायों को चेतावनी जारी करने में मदद मिल सकती है।

ण) महामारी की रोकथाम में दिन की रोशनी और प्राकृतिक हवा रोगियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, वार्डो में खुलने वाली खिड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

12. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) का एकीकरण पीएम एजेंडा 8 और 9, 18–20 जुलाई 2022, एचआईआरडी, निकोलखेरी, कर्ण

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपदा के पैरामीटर जिन्हें आपदाओं को डी-कोड करने से पहले अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है।

ख) 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया जब राहत-प्रतिक्रिया से रोकथाम-शमन उपायों में एक आदर्श बदलाव आया।

ग) आपदा परिदृश्य में समावेशी और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आपदा प्रबंधन उपायों को स्थानीय बनाना सबसे अच्छा तरीका है।



घ) प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में समुदाय किसी अन्य की तुलना में अपने संघर्षों और दर्द को अधिक जानते और समझते हैं, इसलिए संबंधित स्थिति में डीआरआर ढांचा हमेशा समुदाय-आधारित होना चाहिए।

ङ) जब कोई आपदा आती है, तो क्षति और हानि अपेक्षा से अधिक होती है, इसलिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि पीआरआई और विभिन्न योजनाएं कैसे मदद कर सकती हैं।

च) स्थलाकृति, पारिस्थितिकी और संस्कृति के संदर्भ में भारत की विविधता विशिष्ट स्थानों और समुदायों के लिए विशेष समाधान की मांग करती है। एक ग्राम विकास प्रबंधन योजना गांवों में समुदायों को समाधान तैयार करने और आपात स्थिति के दौरान उनका पालन करने की सुविधा प्रदान करती है।

13. डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों की भागीदारी, 25-29 जुलाई 2022, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के बारे में बुनियादी जानकारी को समझें, जिसमें इसके लक्षण, जटिलताएं, यह कैसे फैलता है और संचरण को कैसे रोका जाए और लोगों के बीच कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए ए टू जेड गतिविधि शामिल है।

ख) आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) के मापन से संबंधित जागरूकता प्रदान करना चाहिए।

ग) जागरूकता पैदा करने और परिवर्तन निर्माता के रूप में कार्य करने वाले समुदाय की सहायता करने के रूप में आपदा जोखिम प्रबंधन में युवा संगठनों के महत्व को समझना चाहिए।

घ) जलवायु चुनौतियों या आपदाओं को कम करने में युवाओं की भूमिका और जलवायु कार्रवाई के लिए युवा आंदोलन के महत्व की गणना की जाए।

ङ) आपदा के समय युवाओं और किशोरों के मनोवैज्ञानिक संबंधी मुद्दों से निपटने की रणनीतियों की व्याख्या की जाए।

14. जैव-इंजीनियरिंग उपायों द्वारा चक्रवात जोखिम शमन और कटाव नियंत्रण, 25-29 जुलाई 2022, भूगोल विभाग, विद्या सागर विश्वविद्यालय

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) इस कार्यक्रम ने जैव-अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से कटाव नियंत्रण उपायों के क्षेत्र काम करने को लेकर एक अंतदृष्टि प्रदान की।



ख) वेटिवर घास जैसे विशेष उपकरणों के उपयोग के बारे में सीमित जागरूकता और समझ के कारण परिवहन परियोजनाओं में इसका व्यापक उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर कम काम हुआ है। इसके साथ ही, स्थलीय और बाहरी प्रदूषण को कम करने के लिए उसके उपयोग से नुकसान को कम किया जा सकता है।

ग) आपदा प्रबंधन एवं क्षति की मरम्मत के लिए ही नहीं, बल्कि और अधिक न्यायसंगत, सतत् और प्रतिरक्षा योग्य समुदायों का निर्माण करने के लिए स्थानीय ज्ञान की मांग और सामाजिक, सांस्कृतिक, और पर्यावरणीय संपदाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

घ) वेटिवर घास का उपयोग पारिस्थितिक अभियांत्रिकी और पर्यावरण बहाली के लिए किया गया है। वेटिवर घास मिट्टी को बारिश, अपवाह और फिसलन से बचा सकती है। इससे जंगल की आग का खतरा भी कम हो जाता है।

ङ) गैर-अभियांत्रिक इमारतों को सुदृढ़ करने के बारे में समुदायों के साथ ज्ञान साझा किया जाना चाहिए। स्थानीय इंजीनियर और कारीगर अपने इलाके में इमारतों के निर्माण और रेट्रोफिटिंग में भाग ले सकते हैं और जनता के लिए आपदा प्रतिरोधी निर्माण विधियों का प्रदर्शन कर सकते हैं।

च) एनआईडीएम ने कटाव प्रभावित क्षेत्रों की रक्षा के लिए वेटिवर वृक्षारोपण द्वारा जैव-इंजीनियरिंग माप तकनीकों का प्रदर्शन किया।

15. मजबूत बुनियादी ढांचे के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं में डीआरआर एवं सीसीए की मुख्य भूमिका, 26-29 जुलाई 2022, ओएसडीएमए, यूएनडीपी/गोपबंधु प्रशासन अकादमी, ओडिशा/त्रिपुरा

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) तैयारियों के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय करने की आवश्यकता।

ख) अधिक समुत्थानशील भारत बनाने के लिए डीआरआर को सभी विकासात्मक गतिविधियों में एकीकृत किया जाना चाहिए।

ग) आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए जैसा कि दिशा-निर्देशों में दिए गए हैं।

घ) वेटिवर घास वृक्षारोपण के साथ जैव-इंजीनियरिंग उपायों के बारे में स्थानीय लोगों में जागरूकता विकसित हुई है।

ङ) यह सुनिश्चित किया गया कि कार्यान्वयन के लिए मजबूत संस्थागत आधार के साथ जोखिम में कमी एक राष्ट्रीय और स्थानीय प्राथमिकता है।

च) सभी स्तरों पर सुरक्षा और समुत्थानशील संस्कृति का निर्माण करने के लिए समझ और जागरूकता-नवाचार और शिक्षा का निर्माण करना।

छ) सभी स्तरों पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को मजबूत करना।

16. जनस्वास्थ्य संकट एवं आपदा प्रबंधन पर फाउंडेशन कोर्स, 28–30 जुलाई 2022, एनसीडीसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीडीसी भारत एवं उत्तराखंड सरकार

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की प्रतिरोधक क्षमता के लिए मजबूत निर्णय।

ख) लाइन विभागों के बीच समन्वय, संचार और सहयोग को मजबूत करना।

ग) आकस्मिक प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) के साथ संरेखित करना।

घ) समुदाय किसी भी संकट से निपटने के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं इसलिए उनकी साझेदारी एवं सहभागिता बढ़ाने की जरूरत है।

ङ) किसी भी आपातकालीन, संकट या आपदा के दौरान स्वयं का जीवन बचाने के लिए ज्ञान प्रदान करना।

च) जिला आपदा प्रबंधन योजना में स्वास्थ्य घटक को शामिल करना।

छ) संसाधन दस्तावेज के रूप में मॉड्यूल का उपयोग करके इस प्रशिक्षण को कैस्केड करना।

17. जनस्वास्थ्य संकट एवं आपदा प्रबंधन पर फाउंडेशन कोर्स, 28–30 जुलाई 2022, एनसीडीसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सीडीसी भारत एवं उत्तराखंड सरकार

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) आपदा के प्रभाव, चाहे वे मानव-निर्मित हों या प्राकृतिक, पर्यावरण और मानव दोनों पर प्रभाव डालते हैं। पर्यावरणीय कारकों से आपदाएँ और बदतर हो सकती हैं और इसके विपरीत भी, आपदा का पर्यावरण पर भी प्रभाव हो सकता है।

ख) हमारे प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन प्रोंतिक और मानव निर्मित खतरों को भी कम करता है।

ग) सुदृढ़ संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता, आपदा को टालने या लोगों, उनके घरों और आजीविकाओं पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए एक रणनीति के रूप में किया जाता है और यह आपदा प्रबंधन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के महत्व को मजबूत करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

18. आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाग पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, 16–18 अगस्त 2022, मेघालय राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान, शिलांग

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कुशल सेवा प्रदाताओं की भारी कमी है। यहां तक कि पेशेवरों के पास भी आपदाओं के दौरान पीएसएसएमएचएस के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव है।

ख) विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए अनेक प्रकार के पीएसएसएमएचएस को एकीकृत और समन्वयित करने की आवश्यकता है। इससे सेवाओं के दोहराव से बचा जा सकेगा और सेवाओं की उचित डिलिवरी सुनिश्चित की जा सकेगी।



ग) जिला या राज्य स्तर पर कुशल और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता पर सूची का अभाव।

घ) जीवन की अन्य सुविधाओं के पुनर्निर्माण के साथ आपदा प्रभावित आबादी के भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देने के लिए मनोसामाजिक देखभाल का प्रारंभिक चरण सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न आपदा हस्तक्षेपों से सीख को शामिल करना और सूचना का प्रसार सुनिश्चित करना समय की मांग है।

ङ) मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों और अस्पतालों में मनोरोग विभागों के मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर राज्य में विशेष मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं। एक उभरती हुई प्रवृत्ति देखी गई है जिसमें मनोचिकित्सकों के अलावा, अन्य मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य विषयों के सामाजिक कार्यकर्ता भी सेवाएं प्रदान करने में शामिल हो सकते हैं।

च) राज्य सरकारें आपदाओं के तुरंत बाद कुछ मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को तैनात कर सकती हैं। इन पेशेवरों ने विभिन्न आपदाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करने की पहल की है।

छ) एनआईएमएचएएनएस, मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (आईएचबीएएस) और मेघालय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एमआईएमएचएएनएस) आदि जैसे सरकारी संस्थान आपदाओं में मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं (पीएसएसएमएचएस) प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

ज) आपदा के दौरान पीएसएसएमएचएस गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेष रूप से यूएन एजेंसियों, जैसे मानवतावादी कार्रवाई के लिए समन्वय कार्यालय (ओसीएचए), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

19. व्यापक आपदा प्रबंधन, 22-26 अगस्त 2022, नवोदय विद्यालय, एनआईडीएम

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) एक बंद संस्थान हैं क्योंकि ये आवासीय विद्यालय होते हैं जिनमें कर्मचारी, परिवार और छात्र भी कैम्पस में रहते हैं। इससे आपदा प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण जागरूकता की आवश्यकता महसूस होती है।

ख) प्रत्येक जेएनवी को निकासी, प्राथमिक चिकित्सा, मनो-सामाजिक परामर्श, आश्रय, भोजन आदि जैसी आपदा प्रबंधन टीमों का गठन करना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए।

ग) ऐसे प्रत्येक स्कूल में नियमित अग्नि सुरक्षा अभ्यास आवश्यक है।

घ) जिला अधिकारियों और स्कूल की आंतरिक बैठक नियमित रूप से करने से समन्वय की समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

ङ) जेएनवी परिवार को पूरी तरह से आपदा जोखिम कम करने के लिए इसे मुख्य स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है। इसलिए, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नवोदय आयुक्त, उप आयुक्त, प्राचार्यो और अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ होने वाली हर बैठक में आपदा जोखिम कम करने के बारे में एक सत्र होना चाहिए।



20. दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए आपदा पश्चात आवश्यकताओं का आकलन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण/आपदा पश्चात तैयारियां, 26–30 सितंबर 2022, सीडीएम, एटीआई, मैसूर

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) एक क्षेत्रवार मूल्यांकन के लिए तकनीक को समझना, जिसमें उत्पादक क्षेत्र (कृषि, पशुपालन), सामाजिक क्षेत्र (आवास, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पोषण, शिक्षा और आवास), बुनियादी ढांचा (सड़कें और पुल, जल सफाई और स्वच्छता) और संचित क्षेत्र (जेंडर और सामाजिक समावेशन और विपदा प्रबंधन) शामिल हैं। पुनर्प्राप्ति की आवश्यकताओं का अनुमान सतर्कता से करना आवश्यक है।

ख) किसी आपदा के प्रभाव और प्रभाव की पूरी सीमा और प्रभावित आबादी की जरूरतों को समझने में सरकार की सहायता करना।



ग) पीडीएनए यह सुनिश्चित करता है कि आवास एवं आपदा से निपटने के उपाय प्रभावित समुदायों की जरूरतों के लिए उपयुक्त है।

घ) किसी घटना का तीव्र और व्यापक बहु-क्षेत्रीय मूल्यांकन, पुनर्प्राप्ति योजना प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक व्यापक दृष्टिकोण और नीति प्रदान करता है।

ङ) आपदाओं के शुरुआती परिणामों के दौरान किए गए मानवीय मूल्यांकन का निर्माण।

च) क्षेत्र मूल्यांकन का उद्देश्य आवास क्षेत्र पर घटना के प्रभाव और प्रभाव को समझने में सभी स्तरों पर सरकार की सहायता करना है।

21. ग्राम आपदा प्रबंधन योजना का ग्राम पंचायत (जीपीडीपी) के साथ एकीकरण, 17–19 अक्टूबर 2022, आरआईपीए, राजस्थान

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) किसी भी आपदा परि–श्य में खतरा–जोखिम–संवेदनशीलता और क्षमता का आकलन, सहायता

ख) सबसे उपयोगी और सुलभ समाधानों को तेजी से तैयार करने के साथ-साथ डीआरआर पहलुओं के उपयोग को सुविधाजनक बनाना।

ग) स्थलाकृति, पारिस्थितिकी और संस्कृति के संदर्भ में भारत की विविधता विशिष्ट स्थानों और समुदायों के लिए विशेष समाधान की मांग करती है।



घ) आपदाओं को डी-कोड करने से पहले आपदा के विभिन्न मापदंडों को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है।

ङ) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया जब राहत-प्रतिक्रिया से रोकथाम-शमन उपायों में एक आदर्श बदलाव आया।

च) आपदा परिदृश्य में समावेशी और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आपदा प्रबंधन उपायों को स्थानीय बनाना सबसे अच्छा तरीका है.

22. नदी संरक्षण, जलवायु प्रतिरोधकता और डीआरआर: योजनाएं, दृष्टिकोण एवं नीतियां, 17-21 अक्टूबर 2022, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) क्षेत्र की भूवैज्ञानिक स्थिति के आधार पर डीआरआर योजनाओं को डिजाइन करने के लिए स्थानीय ज्ञान की भागीदारी बढ़ाएँ नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और स्थानीय भागीदारी के बीच इंटरफेस विकसित करना।



ख) सभी नदी खंडों में ई-प्रवाह बनाए रखना।

ग) नदी के आधार प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जलधाराओं, झरनों को पुनर्जीवित करने, तटीय प्रबंधन और नीति अनुशंसा की योजना।

घ) घटते जलभृत को वापस लाने के लिए जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के तहत भूजल प्रबंधन के लिए स्थायी समाधान विकसित करने की आवश्यकता है।

ङ) जलवायु-जल-भूजल-पारिस्थितिकी-अनुकूलन और शमन संबंधों पर साझा समझ विकसित की जानी चाहिए।

च) विनियमन और कार्यान्वयन के बीच अंतर को कम करें.

23. श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंधित संगठनों/कार्यालयों द्वारा डीएमपीएस का विकास, 17-21 अक्टूबर 2022, एनआईडीएम, नई दिल्ली

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण समग्र होना चाहिए और इसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए।

ख) डीआरआर गतिविधियों का समर्थन करें, एक मजबूत संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है; हितधारकों को संबंधित संस्थानों के विभिन्न कार्यों और महत्व के बारे में पता होना चाहिए।

ग) किसी भी डीएम योजना की कुंजी जोखिम, भेद्यता और क्षमता विश्लेषण है, जिसे उचित परिश्रम के साथ किया जाना चाहिए।



24. भूकंप जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन, 17–21 अक्टूबर 2022, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) श्रीनगर शहर और कश्मीर क्षेत्र के अन्य शहरी केंद्र भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और कुप्रबंधन, अनियोजित आवास और गैर-इंजीनियरिंग निर्माण, शहरी फैलाव आदि जैसी मानवजनित गतिविधियों से जोखिम बढ़ गया है।

ख) रणनीतिक शहरी और आपातकालीन योजना प्रबंधन कार्यों को परिभाषित करने के लिए भूकंपीय जोखिम मूल्यांकन आवश्यक है और यह इमारतों, अनाश्रित आबादी और उनकी आपातकालीन बातचीत के विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए।

ग) विरासत को संरक्षित करने के लिए ऐतिहासिक इमारतों की संवेदनशीलता को कम करने के लिए जोखिम न्यूनीकरण समाधानों की पहचान करने की सख्त जरूरत है।



घ) भूकंप प्रतिरोधी भवन प्रौद्योगिकी की विश्वसनीयता और स्थिरता के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय राजमिस्त्रियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है।

ड.) सुरक्षा वृद्धि और आर्थिक संसाधन आवंटन के संदर्भ में लागत-लाभ विश्लेषण के माध्यम से व्यापक पैमाने पर रेट्रोफिटिंग रणनीतियों का परिचय।

च) पारंपरिक प्रथाओं से नई तकनीक में परिवर्तन का प्रबंधन करने की आवश्यकता है ताकि भूकंप जोखिम कम करने के प्रयास टिकाऊ बने रहें।

25. विकास योजना में आपदा समुत्थानशील के उपायों को मुख्यधारा से जोड़ना, 19–21 अक्टूबर 2022, मिजोरम: आइजोल

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) भविष्य में आपदा जोखिम और भेद्यता को कम करने के लिए विकास योजना के लिए मुख्यधारा डीआरआर के लिए आवश्यक।

ख) विकास योजना में डीआरआर को मुख्यधारा में लाने के लिए नीति-निर्माताओं और उच्च प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाना आवश्यक है।

ग) केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से विकास योजना में मुख्यधारा डीआरआर में मौजूदा अंतराल की पहचान। योजनाएं और कार्यक्रम.

घ) जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, उनकी पहचान करने के लिए जोखिम की संवेदनशीलता का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार, स्थानीय स्तर पर जोखिमों को कम करने के लिए रोकथाम और शमन उपाय अपनाए जाने चाहिए।

ङ) योजनाओं को लागू करते समय डीआरआर और सीसीए उपायों को मुख्यधारा में लाने में विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों और हितधारकों की भूमिका को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

च) मौजूदा तकनीकी-कानूनी ढांचे, भवन निर्माण उपनियमों और जोनिंग नियमों की समीक्षा करने और विकास परियोजनाओं को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

छ) जोखिम संवेदनशील विकास योजना का पालन किया जाना चाहिए और योजना बनाई जा रही प्रत्येक गतिविधि को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

ज) सीखे गए सबक और अच्छी प्रथाओं का अध्ययन और दोहराने की जरूरत है।



26. समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, 26-28 अक्टूबर 2022, पणजी गोवा

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) सामुदायिक स्तर पर जागरूकता सृजन और सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता।

ख) उचित प्रतिक्रिया के लिए आपदाओं से निपटने के लिए उचित योजना और रणनीति आवश्यक है। आपदा जोखिम में कमी के लिए जोखिम-संभावित क्षेत्रों, संवेदनशील इलाकों और विभिन्न आपदाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है।

ग) समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीएम) आपदा प्रबंधन का एक दृष्टिकोण है जिसमें समुदाय को इस तरह से शामिल किया जाता है कि वे तय करते हैं कि आपदा के जोखिम को कम करने के लिए क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।

घ) सीबीडीआरएम स्थानीय स्तर पर जमीनी स्तर के सामुदायिक आपदा जोखिम प्रबंधन की भागीदारी को बढ़ावा देता है।

ङ) जोखिम-संभावित क्षेत्रों में रहने वाले जमीनी स्तर के समुदायों के बीच खतरों की समझ आवश्यक है। यदि आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा स्थानीय सामुदायिक क्षमता और सामुदायिक प्राथमिकता के बारे में जागरूकता से नहीं आता है, तो प्रयास टिकाऊ नहीं होगा।



च) स्कूलों, बच्चों और आसपास के क्षेत्रों की उचित सुरक्षा के लिए हमारी कार्य योजना का मसौदा तैयार करके स्कूल सुरक्षा के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना के संबंध में सीबीडीआरएम को मैनुअल और मानक संचालन प्रक्रियाओं के रूप में औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है।

27. बाल केंद्रित संवेदनशीलता, क्षमता वृद्धि एवं समुत्थानशीलता को बढ़ावा देने पर जोर, 31 अक्टूबर-4 नवंबर 2022, चंडीगढ़, पंजाब

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) बच्चों और युवाओं की जनसंख्या ने देश के कार्यबल के निर्माण में मदद की जिसने राष्ट्र के विकास में योगदान दिया।

ख) युवाओं और बच्चों के पास राष्ट्रीय और स्थानीय डीआरआर रणनीति योजना के साथ-साथ कार्यान्वयन में भाग लेने और योगदान करने के लिए ज्ञान और समर्थन है।



ग) जब बच्चे जोखिम कम करने की गतिविधियों में लगे होते हैं तो वे ज्ञान के रचनात्मक संचारक के रूप में उभरते हैं।

घ) बच्चे अपने घरों में जोखिम और जोखिम में कमी के संदेश संप्रेषित करते हैं ताकि इन मूल्यों को परिवार के सदस्यों द्वारा साझा किया जा सके।

ङ) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं और बच्चों को शिक्षा और कौशल निर्माण के अवसरों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

च) कोविड-19 के प्रसार के इस समय में स्कूल को फिर से खोलते समय सीसीडीआरआर दृष्टिकोण को लागू करना समय की मांग है।

28. घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): आईसी और पीएससी, 31 अक्टूबर-4 नवंबर 2022, एनआईडीएम, नई दिल्ली

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) पाठ्यक्रम एनआईडीएम में आयोजित किए जाने चाहिए ताकि पूरे देश के अनुभवों को शामिल किया जा सके।

ख) आईआरएस अधिसूचित राज्यों के विशेषज्ञों द्वारा अपने अनुभव साझा करने के लिए सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।

ग) प्रशिक्षण और समीक्षण का समापन हर प्रशिक्षण के अंत में विषय के बेहतर समझने के लिए किया जाना चाहिए।''

घ) ऐसे पाठ्यक्रमों का अनुसूची इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि इसमें आईआरएस के मूल और मध्यस्तरीय पाठ्यक्रम का अवलोकन शामिल हो, जो संबंधित पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध किया जाए, ताकि उस पाठ्यक्रम के प्रारंभ से पहले आईआरएस के मूल सिद्धांतों की पुनरावलोकन किया जा सके।



29. जिला स्तरीय योजनाओं में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एकीकरण, 31 अक्टूबर–4 नवंबर 2022, एसआईआरडी लखनऊ, यूपी



मुख्य बातें/सिफारिशें

क) विधिक नीति फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दों को प्रतिभागियों द्वारा अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए।

ख) प्रतिभागियों को पंचायती राज संगठनों के साथ समन्वय में व्यावहारिक दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है।.

ग) प्रतिभागियों ने विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के महत्व को समझा।

घ) प्रतिभागियों ने सेंदाई ढांचे और उसके एजेंडे को समझा।

ङ) प्रतिभागियों को व्यावहारिक उदाहरणों के साथ खतरे, जोखिम, भेद्यता और क्षमता विश्लेषण अवधारणाओं, उपकरणों और तकनीकों को समझने की आवश्यकता है।

च) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को उदाहरणों के साथ अच्छी तरह से समझाया गया था।

छ) डीआरआर के लिए पर्यावरणीय उपकरण और दृष्टिकोण प्रतिभागियों द्वारा अच्छी तरह से समझे गए थे

30. आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास में उपग्रह पृथ्वी अवलोकन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर कार्यशाला कार्यक्रम (ईओएआईडीआरआई), 11–13 नवंबर 2022, एमएनएनआईटी, इलाहाबाद

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) आपदा के प्रभाव की जांच करने के लिए विश्लेषण करने और योजना तैयार करने के लिए आर्क–जीआईएस और एचईसीएच–आरएएस जैसे कंप्यूटर सहायता प्राप्त मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक अनुभव और अनुभव।

ख) समाज में नए हितधारकों को विकसित करना और तैयार करना जो आपदाप्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आपदा को कम करने केलिए तकनीकी रूप से सक्षम हों।

ग) बुनियादी ढांचे और मौजूदा संरचनाओं के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए अतीत की विनाशकारी घटनाओं से सीख को भविष्य की विकास गतिविधियों में नियोजित किया जाना चाहिए।



घ) इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के बीच बौद्धिक संसाधनों के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय सहयोग का पता लगाया जाना चाहिए और तैयार किया जाना चाहिए।

ङ) सूखे और बाढ़ आपदा प्रबंधन में मजबूत संस्थागत ढांचा और मानव संसाधनों का क्षमता विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।

31. भारतीय रेलवे के सेवारत अधिकारियों के लिए सामान्य आपदा प्रबंधन, 21–25 नवंबर 2022, (आईआरआईडीएम), बेंगलुरु

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित कराया गया ताकि खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता आदि का आकलन किया जा सके।

ख) डीआरआर पर सेंडाई फ्रेमवर्क और पीएम 10 प्वाइंट एजेंडा की जानकारी ताकि प्रतिभागियों को अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों में इसे लागू करने में सक्षम बनाया जा सके।

ग) एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन सेवाओं द्वारा नियोजित विभिन्न बचाव तकनीकों और उपकरणों का उपयोग प्रतिभागियों को अपने कार्य क्षेत्र के लिए समान उपकरणों की योजना बनाने में सक्षम बनाता है।



घ) ट्रेन दुर्घटना पर पूर्ण पैमाने पर मॉक ड्रिल से प्रतिभागियों को एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को जानने में मदद मिली।

ङ) दुर्घटना स्थल पर बहाली के लिए अर्थमूवर्स के उपयोग को समझना और बरती जाने वाली सावधानियां।

च) आपदा प्रबंधन में शामिल पहली पंक्ति के कर्मचारियों और अन्य कर्मियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए सुनने और विश्राम करने की सक्रिय तकनीक का उपयोग

32. आपदाओं से उबरने में सबसे पहले उत्तरदायित्व निभाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए आपदा के बाद तनाव प्रबंधन, 06–08 दिसंबर 2022, तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) स्थानीय लोगों को संवेदनशीलता, जोखिम और आपदा के खतरे के बारे में शिक्षित करना।

ख) जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से प्रथम उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए।

ग) मानसिक स्वास्थ्य बनाम मानसिक बीमारी की बुनियादी समझ विकसित की जानी चाहिए।

घ) कार्यस्थल पर काम की संसेंति और तनाव को प्रभावित करने वाले संगठनात्मक उपायों में सुधार करना आवश्यक है।

ङ) प्रथम उत्तरदाताओं की जरूरतों और आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।



च) आपदा प्रतिक्रिया के बाद पारिवारिक स्तर पर तनाव को संभालना आवश्यक है।

छ) अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए।

33. तटीय सामुदायिक समुत्थानशीलता पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 27-29 दिसंबर 2022, पुडुचेरी

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति हितधारकों को संवेदनशील बनाना

ख) आपदा के प्रभाव, परिणाम एवं उसके बाद की स्थिति पर होने वाले चर्चाओं में किशोरों और युवाओं को शामिल करना

ग) युवा आबादी को शामिल करने के रास्ते की तलाश

घ) हितधारकों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से व्यापक कार्यबल का निर्माण



ड.) अद्यतन जानकारी के साथ सिस्टम और संरचनाओं का सशक्तिकरण

34. आपदाओं के प्रति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के समुत्थानशीलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 16-20 जनवरी 2023, एटीआई, मैसूरु

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) कर्नाटक राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरोधी बुनियादी संरचनाओं के बारे में क्षमता निर्माण

ख) भारत में आपदा प्रबंधन और वैश्विक ढांचे के साथ इसके संबंध के बारे में बताया गया।

ग) बाढ़ प्रबंधन और स्वास्थ्य मानचित्रण के तरीके।



घ) अधिकारियों द्वारा भूमिका और जिम्मेदारियां संभालने में भ्रम के कारण आपदा प्रबंधन में समस्याएं।

ङ) बुनियादी ढांचे के संरक्षण के लिए भवन सर्वेक्षण और रेट्रोफिटिंग तकनीक।

35. आपदा प्रबंधन और डीएमपी की तैयारी के लिए संकाय विकास कार्यक्रम, 30 जनवरी–03 फरवरी 2023, एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़, पंजाब

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) दृश्य प्रस्तुति और स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से खतरे का मापन, विभिन्न प्रकार के खतरों के लिए संवेदनशील स्थानों की पहचान करने में मदद कर सकता है और पूर्व-आपातकालीन योजना के प्रयासों को सूचित कर सकता है।

ख) मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा (PFA) सुरक्षा, शांति, जुड़ाव, आत्म-कौशल्य और आशा के एक वातावरण को प्रोत्साहित और बनाए रखने में मदद करता है और बनाए रखता है।

ग) पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) के लक्षण आत्मघाती व्यवहार से जुड़े हैं और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल से मनोसामाजिक सहायताध्देखभाल देने तक पहुंचने में लगभग 3 दशक लग गए।

घ) आपदा शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों और समूहों को जागरूकता प्रदान करना है ताकि वे आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जरूरी कदम उठा सकें।

ङ) मौजूदा आपदा प्रबंधन योजनाओं को अद्यतन करना और समीक्षा करना तात्काल जरूरतों के कारण किया जा रहा है।

च) राहत योजना का प्रावधान आपदा के दौरानध्तत्काल बाद प्रभावित लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता या हस्तक्षेप प्रदान करता है।

36. आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, 30 जनवरी–3 फरवरी 2023, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) आपदा जोखिम प्रबंधन की बुनियादी अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है।

ख) आपदा जोखिम प्रबंधन में स्वयंसेवकों को शामिल करने की बात की गई।

ग) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में युवाओं और किशोरों की भूमिका।

घ) युवाओं और किशोरों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की सूची की पहचान।

ङ) आपदा जोखिम प्रबंधन में युवाओं की भूमिका को परिभाषित करने की आवश्यकता है।

37. घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): संचालन अनुभाग प्रमुख, सुरक्षा अधिकारी और रसद अनुभाग प्रमुख, 06–10 फरवरी 2023, एनआईडीएम, नई दिल्ली

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) आपदा प्रबंधन में आईआरएस का उपयोग करने वाले एनडीआरएफ या राज्यों से प्राप्त वीडियो को अधिक प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों के दौरान साझा किया जाना चाहिए।

ख) संपूर्ण पाठ्यक्रम की सीख के आधार पर किया जाने वाला अंतिम अभ्यास कुछ जीवंत स्थितियों पर आधारित होना चाहिए। आईआरएस को लागू करने में यदि कोई चुनौतियाँ हैं, तो उन पर काबू पाने के राज्यों के अनुभवों को साझा करने के लिए सत्र आयोजित की जानी चाहिए।

ग) सीख का मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का तृतीय-पक्ष ऑडिट किया जाना चाहिए।

घ) आईआरएस के बारे में वरिष्ठ पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि वे जिलों में आईआरटी के गठन को बढ़ावा दे सकें।

38. संकाय विकास कार्यक्रम (क्षमता निर्माण) श्रृंखला 2– आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विचारों की प्रेरणा, 06–10 फरवरी 2023, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू), उत्तर प्रदेश

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) आपदा प्रतिरोधी विकास पर थोड़ा अतिरिक्त निवेश की प्रभावशीलता हजारों करोड़ लोगों की मेहनत की कमाई बचा सकती है।

ख) आपदा की तैयारी को एक लक्ष्य के रूप में समझना अधिक उचित है, न कि एक विशेष चरण के रूप में जो आपदा प्रतिक्रिया से तुरंत पहले होता है।

ग) पूरे भारत में भूकंप निगरानी स्टेशन और नागरिकों द्वारा समय पर कार्रवाई के लिए भूकम्प मोबाइल एप्लिकेशन। आर्सेनिक आपदा, लंबे समय तक जोखिम के कारण भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को मानव निर्मित आपदा और इसके संभावित समाधान माना जाता है।

घ) संरचनात्मक ऑडिट का महत्व, एनडीआरएफ मॉक ड्रिल, ड्रॉप-कवर-होल्ड और क्या करें और क्या न करें से संबंधित जीवन रक्षक युक्तियों का त्रिकोण।

ङ) आपदा के बाद मानसिक आघात और आपदा से बचे लोगों के बीच तनाव को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण और उपाय।

च) हरित लक्ष्यों के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वदेशी ऊर्जा संसाधनों, व्यापार लेखा परीक्षा, समान दूरसंचार नीतियों, रेडियो टावरों, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में कुछ व्यावहारिक समाधानों के साथ आपदा जोखिम में कमी।

छ) योजना रणनीतियाँ (राज्य और जिला डीएम योजना)य योजना की जरूरतें, ग्राम पंचायत स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (जीपी-डीआरआर)।

ज) आपदा के दौरान और उसके बाद एक प्रभावी संचार उपकरण के रूप में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी और आपातकालीन प्रतिक्रिया।

39. आपदाओं से उबरने में सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए आपदा के बाद तनाव प्रबंधन, 07-09 फरवरी 2023, एमसीएचआरडीआई, तेलंगाना

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) स्थानीय लोगों को संवेदनशीलता, जोखिम और आपदा जोखिम के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

ख) जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आपदा से निपटने में सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए।

ग) आपदा स्थितियों से निपटना।

घ) कार्यस्थल में काम की संस्कृति और तनाव को प्रभावित करने वाले संगठनात्मक उपायों में सुधार करें । संभावित रणनीतियों में वर्कफ्लो प्रबंधन में सुधार करना और कार्यभार कम करने पर केंद्रित सेवाओं को व्यवस्थित करना शामिल है।

ङ) पारिवारिक स्तर पर तनाव से निपटने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास विधियाँ।

च) तनाव को स्वयं से संभालना या तनाव पर काबू पाने के लिए विशेषज्ञ से परामर्श लेना।

40. पीएम एजेंडा नंबर 4, 7 और 8: स्कूल सुरक्षा योजना और ऑडिटिंग, 07-09 फरवरी 2023, जीआईपीएआरडी, गोवा

मुख्य बातें/सिफारिशें



क) गोवा के प्रत्येक स्कूल के लिए स्कूल आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) के तैयारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन समिति (डीएमसी) द्वारा स्कूल सुरक्षा के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शिकाओं का तैयार किया जाना चाहिए।

ख) छात्रों को इस एसडीएमपी के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए और घर से घर की सुरक्षा सहित भविष्य में जीवन के लिए जोखिम पैदा करने वाले किसी भी कारण की तलाश करने में सक्षम होना चाहिए। सभी स्कूल भवनों को आग से सुरक्षित होना चाहिए और

उनके पास अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग से एनओसी होनी चाहिए।

ग) स्कूल आपदा प्रबंधन योजना में स्कूल के आस-पास किसी भी ढीले तार, खम्भे, स्विच, और रसोईघर की जांच अच्छी तरह से किया जाना चाहिए।

घ) बहु-खतरे की तैयारी और शमन दृष्टिकोण हमारे स्कूलों की लचीलापन बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

ङ) भूकंप के खतरे से पुराने और कमजोर स्कूल निर्माणों की पहचान के लिए रेट्रोफिटिंग उपाय अपनाए जाने चाहिए।

च) राज्य सरकार को स्कूलों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा उपकरणों को लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जा सके।

छ) दूरस्थ क्षेत्रों को विशेष रूप से युवाओं और बच्चों को स्वयंसेवकों या आपदा मित्र के रूप में आपदा प्रबंधन गतिविधियों में शामिल करने के लिए संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

41. दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (पीडीएनए) पर टीओटी/पीडीपी, 13-17 फरवरी 2023, एपीएचआरडीआई, आंध्र प्रदेश

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं और रणनीतियों के विकास और अनुमान को समझना।



ख) भारत के संदर्भ में पुनर्प्राप्ति योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन की रूपरेखा को समझने की आवश्यकता है।

ग) इसका उद्देश्य सरकारों को आपदा के प्रभाव और प्रभाव की पूरी सीमा और प्रभावित आबादी की जरूरतों को समझने में सहायता करना था।

घ) पीडीएनए ने सुनिश्चित किया कि आवास और निपटान प्रतिक्रिया प्रभावित समुदायों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।

ङ) यह किसी घटना का तीव्र और व्यापक बहु-क्षेत्रीय मूल्यांकन है और पुनर्प्राप्ति योजना प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक व्यापक दृष्टिकोण और अभिविन्यास प्रदान करता है।

च) क्षेत्र मूल्यांकन का उद्देश्य आवास क्षेत्र पर घटना के प्रभाव और प्रभाव को समझने में सभी स्तरों पर सरकार की सहायता करना था.

42. आपातकालीन संचालन केंद्र: स्थापना और संचालन, 22-24 फरवरी 2023, एनआईडीएम, नई दिल्ली

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए कुछ परिचालन ईओसी के विशेषज्ञों को आमंत्रित करना।

ख) परिचालन ईओसी का क्षेत्र दौरा पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।

ग) ईओसी के महत्व और परिचालन संबंधी मुद्दों को संवेदनशील बनाना। क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर विचार किया जा सकता है।

घ) ईओसी पाठ्यक्रम में डीएम योजना, प्रबंधन और संसाधनों को जुटाने, प्रबंधन और सूचना विश्लेषण के साथ इसके जुड़ाव पर सत्र भी शामिल होना चाहिए।

ङ) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इसे स्थापित करने से पहले ईओसी के संचालन और गतिविधियों का एक दृष्टिकोण होना चाहिए



43. श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंधित संगठनों/कार्यालयों द्वारा डीएमपीएस विकसित करने पर संवेदीकरण कार्यक्रम, 13–17 मार्च 2023, एनआईडीएम, नई दिल्ली

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) विचारों के बेहतर कार्यान्वयन की कुंजी है योजना, और आपदा प्रबंधन योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर जीवन बचाने से संबंधित है।

ख) आपदा प्रबंधन का दृष्टिकोण समग्र होना चाहिए और इसमें सभी पक्ष शामिल होने चाहिए।

ग) डीआरआर गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, एक मजबूत संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है; हालाँकि, इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, हितधारकों को संबंधित संस्थानों के विभिन्न कार्यों और महत्व के बारे में पता होना चाहिए।

घ) किसी भी डीएम योजना की कुंजी खतरा, भेद्यता और क्षमता विश्लेषण है, जिसे उचित परिश्रम और जमीनी सच्चाई के साथ किया जाना चाहिए।



44. राज्य और जिला योजनाओं में सीसीए-डीआरआर एकीकरण पर क्षेत्रीय स्तर की टीओटी, 20–22 मार्च 2023, एटीआई, नैनीताल

मुख्य बातें/सिफारिशें

क) संवेदनशीलता के मूल्यांकन का संचालन करना: सबसे कमजोर आबादी, संपत्ति और बुनियादी ढांचे की पहचान की गई जो सीसीए और डीआरआर उपायों के लिए संसाधनों के आवंटन को प्राथमिकता देने में मदद करेगी।

ख) अनुकूलन और शमन रणनीतियाँ विकसित करना: अनुकूलन और शमन रणनीतियाँ विकसित की जानी चाहिए जो जलवायु परिवर्तन और संभावित आपदाओं के प्रभावों पर विचार करें। इन रणनीतियों को राज्य और जिला विकास योजनाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए।



ग) सभी हितधारकों को शामिल करना: सीसीए और डीआरआर के प्रभावी एकीकरण के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।

घ) विकास योजना में सीसीए और डीआरआर को मुख्यधारा में लाना: सीसीए और डीआरआर को राज्य और जिला विकास योजना, बजट और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में मुख्यधारा में लाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सीसीए और डीआरआर उपायों को प्राथमिकता दी जाती है और संसाधनों को तदनुसार आवंटित किया जाता है।

ङ) संस्थागत क्षमता को मजबूत करना: विकास योजना में सीसीए और डीआरआर को एकीकृत करने के लिए राज्य और जिला सरकारों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए।

नोट: आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रमों/वेबिनार/ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रमों की विस्तृत सूची अनुलग्नक 3 से 5 (अध्याय 8) पर उपलब्ध हैं ।

6.22 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर) का तीसरा सत्र

'विकास में डीआरआर को मुख्यधारा से जोड़ना: जोखिम से समुत्थानशीलता तक' और 'सतत् विकास के लिए आपदा जोखिम में कमी: 2030 तक समुत्थानशील भारत का निर्माण' विषयों पर क्रमश: 2013 एवं 2017 में दो एनपीडीआरआर बैठकों के सफल समापन के बाद, एनपीडीआरआर की तीसरी बैठक **'जलवायु परिवर्तन में स्थानीय समुत्थानशीलता का निर्माण'** विषय पर 10-11 मार्च 2023 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है।



बैठक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, डॉ. पी के मिश्रा, पीएमओ में माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने किया। एनपीडीआरआर के सदस्यों के साथ-साथ 1200 से अधिक विशेषज्ञ/प्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रतिनिधि, शिक्षा जगत, विश्वविद्यालय, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र संगठन, शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत और मीडिया ने बैठक के सत्रों में भाग लिया।

इस बैठक में आपदाओं के खिलाफ स्थानीय परिपुष्टि बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, खासकर प्रधान मंत्री के आपदा जोखिम प्रबंधन पर एजेंडा 10 पर विशेष ध्यान देते हुए और इसके संबंध में सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (एसएफडीआरआर), पेरिस क्लाइमेट समझौता और सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के एकीकृत कार्यान्वयन के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।

तीसरे सत्र ने विभागों, राज्य और संघ शासित प्रदेशों, शहरी और ग्रामीण स्वयं प्रशासन, शैक्षिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, सीएसओ, पीएसयू और समुदायों के बीच आपदा प्रबंधन के मानक अभ्यास को मुख्यधारा में लाने में मदद की। इसे गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें चार प्लेनरी सत्र, एक मंत्रिसभा सत्र, और आठ विषयवार सत्र शामिल थे। उद्घाटन सत्र के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक विशेष मंत्रिस्तरीय सत्र का आयोजन किया गया जिसमें केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने विभिन्न स्तरों पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणालियों को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया।

पूर्ण सत्र: दो दिनों के दौरान चार पूर्ण सत्र आयोजित किये गये:



- **उद्घाटन सत्र:** इस सत्र की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, डॉ. पी के मिश्रा, प्रधान सचिव, पीएमओ और माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा, गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, और सदस्य सचिव, एनडीएमए श्री कमल किशोर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
- **जोखिम प्रशासन:** स्थानीय स्तर पर गहराते आपदा जोखिम का प्रबंधन
- **सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में डीआरआर को मुख्यधारा से जोड़ना**
- **समापन सत्र:** प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री पीके मिश्रा ने समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने सत्र के विषय 'जलवायु परिवर्तन में स्थानीय समुत्थानशीलता का निर्माण' के महत्व को रेखांकित किया क्योंकि यह ऐसे समय में स्थानीय आपदा जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रतिक्रिया करता है जब आपदा जोखिम न केवल बढ़ रहे हैं बल्कि जोखिमों के नए पैटर्न उभर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के 10-सूत्रीय एजेंडे का भी उल्लेख किया जो स्थानीय क्षमताओं और पहलों को विशेष रूप से आपदा जोखिम प्रबंधन में महिला नेतृत्व के निर्माण की आवश्यकता पर जोर देता है।

मंत्रिस्तरीय सत्र: राज्यों में आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना



माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष मंत्रिस्तरीय सत्र आयोजित किया गया था। मंत्रिस्तरीय सत्र के दौरान, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने (उदाहरण के लिए राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की क्षमता बढ़ाकर) से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों की स्थापना, और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य क्षमता निर्माण के मुद्दे जैसे विषय शामिल थे।

6.23 विषयगत सत्र: निम्नलिखित विषयों पर आठ विषयगत सत्र प्रस्तावित थे:

विषयगत सत्र 1: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण: प्रकृति आधारित समाधान



श्री आरआर रश्मी, प्रतिष्ठित फेलो, टीईआरआई, आईएएस (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनबीएस पर नीति और हस्तक्षेप को अलग-अलग तरीकों से निपटाया गया है। उन्होंने जैव विविधता हानि, भूमि क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान पर जलवायु परिवर्तन के दृश्य प्रभावों को संबोधित करने के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा

जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों को एक साथ लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विकास पथों का पुनर्मूल्यांकन करने और प्रौद्योगिकी और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के उपयोग के साथ निरंतर प्रणालीगत परिवर्तन लाने का आह्वान किया।

डॉ. अरुणाभा घोष, सीईईडब्ल्यू, नई दिल्ली ने 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की व्यवहार्यता' पर बात की। उन्होंने सीसीए और डीआरआर, पेरिस समझौते और एसएफडीआरआर के बीच संबंधों पर जोर दिया।

श्री विवेक कुमार, पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 'पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव मिशन' पर ध्यान केंद्रित किया और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में मैंग्रोव संरक्षण के मामले का अध्ययन साझा किया।

श्री रामवीर तंवर, पर्यावरणविद् ने 'आर्द्र भूमि में सुधार एवं सूखे के शमन में इसके प्रभाव' पर अपने विचारों को केंद्रित किया और जल निकायों के अतिक्रमण और सीवरेज निपटान जैसे मानवजनित दबावों के कारण ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में जल निकाय खराब होने पर चर्चा की।

सुश्री राजश्री रे, अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार, एमओईएफसीसी, (सह-अध्यक्ष) ने प्रमुख निष्कर्षों पर अपनी समापन टिप्पणियाँ दीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनबीएस को लागू करने के साथ-साथ प्राकृतिक प्रणालियों से जुड़े जोखिमों को समझने के लिए क्षमता, वित्तीय संसाधनों और प्रौद्योगिकी का मानचित्रण महत्वपूर्ण है।

विषयगत सत्र 2: आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए स्थानीय समुत्थानशीलता का निर्माण

श्री पीएन राय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बीएसडीएमए) के सदस्य और सत्र के अध्यक्ष ने स्थानीय समुत्थानशील को वास्तविकता बनाने के लिए स्थानीय समुदाय के सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे और कौशल में निवेश करने, अच्छी प्रथाओं को साझा करने पर जोर दिया।



श्री राजेंद्र रत्नू सत्र के सह-अध्यक्ष, एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, ने डीआरआर पर प्रधानमंत्री के 10-सूत्री एजेंडे के बिंदु 8 पर जोर दिया, जो स्थानीय समुदायों की क्षमता निर्माण के बारे में चर्चा करता है। उन्होंने जिला, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर समुदायों की क्षमताओं को बढ़ाने और इस तरह स्थानीय समुत्थानशील बनाने के लिए स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया।

डॉ. आलोक रंजन घोष, जिला मजिस्ट्रेट, खगड़िया, बिहार ने बाढ़ के खिलाफ सामुदायिक समुत्थानशीलता बनाने के बारे में बात की और बिहार से उन परिप्रेक्ष्यों को सामने लाया जिसमें बाढ़ से नई जलोढ़ मिट्टी के आने और जल स्तर को बढ़ाने आदि में मदद मिलती है।

श्री क्रिस्पिनो लोबो, वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, अहमद नगर ने सूखे को कम करके और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल भोजन प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया।

डॉ. शेखर लुकोस कुरियाकोस, केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बेहतर, सुरक्षित और समुत्थानशील भविष्य के निर्माण की आवश्यकता का संकेत देते हुए ''बिल्ड फॉरवर्ड बेटर'' की अवधारणा के साथ आवास पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण में हस्तक्षेप पर चर्चा की।

विषयगत सत्र 3: आपदा जोखिम न्यूनीकरण में शहरी जोखिम प्रशासन

श्री मनोज जोशी, सचिव, एमओएचयूए एवं सत्र के अध्यक्ष ने विषयगत सत्र का एजेंडा पेश किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से बदलते जलवायु और आपदा परिदृश्यों से निपटने के लिए योजना और कार्यान्वयन साथ-साथ चलना चाहिए।



श्री हितेश कुमार एस मकवाना, एएस, आपदा प्रबंधन (एमएचए) और सत्र के सह-अध्यक्ष ने हमारे घरों और कस्बों की योजना बनाने के लिए एक सुव्यवस्थित लेकिन पारंपरिक और टिकाऊ दृष्टिकोण विकसित करने पर माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दोहराया।

श्री कुणाल कुमार, मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट शहरों में समुत्थानशीलता हासिल करने पर अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने बताया कि सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ सामग्रियों का टिकाऊ उपयोग स्मार्ट शहरों की संभावनाएं होनी चाहिए।

श्री अंशुल मिश्रा, सदस्य सचिव, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण ने शहरी परिवेश में आपदाओं के कारणों पर प्रकाश डाला। श्री मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि सतत् विकास के माध्यम से समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिए योजना और विकास में डीआरआर शामिल होना चाहिए।

श्रीमती श्रुति नारायण, भारत प्रमुख, शहर-40 ने स्थानीय सरकार को उनकी शहरी योजना और विकास पहल में आपदा जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करने के लिए प्रभावित करके शहरी शासन को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

विषयगत सत्र 4: राष्ट्रीय एकीकृत प्रतिक्रिया प्रणाली का निर्माण

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, सदस्य, एनडीएमए ने फरवरी 2023 में तुर्की में आए भूकंप के बाद विषम परिस्थितियों में राहत और बचाव में मदद के लिए भारत सरकार की ओर से दी गई त्वरित प्रतिक्रिया के बारे में बात की।



संजीव कुमार जिंदल, आपदा प्रबंधन (एमएचए) के संयुक्त सचिव और सत्र के सह-अध्यक्ष ने शमन के मोर्चे पर मजबूती के बारे में बात की। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर ऐसे प्रयास करने पर जोर दिया ताकि एक समुत्थानशील समुदाय विकसित किया जा सके और प्रतिक्रिया के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को कम किया जा सके।

श्री गुरमिंदर सिंह, कमांडिंग ऑफिसर, दूसरी बटालियन, एनडीआरएफ, कोलकाता ने सुझाव दिया कि अंतरराष्ट्रीय मिशनों के लिए प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है।

श्री हेमंत सचदेव, संस्थापक, तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू ने हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रेस्क्यू के बारे में चर्चा की, जिसमें ऊंचाई वाले पर्वतीय बचाव के लिए विभिन्न इलाकों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानने के कौशल की आवश्यकता, बचाव कार्यों के लिए पर्वतारोहियों की पहचान, बेहतर उपकरण और प्रभावी समन्वय और संचार के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन और विकास में दीर्घकालिक रणनीति सुनिश्चित करना शामिल है।

डॉ. सतीश कुमार, एसडीआरएफ, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश एसडीआरएफ टीम की बाढ़ तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जागरूकता पैदा करने, नियमित मॉक ड्रिल और आपदा मित्रों के एकीकरण जैसी आपदा तैयारियों में यूपी एसडीआरएफ टीम की भूमिका पर प्रकाश डाला।

श्री मनु गुप्ता, सीड्स के संस्थापक ने आपदा प्रतिक्रिया में नागरिक समाज की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने सुझाव दिया कि समुदाय-आधारित और गैर-सरकारी संगठनों जैसे नागरिक समाजों को तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास सहित आपदाओं के विभिन्न चरणों में एक साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

विषयगत सत्र 5: क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

श्री सुजान आर. चिनॉय, महानिदेशक, एमपीआईडीएसए एवं सत्र के अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय विदेश नीति में 'वैश्विक भलाई का सिद्धांत' सर्वोपरि रहा है। उन्होंने वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और सहायता पहुंचाने में 'सभी लोगों, सभी क्षेत्रो' के योगदान और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के भारत के दृष्टिकोण को एकीकृत किया।



श्री शोम्बी शार्प, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक एवं सत्र के सह-अध्यक्ष ने कहा कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए देशों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

श्री रंजीत राय, हंगरी, वियतनाम और नेपाल में भारत के (पूर्व) राजदूत ने 2015 के नेपाल भूकंप और भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन मैत्री' पर प्रकाश डाला। उन्होंने भूकंप के दौरान भारत द्वारा अपनाए गए सैन्य-से-सैन्य कूटनीति दृष्टिकोण को रेखांकित किया।

श्री अमित प्रोथी, महानिदेशक, सीडीआरआई, नई दिल्ली ने छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण पर प्रकाश डाला। उन्होंने एसआईडीएस में प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा विकसित करने के महत्व पर जोर दिया और सुझाव दिया कि सीडीआरआई जैसे बहुपक्षीय संगठन इसमें सहायता कर सकते हैं।

श्री कृष्ण वत्स, सदस्य, एनडीएमए ने द्विपक्षीय सहायता, आईटीईसी प्रशिक्षण, आईसीसीआर सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय सहायता पर जोर दिया ।

विषयगत सत्र 6: आपदा शमन और समुत्थानशीलता

श्री कृष्ण एस. वत्स, एनडीएमए के सदस्य और सत्र के अध्यक्ष ने विषयगत सत्र का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि शमन का अर्थ जोखिम को कम करना है, जिसमें संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय शामिल

हैं। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम और ज्ञान विनिमय आयोजित करके इस क्षेत्र में क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।



श्री रंजीत सिन्हा, सचिव, आपदा प्रबंधन, उत्तराखंड और सत्र के सह-अध्यक्ष ने आपदा शमन में समुदायों को शामिल करने की क्षमता की कमी पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोशीमठ भूमि धंसाव मामले का उदाहरण दिया और ऐसे क्षेत्रों में किए जा रहे नए विकास के लिए एक कार्य योजना विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

श्री हर्ष गुप्ता, परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चक्रवात जोखिम शमन परियोजना चरण । और चरण ।। प्रस्तुत किया। उन्होंने इन चरणों के तहत की गई गतिविधियों का उल्लेख किया और एनसीआरएमपी के तीसरे चरण की गतिविधियों का प्रस्ताव रखा।

प्रोफेसर सीवीआर मूर्ति, आईआईटी मद्रास ने भारत में भूकंप सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भूकंप शमन के लिए पर्यावरणीय, तकनीकी, मानव संसाधन बनाने का सुझाव दिया।

श्री कुणाल सत्यार्थी, एनडीएमए के संयुक्त सचिव ने वन अग्नि प्रबंधन पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि वनाग्नि प्रबंधन में जीरो फायर कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने रेखांकित किया कि जंगल की आग का प्रमुख कारण जटिल सामाजिक-आर्थिक स्थिति के साथ-साथ मानवीय लापरवाही भी है।

डॉ. प्रदीप कुमार, सीबीआरआई ने भूस्खलन जोखिम शमन पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि पहाड़ी ढलान प्रबंधन प्रणाली कठिन इलाकों में ढांचागत विकास का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने भूस्खलन के लिए उपलब्ध स्वदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपकरणों/प्रणालियों के उपयोग का सुझाव दिया।

श्री मृत्युंजय महापात्र, महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिजली के जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साझा किया कि बिजली की आवृत्ति उत्तर-पूर्व और पूर्वी भारत में अधिकतम और जम्मू-कश्मीर और भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर अधिक है।

विषयगत सत्र 7: डीआरआर में नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का अनुप्रयोग

डॉ. (श्रीमती) परविंदर मैनी, वैज्ञानिक सचिव, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार एवं सत्र की अध्यक्ष ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) मुद्दों के समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समामेलन की आवश्यकता को रेखांकित किया।



श्री श्रीरंग धावले, क्लस्टर हेड, सोशल सर्विसेज क्लस्टर, टाटा सस्टेनेबिलिटी ग्रुप, टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड एवं सत्र के सह-अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी तकनीकी उन्नति का उद्देश्य सामाजिक विकास होना चाहिए।

श्री शांतनु भटावडेकर, वैज्ञानिक सचिव, इसरो ने प्रारंभिक चेतावनी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति के बारे में बात की। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर डेटा प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुविधाजनक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया, जिसका उपयोग सभी आपदा प्रबंधन चरणों में किया जा सकता है।

डॉ. हरीश गुरुप्रसाद रामास्वामी, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी मद्रास ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एआई को अधिक डेटा प्रदान करने से बेहतर मूल्यांकन और निर्णय लेने और निष्पक्ष निष्कर्ष प्रदान करने में मदद मिल सकती है।

डॉ. मनोज राजन, आयुक्त, कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कर्नाटक सरकार ने खतरे की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के अनुप्रयोग के बारे में बताया।

कर्नल के पी सिंह, एनडीएमए के सलाहकार (ऑपरेशन) ने सीएपी और ईआरएसएस परियोजनाओं के हालिया विकास के बारे में बात की। उन्होंने सीएपी के चरणों, सीएपी के लिए एक नए प्लेटफॉर्म सचेत और इसकी संभावनाओं जैसे अलर्ट जारी करने में मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने के लिए एआई का उपयोग करके तीसरे पक्ष और विरासत प्रणालियों के साथ इसके एकीकरण के बारे में बताया।

विषयगत सत्र 8: आपदा जोखिम न्यूनीकरण में क्षमता निर्माण

श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'भविष्य उनका है जो इसके लिए तैयार रहते है' और इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक तैयारी के लिए एक एकीकृत संस्थागत तंत्र विकसित करने से किसी भी आपदा का प्रभाव कम हो जाता है।



लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) आर.पी. शाही, यूपीएसडीएमए के उपाध्यक्ष ने डीआरआर पर प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे में क्षमता निर्माण और समुत्थानशीलता पर दिए गए महत्व पर प्रकाश डाला।

युवा मामले और खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव **श्री नितेश मिश्रा** ने आपदा प्रबंधन में नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की भूमिका को रेखांकित किया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के **प्रोफेसर संतोष कुमार** ने क्षमता निर्माण ढांचे के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आपदाओं की रोकथाम के उपायों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान देने की जरूरत है।

टीआईएसएस की निदेशक **प्रोफेसर शालिनी भरत** ने एक अकादमिक अनुशासन के रूप में आपदा प्रबंधन और पेशेवर अवसरों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने न केवल प्रतिक्रिया देने के लिए बल्कि जोखिम में कमी और शमन के लिए स्थानीय क्षमताओं में निवेश करने के माननीय प्रधान मंत्री के मार्गदर्शक शब्दों पर जोर दिया।

6.24 एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र के पूर्व आयोजित कार्यक्रम

क) समुत्थानशीलता एवं स्थिरता शिखर सम्मेलन पर चर्चा: परिकल्पना 2047 (पुनर्सम्मेलन 2047), 17–19 जनवरी 2023

एनआईडीएम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) भारत सरकार के सहयोग से, साझेदारों–संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जीआईजेड–भारत और संयुक्त राष्ट्र निकायों, बहु–पक्षीय, अकादमिक, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के अन्य लोगों के साथ मिलकर ''समुत्थानशीलता और स्थिरता शिखर सम्मेलन: विजन 2047 (पुनर्समारोह)'', जलवायु परिवर्तन में डीआरआर के लिए विज्ञान–नीति–योजना–अभ्यास इंटरफेस'' का 17–19 जनवरी 2023 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली, भारत में आयोजन किया। 'पुनर्समारोह2047' विचार–विमर्श से भविष्य के 'जोखिम और समुत्थानशीलता' के प्रमुख संदर्भों की पहचान हुई है। पुनर्समारोह2047, एनपीडीआरआर 2023 का एक बहु–मंत्रालयी और बहु–साझेदार प्री–इवेंट पहल रहा है, जिसमें 'उच्च–स्तरीय पूर्ण सत्र' और तकनीकी 'संवाद–परिसंवाद सत्र' आयोजित किए गए। पुनर्समारोह2047 में 130 वक्ता और 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, 18 केंद्रीय मंत्रालय और यूएडीपी, जीआईजेड, जीईएजी, यूनिसेफ, स्फीयर इंडिया, डब्ल्यूएचओ, एनआईडीएम, वेटलैंड, डीएसटी, स्प्रिंगर सहित भागीदारों के प्रतिनिधि शामिल थे।



ख) बाढ़ की तैयारी और प्रतिक्रिया, 18–19 फरवरी 2023

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (एनपीडीआरआर) 2023 के तीसरे सत्र का प्री–इवेंट असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के सहयोग से केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), जल शक्ति मंत्रालय, स्फीयर इंडिया, ग्रामीण स्वयंसेवी केंद्र और रामकृष्ण मिशन के साथ मिलकर असम प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। कार्यशाला का आयोजन मौजूदा पद्धतियों को समझने और बाढ़ की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए समुत्थानशीलता के एजेंडे को स्थानीय बनाने के लिए रणनीतियों और सिफारिशों को प्राप्त करने और सूक्ष्म प्रौद्योगिकियों के साथ अंतर को पाटने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चर्चा राज्य, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों,



निजी क्षेत्र, ज्ञान संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के प्रगतिशील कार्यों को प्रदर्शित करते हुए बाढ़ की तैयारियों पर केंद्रित रही। श्री सैयदेन अब्बासी, आईएएस, असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि थे, जिन्होंने असम में विभिन्न चुनौतियों और सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में चर्चा की। एएसडीएमए और यूनिसेफ प्रतिनिधियों ने सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बेहतर बनाने के लिए आपदा प्रतिरोध और सामुदायिक समर्थन के लिए दस्तक देने वाले सामाजिक संरक्षण उपायों के महत्व पर भी जोर दिया।

ग) समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, 20 फरवरी 2023



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूपीएसडीएमए), सीड्स इंडिया और आगा खान फाउंडेशन के साथ साझेदारी में यूपीएसडीएमए, लखनऊ में एनपीडीआरआर का एक प्री-इवेंट आयोजित किया। प्री-इवेंट का विषय समुदाय-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीबीडीआरआर) था। जलवायु समुत्थानशीलता हासिल करने के लिए विभिन्न सीबीडीआरआर पहलों पर चर्चा की गई और इस कार्यक्रम में 29 अधिकारियों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन यूपीएसडीएमए के माननीय उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आर पी शाही ने किया। श्रीकृष्ण वत्स, सदस्य एनडीएमए ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और विशेष संबोधन दिया जिसने पूरे कार्यक्रम को दिशा दी। सीड्स इंडिया के श्री मनु गुप्ता ने कार्यक्रम के दौरान मुख्य भाषण दिया।

घ) आपदा जोखिम शमन और जलवायु निर्माण के लिए जोखिम वित्तपोषण और बीमा जोखिम समुत्थानशीलता, 20-21 फरवरी, 2023



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय बीमा अकादमी ने होटल प्रेसिडेंट, कफ परेड, मुंबई में ''जलवायु जोखिम समुत्थानशीलता के निर्माण के लिए अभिनव जोखिम हस्तांतरण'' पर एक प्री-इवेंट कार्यशाला का आयोजन किया। सामुदायिक जलवायु जोखिम-निर्माण उद्देश्यों के महत्व को समझते हुए, प्री-इवेंट एक आपदा प्रबंधन चक्र के विषय पर आधारित था जिसमें रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया, शमन, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण शामिल थे। बीमा तैयारियों और पुनर्प्राप्ति में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। आपदा के जोखिम प्रबंधन में बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीमा कवर यह सुनिश्चित करता है कि आपदा की स्थिति में आबादी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। जबकि बीमा आपदा के बाद की वसूली के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है, यह आपदा जोखिम को कम करने में भी भूमिका निभा सकता है।

(ड.) तटीय क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता, 23-24 फरवरी 2023

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर) के तीसरे सत्र का प्री-इवेंट कृषि भवन भुवनेश्वर, ओडिशा में

आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) द्वारा आयोजित प्री-इवेंट का विषय तटीय क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता था। इस अवसर पर एनडीएमए, एनआईडीएम, तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गणमान्य व्यक्ति, शिक्षाविद्, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।



च) आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व, 24 फरवरी 2023

देश में आपदा प्रबंधन संरचना और संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता को संबोधित करने और संघीय राजनीति को और मजबूत करने और बड़े पैमाने पर समुदाय के हित में स्थानीय क्षमताओं का निर्माण करने के लिए एनआईडीएम, टीआईएसएस और महिला हाउसिंग ट्रस्ट के सहयोग से ''डीआरआर में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व'' पर एक पूर्व-कार्यक्रम/परामर्श आयोजित किया गया। परामर्श का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में महिलाओं की भूमिका और रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति की निरंतरता में समुत्थानशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट मुद्दों, अच्छी प्रथाओं और अवसरों पर विचार-विमर्श करना था। हितधारकों ने व्यापक, समसामयिक और लैंगिक समावेशी अनुशंसाओं को तैयार करने के लिए अपने कार्यक्रमों से अच्छी प्रथाओं को साझा किया, जिसने राष्ट्रीय डीआरआर नीति को बढ़ाया और महिलाओं और महिला संगठनों की आवाज, क्षमताओं, नेतृत्व और एजेंसी का लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त किया।



छ) पहाड़ों में आपदा समुत्थानशीलता: क्षमता निर्माण की आवश्यकता, 24 फरवरी 2023

डॉ. आर.एस.टी. उत्तराखंड प्रशासन अकादमी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से ''पहाड़ों में आपदा समुत्थानशीलता'' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जो राष्ट्रीय मंच की तीसरी बैठक की पूर्व-इवेंट थी। कार्यशाला में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पर्वतीय राज्यों की क्षमता निर्माण के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला में हितधारकों की तैयारी और शमन के लिए क्षमता निर्माण में चुनौतियों और कमियों, संस्थागत प्रक्रियाओं को मजबूत करने के विभिन्न तरीकों, जमीनी स्तर पर विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण पर चर्चा करने के लिए हिमालयी राज्यों और संगठनों के विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आज के खतरे कल की आपदा में नहीं बदलें।



ज) आपदा अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन, 25 फरवरी 2023



प्री-इवेंट डिजास्टर रिसर्च एंड न,लेज मैनेजमेंट का आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तिरुवरूर द्वारा किया गया था। कार्यशाला में शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, प्रशासकों और नीति नियोजकों सहित (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) विभिन्न क्षेत्रों से बहु-हितधारकों को चर्चा करने, विचार-विमर्श करने और व्यावहारिक समाधान और नीति-स्तरीय पहल को साथ लाने के लिए एकजुट किया गया जो किसी भी प्रकार की आपदाओं के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया दृष्टिकोण को आकार देने में मदद करे ताकि आपदा प्रबंधन में ज्ञान सृजन और अनुसंधान का एक नेटवर्क स्थापित किया जा सके।

झ) आपदा के बाद उबरने में आजीविका के उपाय, चंडीगढ़, 28 फरवरी 2023

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तीसरे राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर-3) सत्र के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में आपदा के बाद उबरने में आजीविका का आयोजन महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एमजीएसआईपीए) ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ मिलकर एमजीएसआईपीए में आयोजित किया। कार्यशाला का उद्देश्य आपदा के बाद के चरणों में आजीविका के अवसरों की कमी के कारण पलायन के मुद्दे पर समुत्थानशीलता में सुधार पर विचार-विमर्श करना था। प्रमुख प्रतिभागियों में राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारी जैसे आपदा प्रबंधन व्यवसायी, योजना अधिकारी, राजस्व अधिकारी, शहरी योजनाकार, इंजीनियर, वास्तुकार, आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षक, राज्य संस्थान, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, पुलिस सहित विभिन्न लाइन विभागों के मध्य स्तर के अधिकारी जिनमें अग्नि, वन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, नगर पालिकाएँ, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के सदस्य शामिल हैं।



ण) जलवायु और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सशक्तिकरण, 03 मार्च 2023



एनआईडीएम-यूनिसेफ और भागीदारों के एक बड़े समूह ने 3 मार्च 2023 को एनपीडीआरआर साइड इवेंट के रूप में मुलाकात की। साइड इवेंट (गोलमेज) जलवायु और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने पर केंद्रित था। यह कार्यक्रम हाई-प्रोफाइल था और इसे भारत की जी20 अध्यक्षता और आपदा जोखिम प्रतिरोधी (डीआरआर) कार्य समूह पर विचार-विमर्श में योगदान देने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें शॉक रिस्पॉन्सिव सोशल प्रोटेक्शन प्रमुख विषयों में से

एक है। इस आयोजन में भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ-साथ अनुसंधान संगठनों, आईएफआई, सीएसओ और जोखिम वाले या आपदाओं से प्रभावित समुदायों की भागीदारी देखी गई।

ट) आपदा जोखिम न्यूनीकरण में शहरी जोखिम प्रशासन और क्षमता निर्माण, 04 मार्च 2023



राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (एनपीडीआरआर) 2023 के तीसरे सत्र के लिए एक राष्ट्रीय प्री-इवेंट दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा स्फीयर इंडिया के साथ सहयोगात्मक साझेदारी में आयोजित किया गया था, और इसे प्लान इंडिया द्वारा समर्थन दिया गया था। यह कार्यक्रम ''शहरी जोखिम प्रशासन और डीआरआर में क्षमता निर्माण'' पर केंद्रित था। प्री-इवेंट में दो तकनीकी सत्र थे जो डीआरआर में शहरी समुत्थानशीलता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित थे। चर्चा सीसीए और डीआरआर को मुख्यधारा में लाने, संस्थानों और स्वैच्छिक समूहों को मजबूत करने और क्षमता निर्माण में शिक्षा जगत की भूमिका जैसे उप-विषयों पर केंद्रित रही। कार्यक्रम का समापन एक समूह गतिविधि के साथ हुआ जहां प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के उप-विषयों पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राज्य और राष्ट्रीय मंच के लिए अपने अनुभवों और अनुशंसाओं को व्यक्त किया।

ठ) आपदा से होने वाले खतरे से उबरने के उपाय एवं पुनर्निर्माण, 06 मार्च 2023

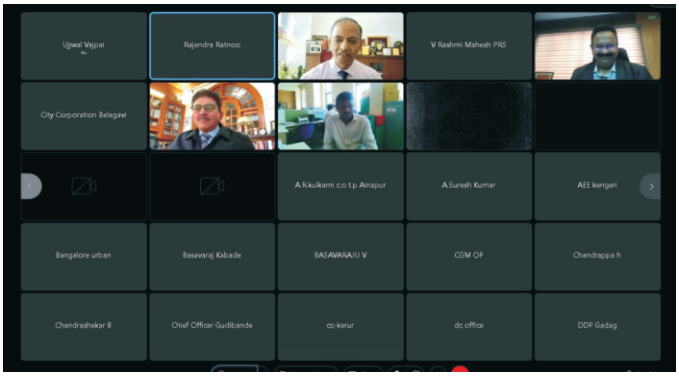


विश्व बैंक के सहयोग से एनआईडीएम ने नई दिल्ली में ''आपदा से होने वाले खतरे से उबरने के उपाय एवं पुनर्निर्माण'' पर एक प्री-इवेंट आयोजित किया। यह कार्यक्रम एक प्री-इवेंट था जिसमें जी20 डीआरआर कार्य समूह के प्राथमिकता अंक 3% आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मजबूत राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे की जानकारी देने के लिए राज्यों और राष्ट्रीय सरकार द्वारा बेहतर आर्थिक प्राथमिकता और वित्तीय योजना को सूचित करने के लिए भारत में पीडीएनए और पुनर्प्राप्ति योजना के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को मजबूत करने पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को एक साथ लाने का प्रयास किया गया था। इस आयोजन की कार्यवाही जी20 के मुख्य आयोजन को सूचित करेगी, जिसमें पीडीएनए और दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए क्षमता निर्माण प्रक्रिया का विकास भी शामिल है।

ड) शहरी बाढ़ में सामुदायिक समुत्थानशीलता का निर्माण, 06 मार्च 2023

कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) के साथ एनआईडीएम ने एक प्री-इवेंट, ''शहरी बाढ़ में सामुदायिक समुत्थानशीलता का निर्माण'' का आयोजन किया, जिसका प्रतिनिधित्व कर्नाटक सरकार के संरक्षक के रूप में डॉ. मनोज राजन, आयुक्त, केएसडीएमए, राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन), सुश्री वी. रश्मि महेश, राहत आयुक्त सह प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग (आपदा प्रबंधन) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) का प्रतिनिधित्व प्रोफेसर चंदन घोष प्रमुख-रेजिलिएंट

इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन, एनआईडीएम, एमएचए, भारत सरकार और श्री राजेंद्र रत्नू, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, एमएचए, भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा किया गया।



6.25 एनपीडीआरआर के दौरान प्रदर्शनी (10–13 मार्च 2023)



10–11 मार्च 2023 को, एनपीडीआरआर की तीसरी बैठक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने अपने विभिन्न प्रकाशनों को प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जिसमें प्रशिक्षण मॉड्यूल, केस स्टडी रिपोर्ट, कार्यवाही, जर्नल 'आपदा और विकास', आईईसी सामग्री शामिल है। प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, शिक्षा जगत, विश्वविद्यालयों, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र संगठनों, शहरी स्थानीय निकायों और मीडिया के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों ने एनआईडीएम स्टॉल का दौरा किया। आपदा प्रबंधन के विभिन्न विषयों की पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई।

इसके अलावा, विभिन्न स्कूलों से बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने-अपने शिक्षकों के साथ इस प्रदर्शनी में भाग लिया। कुल मिलाकर, क्षमता निर्माण प्रयासों, अनुसंधान कार्यक्रमों और साझेदारी के लिए संचार प्रबंधन गतिविधियों पर एनआईडीएम प्रकाशनों के डिजिटल संस्करण के माध्यम से अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया।





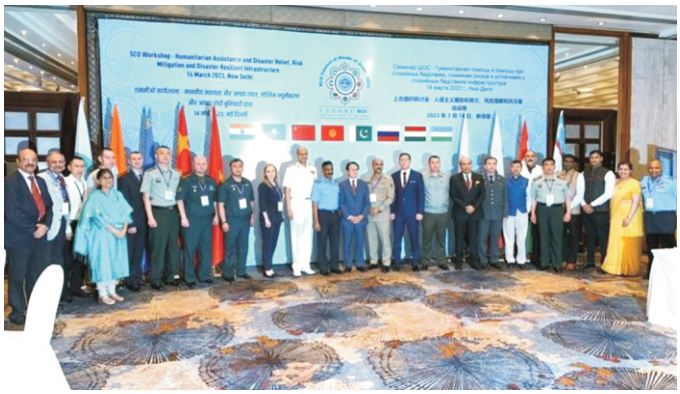




अन्य गतिविधियों

1. 14 मार्च 2023 को, नई दिल्ली, श्री राजेंद्र रत्नू, ईडी एनआईडीएम ने मानवीय सहायता और आपदा राहत, जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर कार्यशाला के पहले सत्र, ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण और उन्नत समुत्थानशीलता'' की अध्यक्षता की जिसका आयोजन मुख्यालय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इंडिया, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स निदेशालय, भारत के रक्षा मंत्री के कार्यालय द्वारा भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की एससीओ सदस्य देशों और पर्यवेक्षक सदस्यों की भागीदारी के साथ किया गया।







2. सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी) पुणे परिसर का दौरा, 17 मार्च 2023– पोस्ट ग्रेजुएट सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज (एएफएमसी) पुणे के छात्रों ने 17 मार्च 2023 को एनआईडीएम रोहिणी परिसर का दौरा किया। इसके बाद रोहिणी नई दिल्ली में एनआईडीएम के परिसर में कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम के संक्षिप्त संबोधन के साथ इसका समापन हुआ।



3. 20 मार्च 2023 को नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीमीडिया, दिल्ली में, श्री राजेंद्र रत्नू ईडी एनआईडीएम ने ''आपदा के दौरान प्रसारण प्रबंधन'' पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय आपदा संचार नीति-अवलोकन पर मुख्य भाषण दिया।









4. जनस्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) के लिए क्षमता निर्माण के पहलुओं को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 23 मार्च 2023 को एनआईडीएम रोहिणी परिसर में श्री राजेंद्र रत्नू, ईडी एनआईडीएम, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, प्रमुख, जीएमआरडी और यूएस-सीडीसी भारत और एनसीडीसी के अधिकारियों के बीच एक सार्थक बैठक हुई।





5. एनआईडीएम और जीआईजेड इंडिया प्रतिनिधिमंडल 27 मार्च 2023 को श्री राजेंद्र रत्नू ईडी एनआईडीएम के नेतृत्व में सतत् शहरी विकास- स्मार्ट सिटी ।। परियोजना के लिए अनुदान आवंटन पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। बैठक में

बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा हुई। सतत् शहरी विकास-स्मार्ट सिटीज ।। के बारे में जीआईजेड इंडिया के साथ बैठक में प्राथमिक कार्य पर चर्चा हुई, जिसमें सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे के विकास में डीआरआर उपायों को शामिल करने के लिए विभिन्न राज्यों से पांच स्मार्ट शहरों का चयन किया गया।





आगरा में संयुक्त एचएडीआर कार्यक्रम में भागीदारी

- डॉ. अमीर अली खान को 28-30 नवंबर, 2022 को वायु सेना स्टेशन, आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) पूर्व समन्वय-2022 में भाग लेने के लिए संस्थान द्वारा नामित किया गया था। उन्होंने डीएम क्षमताओं और भूकंप और भूस्खलन क्षति शमन और प्रबंधन का अवलोकन' पर प्रस्तुति किया।

डोडा जिले का फील्ड दौरा

- नई बस्ती हेमलेट, थाथरी तहसील, डोडा जिला, जम्मू में भूमि धंसाव/भूस्खलन गतिविधियों का अध्ययन और निरीक्षण करने के लिए एनआईडीएम के सदस्य के रूप में डॉ. सूर्य प्रकाश और डॉ. अमीर अली खान की अध्यक्षता में एनडीएमए द्वारा गठित विशेषज्ञ टीम ने 18-19 फरवरी, 2022 को फील्ड दौरा किया।

*****

अध्याय 7

वित्त और लेखा

वित्त और लेखा

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

एच के कोतावालिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

बी-2ए/31, जनक पुरी, मेट्रो पिलर नं. 536, नई दिल्ली-110058
दूरभाष: 011-41650299 मोबाइल: +91-9810450299, 9999701196
ई-मेल: kotwalia@gmail.com / khurana@hkkotwalia.com
sneha@hkkotwalia.com Web.: www.hkkotwalia.com

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (''संस्था'') की 31 मार्च 2023 तक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें इस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष का तुलन-पत्र, आय और व्यय खाते, प्राप्ति और भुगतान खाता तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश और अन्य स्पष्टीकरण जानकारी शामिल है। हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं तथा संलग्नक 'क' में दी गई टिप्पणियों को छोड़कर, सही और निष्पक्ष मत परिलक्षित करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के आधार पर हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के ''वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व'' खण्ड में भी स्पष्ट किए गए हैं। वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से सम्बद्ध नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप हम संस्था से स्वतंत्र हैं, और हमने अपने अन्य उत्तरदायित्वों का निर्वहन

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

इन नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप किया है। हमारा विश्वास है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे हमें हमारा अभिमत व्यक्त करने के आधार के रूप में पर्याप्त और समुचित हैं।

प्रबंधन एवं वित्तीय विवरण के उत्तरदायित्व: वित्तीय विवरण तैयार करने और ऐसे आंतरिक नियंत्रण सृजित करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर होगा, जो कि उसके अनुसार ऐसा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है जिसमें कोई मिथ्या कथन न हो, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से हो। वित्तीय विवरण तैयार करने में, यथा प्रयोज्य, चालू व्यापार लेखांकन आधार और चालू व्यापार से सम्बद्ध मुद्दों को उद्घाटित करते हुए यह प्रबंधन का उत्तदायित्व होगा कि वह संस्था की क्षमता का आकलन करे कि वह अपना व्यापार (गतिविधियां) चालू रखने में सक्षम है; बशर्ते प्रबंधन का इरादा संस्था के परिसमापन, अथवा संचालन बंद करने, अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प न हो। संस्था के संचालकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे संस्था की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की निगरानी करें।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सम्बंध में लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व:

हमारे उद्देश्य ये हैं कि हम एक उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण में कोई मिथ्या कथन नहीं है चाहे यह किसी धोखाधड़ी के कारण हो अथवा किसी त्रुटि के कारण, और तद्नुसार एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें हमारा अभिमत शामिल हों, उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है, परन्तु यह इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव वित्तीय विवरण में दिए गए किसी मिथ्या कथन को ढूंढ ही लेगी। मिथ्या कथन किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो सकते हैं; और इन्हें तब तथ्यात्मक माना जाता है, जब व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से प्रयोक्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को इनके द्वारा काफी हद तक प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमने व्यवसायिक तर्कशीलता का उपयोग करते हुए और व्यवसायिक संशय बनाए रखते हुए लेखा परीक्षा निष्पादित की।

हमने यह कार्य भी किए:-

- वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध मिथ्या कथन को चिह्नित करना तथा उसका आकलन करना, चाहे यह किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण से हो, इन जोखिमों के अनुरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत के प्रकटीकरण के लिए पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते हों। तथ्यात्मक मिथ्या कथन की अपेक्षा किसी धोखाधड़ी के कारण किए गए तथ्यात्मक मिथ्या कथन को न ढूंढ पाने का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, आन्तरिक चूक, गलत प्रस्तुतिकरण अथवा आन्तरिक नियन्त्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- अपनी लेखा परीक्षा को डिजाइन करने के लिए सुसंगत ऐसी आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई जो कि इन परिस्थितियों के अनुरूप है, परन्तु जिसका उद्देश्य संस्था के आन्तरिक नियन्त्रण की प्रभावशीलता पर मत व्यक्त करना नहीं था;
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन, प्राक्कलनों की व्यवहारिकता और सम्बद्ध प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना;
- प्रबंधन द्वारा चालू व्यापार लेखांकन आधार के प्रयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या कोई ठोस अनिश्चितता ऐसी घटनाओं और परिस्थितियों के सबंध में विद्यमान है जो

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

संस्था की चालू व्यापार क्षमता पर उल्लेखनीय शंका पैदा कर सकती है। अगर हम ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ठोस अनिश्चितता वास्तव में विद्यमान है; तो हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में दिए गए ऐसे प्रासंगिक प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकृष्ट करवाना आवश्यक है; और अगर यह प्रकटीकरण अपर्याप्त है; तो अपने अभिमत को तदनुसार संशोधित करेंगे। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार होने तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य में व्याप्त होने वाली घटनाओं और परिस्थितियां संस्था के चालू व्यापार अस्तित्व को समाप्त कर सकती है।

अन्य मुद्दों के अतिरिक्त, नियोजन दायरे, लेखा परीक्षा के समय तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमारे द्वारा चिह्नित आन्तरिक नियन्त्रण से सम्बन्धित किसी विशिष्ट त्रुटि के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के सम्बंध में हम संस्था के संचालकों के साथ निरंतर सम्पर्क में रहे ।

कृते एच के कोतावालिया एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजि. सं.. 015187-N

राजेश खुराना

पार्टनर

सदस्यता संख्या- 095946

यूडीआईएन : 23095946BGYADW5807

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 16.10.2023

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक 'क'

लेखा परीक्षा टिप्पणियां/अर्हतायें

1. **भारत में सामान्यत:** स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप संस्थान के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियों का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रबंधन ने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्राप्ति आधार अपनाया है (स्थापना व्यय, किराया, दर तथा कर, सहायता अनुदान के अतिरिक्त जिनका लेखा-जोखा नकदी के आधार पर रखा जाता है) जिसके कारण प्राप्ति संकल्पना नीति और टीडीएस प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

2. स्रोत पर कर के रूप में काटी गई 2,59,257.65 रुपए की राशि लम्बे समय से बही में दर्ज है और वसूली योग्य नहीं है।

3. संस्थान ने मात्रात्मक विवरण और स्थायी परिसम्पत्तियों की स्थिति को दर्शाते हुए सम्पूर्ण विवरण तैयार नहीं किया है। सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पण

अनुसूची 1

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) वित्तीय विवरण प्राप्ति आधार पर प्राचीन लागत परंपरा के अनुसार तैयार किए जाते हैं (स्थापना व्यय, किराया, दर तथा कर, सहायक अनुदान जिसका हिसाब नकद आधार पर किया जाता है) और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुसार होते हैं।

ख) स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर भौतिक सत्यापन के लिए रखा जा रहा है और परियोजना के अंतर्गत अर्जित सभी स्थिर परिसंपत्तियों को उस वित्तीय वर्ष, जिसमें वह आस्ति प्राप्त की गई थी, में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की लेखा बही में रखा जाता है। स्थिर आस्तियों की प्राप्ति की लागत और स्थापना की लागत, यदि हो, के साथ एक वर्ष में प्रभारित अवमूल्यन से घटाकर लिखा जाता है। स्थिर आस्तियों पर अवमूल्यन का प्रावधान आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाता है।

ग) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च 2017 के पत्र संख्या एफ. नंबर 45-16/2012-एनडीएम-।। के अनुसार एनडीआई ने 3 कर्मचारियों (जिनमें से एक दिसंबर 2019 में सेवानिवृत हो गए) जिन्होंने एनपीएस में राशि जमा करने का विकल्प नहीं दिया है, को छोड़कर 27 में से 24 कर्मचारियों की राशि एनपीएस खाते में जमा की है। तथापि, जिन कर्मचारियों ने सेवा छोड़ दी है, अदालत में विचाराधीन और निधन के मामले, उनकी राशि (कर्मचारी एवं नियोक्ता का अंशदान) एनआईडीएम के बैंक खाते में है ।

घ) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुन: व्यवस्थित/पुन: समूहीकृत किया गया है।

ड.) एनआईडीएम और एनडीएमसी के बीच किराया करार पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। एनआईडीएम ने नवंबर 2017 से अक्टूबर 2019 तक की अवधि के लिए गृह मंत्रालय और एनडीएमसी के मध्य अनुबंध कृत दर पर किराए का भुगतान कर दिया है।

च) संस्थान का 1 चालू खाता और 2 बचत खाते और 1 पीएफएमएस से जुड़ा बचत खाता है।

छ) जिन लेखांकन नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है वे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुरूप हैं।

2. आकस्मिक देयताएं

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में मान्यता नहीं दी गई – शून्य।

3. प्रबंधन की राय में व्यापार के सामान्य क्रम में वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम वसूली का मूल्य राशि से कम नहीं होगा जो बैलेंस शीट में दर्शायी गई है। सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान लेखा में किया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

4. गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के दिनांक 23 मार्च, 2010 के पत्र संख्या 45-5/2008-एनडीएम-IV/II के अनुसरण में, एक अलग पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए) बनाया गया है और जमा से प्राप्त ब्याज सहित परियोजनाओं से सृजित निवल बचत भारत की संचित निधि में जमा कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पीएलए के वित्तीय विवरण अलग से तैयार किए गए हैं।

महत्वपूर्ण लेखांकन और नीतियों और लेखा टिप्पणी

एच के कोतावालिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 015187N

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-
राजेश खुराना
(पार्टनर)
एम.नं. 095946

हस्ताक्षर/-
राजेन्द्र रत्नू
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

दिनांक: 16.10.2023
स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

31 मार्च, 2023 तक का बैलेंस शीट

(राशि)

विवरण	अनुसूची	31.03.2023	31.03.2022
संचित निधि/पूंजी कोष और देयताएं			
आरक्षिती और अधिशेष	2	1,16,97,76,006.65	1,14,24,22,710.41
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	7,48,30,594.15	6,26,88,164.14
कुल		**1,24,46,06,600.80**	**1,20,51,10,874.55**
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	4	1,05,85,44,974.14	1,03,96,32,858.14
निवेश	5	14,75,60,298.99	13,85,43,406.00
वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	6	3,85,01,327.67	2,69,34,610.41
कुल		**1,24,46,06,600.80**	**1,20,51,10,874.55**

महत्वपूर्ण लेखांकन और नीतियों और लेखा टिप्पणी

एच के कोतावालिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 015187N

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-
राजेश खुराना
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 095946
यूडीआईएन: 23095946BGYADW5807

हस्ताक्षर/-
राजेन्द्र रत्नू
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16.10.2023

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आय और व्यय का लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2023	31.03.2022
आय/अनुदान (गृह मंत्रालय से)			
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	7	32,00,00,000.00	30,00,00,000.00
कुल क		**32,00,00,000.00**	**30,00,00,000.00**
व्यय (गृह मंत्रालय अनुदान)			
स्थापना व्यय	8	8,04,98,835.00	8,32,55,883.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	9	15,73,08,494.76	14,59,40,183.67
प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	10	8,71,44,605.00	3,66,36,682.00
अवमूल्यन	4	61,94,769.00	63,19,466.00
कुल ख		**33,11,46,703.76**	**27,21,52,214.67**
पूर्व अवधि और असाधारण मदों से पहले गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने के कारण शेष राशि		**(1,11,46,703.76)**	**2,78,47,785.33**
घाटा: पूर्व अवधि व्यय	–	–	
गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने पर शेष		**(1,11,46,703.76)**	**2,78,47,785.33**

महत्वपूर्ण लेखांकन और नीतियों और लेखा टिप्पणी

एच के कोतावालिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 015187N

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/–
राजेश खुराना
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 095946
यूडीआईएन: 23095946BGYADW5807

हस्ताक्षर/–
राजेन्द्र रत्नू
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर/–
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16.10.2023

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
प्राप्तियां				
अथशेष				
यूको बैंक खाता संख्या 18200200000924	1,45,00,000.00		2,00,76,523.33	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 40256508810	86,09,854.76		--	
यूको बैंक खाता संख्या 182001100067819	(3,63,78,127.14)	**(1,32,68,272.38)**	25,787.80	2,01,02,311.13
प्रान्त अनुदान				
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	32,00,00,000.00		30,00,00,000.00	
दक्षिणी परिसर के निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान	3,85,00,000.00		--	
		32,85,00,000.00		**30,00,00,000.00**
बैंक ब्याज अन्य	773.00		715.00	
ब्याज (पूंजी शीर्ष)	30,56,421.00		6,33,623.00	
एफडी पूंजी शीर्ष ऑटो स्वीप	--		7,47,33,065.00	
त्योहार के लिए अग्रिम	--		54000.00	
पीएलआई खाते	--		8338.00	
आकस्मिक अग्रिम	63,039.00		--	
अग्रिम एलटीसी	80220.00		1,96,696.00	
सीजीएचएस खाते	--		25650.00	
विविध प्राप्तियां	15,85,312.15		--	
अग्रिम राशि	--	**47,85,765.00**	85,000	**7,57,37,087.00**
एनपीएस के लिए कर्मचारी अंशदान	2,56,166.00	**2,56,166.00**	2,38,142.00	**2,38,142.00**
कुल		**35,02,73,658.77**		**39,60,77,540.13**
भुगतान				
पूंजी व्यय/अन्य देयताएं				
फर्नीचर और फिक्सर	--		86,84,784.00	
कार्यालय उपकरण	19,88,740.00		1,27,65,859.00	
निर्माणाधीन भवन (दक्षिणी परिसर)	10,56,789.00		2,66,62,729.00	
निर्माणाधीन भवन (रोहिणी परिसर)	48,93,708.00		3,48,68,630.84	
पुस्तकें	4,44,393.00		8,58,196.00	
लेनदार	(45,778.00)		--	
कम्प्यूटर	5265.00	**83,43,117.00**	49,69,088.00	**8,90,09,286.84**
राजस्व व्यय				
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	4,66,53,502.00		3,19,85,121.00	
एलटीसी अग्रिम	3,28,000.00		--	
टीडीएस खाता	--		183	
स्थायी जमा	65,64,026.99		1,45,61,824.00	
स्थायी जमा (निधि)	--		75,00,000.00	

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
पीएलए खाता	--		59,000.00	
आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	2,29,020.00		44,926.00	
ईएमडी धनवापसी	25,000	**5,37,99,548.99**	--	**5,41,51,054.00**
स्थापना व्यय				
वेतन और भत्ते	7,05,00,262.00		7,07,92,620.00	
यात्रा रियायत भत्ता/एलटीए	5,43,988.00		7,43,204.00	
मेडिकल	5,00,352.00		5,58,336.00	
पेंशन अंशदान	6,44,965.00		28,04,669.00	
		7,21,89,567.00		**7,48,98,829.00**
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मरम्मत और रखरखाव	1,11,98,589.00		95,21,661.00	
विद्युत व्यय	51,40,138.00		31,77,698.00	
डाक	1,97,591.00		1,26,270.00	
हॉस्टल संचालन/रखरखाव	40,48,641.00		--	
मुद्रण और स्टेशनरी	10,68,078.00		6,15,953.00	
किराया, दर और कर	11,28,74,208.00		10,47,81,914.00	
विविध व्यय	8,12,632.00		24,27,534.00	
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	1,57,325.00		44,805.00	
टेलीफोन व्यय	30,73,127.00		9,33,759.00	
जल का शुल्क	58,595.00		3,63,140.00	
घरेलू यात्रा	27,16,353.00		24,23,328.00	
एनपीडीआरआर व्यय	1,04,96,549.00		--	
व्यवसायिक शुल्क	58,85,746.00		60,88,221.00	
पुस्तकालय/प्रकाशन	16,98,678.00		14,59,228.00	
बैंक शुल्क	3105.76		8,703.67	
अनुसंधान और विकास	14,55,000.00		37,23,574.00	
कार्यालय वाहन मरम्मत व्यय	1,19,445.00		2,27,208.00	
देय खर्चे	1,11,98,576.00	**17,22,02,376.76**	88,55,036.00	**14,47,78,032.67**
सरकार को भुगतान				
एनपीएस ट्रस्ट को भुगतान (सीपीएफ)	--		55208.00	
देय खर्चे- एनबीसीसी (पूंजी शीर्ष)	--		3,16,96,575.00	
पीएओ, मंत्रीमंडलीय मामले (श्री आशीष के. पांडा)	--		1000.00	
देय एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान	39,15,048.00		35,03,690.00	
सरकार को अतिरिक्त आय का भुगतान	18,47,682.00	**57,62,730.00**	1,12,52,137.00	**4,65,08,610.00**
अंतिम शेष				
यूको बैंक खाता संख्या 182001100067819	3,85,25,756.02		(3,63,78,127.14)	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 40256508810	(5,49,437.00)		86,09,854.76	
यूको बैंक खाता संख्या 18200200000924	--	**3,79,76,319.02**	1,45,00,000.00	**(1,32,68,272.38)**
कुल		**35,02,73,658.77**		**39,60,77,540.13**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

सलंग्न सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

एच के कोतावालिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 015187N

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-

राजेश खुराना
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 095946
यूडीआईएन: 23095946BGYADW5807

हस्ताक्षर/-

राजेन्द्र रत्नू
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर/-

सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16.10.2023

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
अनुसूची 4: 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्थिर आस्तियों और अवमूल्यन का विवरण

क्र.सं.	विवरण	दर	01.04.2022 को डब्ल्यूडीवी	परिवर्धन		कटौती	कुल	वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2023 को डब्ल्यूडीवी
				180 दिन से अधिक	180 दिन से कम				
			रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1	पुस्तकें	40%	25,03,839.00	2,29,217.00	2,16,471.00	1,295.00	29,48,232.00	11,38,258.00	18,11,974.00
2	कार्यालय उपकरण	15%	89,79,217.00	4,81,790.00	15,06,950.00	–	1,09,67,957.00	15,32,172.00	94,35,785.00
3	फर्नीचर और उपस्कर	10%	86,31,299.00	--	--	--	86,31,299.00	8,63,130.00	77,68,169.00
	संयंत्र और मशीनरी								
4	संयत्र और मशीनरी	15%	2,35,657.00	–	--	–	2,35,657.00	35,349.00	2,00,308.00
5	वाहन (मारूति सियाज)	15%	4,23,023.00	–	–	–	4,23,023.00	63,453.00	3,59,570.00
	कंप्यूटर								
6	कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	40%	64,05,746.00	5,265.00	--	--	64,11,011.00	25,64,404.00	38,46,607.00
7	सॉफ्टवेयर	40%	8.00	--	--	--	8.00	3.00	5.00
8	भूमि (रोहिणी परिसर)	0%	5,54,17,002.00	--	--	--	5,54,17,002.00	--	5,54,17,002.00
9	निर्माणाधीन भवन (दक्षिणी परिसर)	0%	39,52,07,034.30	--	1,77,74,779.00	–	41,29,81,813.30	–	41,29,81,813.30
10	निर्माणाधीन भवन (रोहिणी परिसर)	0%	56,18,30,032.84	48,93,708.00	--	--	56,67,23,704.84	--	56,67,23,740.84
	कुल		**1,03,96,32,858.14**	**56,09,980.00**	**1,94,98,200.00**	**1,295.00**	**1,06,47,39,743.14**	**61,94,769.00**	**1,05,85,44,974.14**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2023 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपये में)

अनुसूची 2: आरक्षितियां और अधिशेष

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
आरक्षितियां और अधिशेष		
अथशेष	1,14,24,22,710.41	1,11,45,74,925.08
जोड़े: वर्ष के दौरान आंतरिक आय पर व्यय के आधिक्य का अंतरण	(1,11,46,703.76)	2,78,47,785.33
पूंजी शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदान		
– साउथ कैंपस	3,85,00,000.00	--
कुल	**1,16,97,76,006.65**	**1,14,24,22,710.41**

अनुसूची 3: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
स्टॉफ अंशदान भविष्य निधि		
अथशेष	72,72,641.00	73,27,849.00
जोड़े:– नियोक्ता अंशदान	–	–
– कर्मचारी अंशदान		– –
भविष्य निधि पर ब्याज	–	–
	72,72,641.00	**73,27,849.00**
घटा: कर्मचारी को अदायगी	--	55,208.00
	72,72,641.00	**72,72,641.00**
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज (बीजी)		
सरकार को देय	5,11,844.00	3,88.281.00
सरकार को देय अन्य आय*	66,37,277.15	18,47,682.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
बयाना जमा राशि	2,71,298.00	2,96.298.00
देय व्यय	3,71,16,305.00	1,12,38,600.00
प्राप्त सुरक्षा राशि	71,809.00	71,809.00
अर्जित ब्याज (सीपीएफ फंड)	5,96,850.00	1,81,528.00
सीजीएचएस	37,700.00	37,700.00
एनपीएस में कर्मचारी का अंशदान	12,47,456.00	9,91,290.00
एनपीएस में नियोक्ता का देय अंशदान	16,30,697.00	12,65,481.00
यूको बैंक खाता संख्या 182001100067819	--	3,63,78,127.14
देय व्यय (पूंजी शीर्ष)	1,94,36,717.00	27,18,727.00
कुल	**7,48,30,594.15**	**6,26,88,164.14**

*इस राशि में सावधि जमा में निवेश किए गए पूंजी अनुदानों पर अर्जित ब्याज शामिल हैं।

अनुसूची 5: निवेश

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सावधि जमा (ऑटो-स्वीप एफएफडी)	6,11,52,717.99	1,45,63,000.00
सावधि जमा (पूंजी शीर्ष खाता)	7,52,50,775.00	11,44,23,371.00
प्राप्त ब्याज (ऑटो-स्वीप एफएफडी-एसबीआई)	11,09,929.00	49,043.00
सावधि जमा (निधि)	80,96,850.00	76,81,528.00
सावधि जमा (दक्षिणी परिसर-बीजी)	19,50,027.00	18,26,464.00
कुल	**14,75,60,298.99**	**13,85,43,406.00**

अनुसूची 6: चालू आस्तियां, त्रृण और अग्रिम

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	रुपये	रुपये
क. चालू आस्तियां		
बैंक बकाया:		
यूको बैंक खाता संख्या 18200200000924	--	1,45,00,000.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 40256508810	(5,49,437.00)	86,09,854.76

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	रुपये	रुपये
यूको बैंक खाता संख्या 18200110067819	3,85,25,756.02	--
बैंक बकाया	**3,79,76,319.02**	**2,31,09,854.76**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
सुरक्षा जमा	50,999.00	50,999.00
स्रोत पर वसूली योग्य काटा गया टैक्स	3,40,047.65	2,59,257.65
आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	59,100.00	10,440.00
परिवहन अग्रिम	29,781.00	29,781.00
पीएलए (विविध प्राप्ति खाते)	45,081.00	45,081.00
पूर्वदत्त व्यय	--	34,29,197.00
कुल	**3,85,01,327.67**	**2,69,34,610.41**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत निकाय)
31 मार्च, 2023 की तिथि के अनुसार आय-व्यय खाता संबंधी अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 7: गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान(डीएम-डिवीजन)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
केन्द्र के अधीन गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	32,00,00,000.00	30,00,00,000.00
कुल	**32,00,00,000.00**	**30,00,00,000.00**

अनुसूची 8: संस्थापना व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वेतन और भत्ते	7,42,81,486.00	7,53,19,176.00
पेंशन अंशदान	49,25,229.00	66,35,167.00
यात्रा रियायत भत्ता/एलटीए	7,91,768.00	7,43,204.00
मेडिकल	5,00,352.00	5,58,336.00
कुल	**8,04,98,835.00**	**8,32,55,883.00**

अनुसूची 9: अन्य प्रशासनिक व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
मरम्मत और रखरखाव	1,33,88,921.00	1,08,66,659.00
डाक	2,27,615.00	1,41,952.00
मुद्रण और स्टेशनरी	10,68,078.00	6,40,005.00
विद्युत एवं जल प्रभार	51,98,733.00	35,40,838.00
विविध व्यय	9,72,598.00	29,62,308.00
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	1,63,983.00	49,625.00
हॉस्टल संचालन एवं रखरखाव	40,48,641.00	
टेलीफोन व्यय	66,11,920.00	88,04,481.00
घरेलू यात्रा	28,61,493.00	26,05,745.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
व्यवसायिक प्रभार	65,81,756.00	60,88,221.00
किराया, दर और कर	11,28,74,208.00	10,47,81,914.00
बैंक प्रभार	3,105.76	8,703.67
प्रकाशन	17,18,678.00	14,59,228.00
अनुसंधान और प्रलेखन	14,55,000.00	37,53,574.00
कार्यालय संचालन एवं रखरखाव	1,33,765.00	2,36,930.00
कुल	**15,73,08,494.76**	**14,59,40,183.67**

अनुसूची 10: प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला व्यय	6,14,53,721.00	3,66,36,682.00
एनपीडीआरआर व्यय	2,56,90,884.00	--
कुल	**8,71,44,605.00**	**3,66,36,682.00**

कृते एच के कोटवालिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 015187N

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-

राजेश खुराना
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 095946
यूडीआईएन: 23095946BGYADW5807

हस्ताक्षर/-

राजेन्द्र रत्नू
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर/-

सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16.10.2023

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान)
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2023 तक पीएलए बैलेंस शीट

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2023	31.03.2022
संचित निधि और देयताएं			
पूंजी और आरक्षितीतथा अधिशेष	1	7,31,560	7,31,560
निर्धारित राशि	2	51,09,802	39,34,350
चालू देयताएं और प्रावधान	3	10,32,456	19,97,192
कुल		**68,73,817**	**66,63,102**
आस्तियां			
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	4	68,73,817	66,63,102
कुल		**68,73,817**	**66,63,102**

सम तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एच के कोटवालिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 015187N

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-
राजेश खुराना
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 095946
यूडीआईएन: 23095946BGYADW5807

हस्ताक्षर/-
राजेन्द्र रत्नू
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16.10.2023

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान)
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2023	31.03.2022
आय		
ब्याज आय	1,41,878.00	1,88,144.00
विविध प्राप्ति	1,03,228.00	--
सावधि जमा पर ब्याज	--	--
ऑनलाईन पाठ्यक्रम प्राप्ति	6,01,205.00	9,85,004.36
परियोजनाओं से संस्थागत अतिरिक्त आय	82,984.00	1,59,876.00
कुल (क)	**9,29,295.00**	**13,33,024.36**
व्यय		
बैंक प्रभार	88.50	1,213.69
कार्यालय खर्चे	11,682.00	--
प्रशिक्षण कार्यक्रम	--	1,46,000.00
कुल (ख)	**11,770.50**	**1,47,213.69**
अधिशेष होने के कारण बकाया (क-ख)	**9,17,524.50**	**11,85,810.67**
घटाएं: पीएओ, गृह मंत्रालय को अंतरित बचत	9,17,524.50	11,85,810.67
अधिशेष/कम होने के कारण बैलेंश शीट में ले जाया गया बकाया	--	--

सम तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एच के कोटवालिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 015187N

हस्ताक्षर/-

राजेश खुराना
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 095946
यूडीआईएन: 23095946BGADW5807

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16.10.2023

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-

राजेन्द्र रत्नू
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर/-

सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान)
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
प्राप्तियां				
अथशेष				
यूको बैंक (बचत खाता)			78,76,635.92	
एसबीआई बैंक खाता संख्या 5043	66,60,159.59	66,60,159.59	--	78,76,635.92
वर्ष के दौरान प्राप्तियां				
1 ऑनलाइन पाठ्यक्रम से प्राप्ति	6,01,205.00		9,85,004.36	
2 सीपीसीबी परियोजना से प्राप्त राशि	1,00,000.00		2,00,000.00	
3 बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना से प्राप्त राशि	79,95,400.00		59,33,000.00	
4 विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्ति	--		⁄61,580.00	
5 एनएडीएमपी परियोजना से प्राप्ति	--		--	
6 विज्ञान और प्रौद्यौगिकी मंत्रालय से प्राप्तियां (सीएपी-आरईएस परियोजना)	34,53,088.00		15,00,000.00	
7 एनसीपीसी-डीएमपीपरियोजना (पेट्रो-रसायन विभाग) से प्राप्त राशि	--		591,000.00	
8 एमएचएफडब्ल्यू परियोजना से प्राप्त राशि	--		5,00,000.00	
9 आयुष मंत्रालय से प्राप्त राशि	--		15,58,200.00	
10 प्रधानमंत्री राहत कोष से प्राप्त राशि	--		--	
11 एनआईडीएम (मुख्य खाता) से प्राप्त राशि	30,00,000.00		58,00,000.00	
12 एनईएफसी-डीएमपी परियोजना के लिए एमओईएफएंडसी से प्राप्त राशि	--	1,47,49,693.00	--	1,71,28,784.36
अन्य प्राप्तियां				
1 अन्य विविध प्राप्तियां	29, 894.00	--		
2 प्राप्त ब्याज (ऑटो-स्वीप)	--	--		
3 प्राप्त ब्याज (अन्य)	143,192.00	1,73,086.00	1,85,202.00	1,85,202.00
कुल		**2,15,82,938.59**		**2,51,90,622.28**
भुगतान				
परियोजना व्यय				
1 बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना	66,13,901.00		55,59,975.00	
2 आयुष परियोजना	7,00,748.00		--	

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
3 विश्व स्वास्थ्य संगठन परियोजना व्यय	--		12,73,750.00	
4 एनएडीएमपी परियोजना	--		2,215.00	
5 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय परियोजना	5,00,000.00		--	
6 सीएपी-आरईएस परियोजना व्यय	14,70,970.00		21,98,322.00	
7 सीपीसीबी परियोजना व्यय	1,15,900.00		90,000.00	
8 एमओईएफएंडसी-एनईएफसी-डीएमपी परियोजना	3,35,849.00		19,33,901.00	
9 एनसीपीसी-डीएमपी परियोजना (पेट्रो-रसायन मंत्रालय)	5,900.00		7,89,535.00	
10 ऑनलाईन पाठ्यक्रम व्यय	15,282.00	97,58,550.00	--	1,18,47,698.00
अन्य व्यय/भुगतान				
1 सरकार को देयता	12,24,108.00		4,54,057.00	
2 एनआईडीएम (मुख्य खाता)	30,00,000.00		57,70,000.00	
3 परियोजना कर्मचारी (यूनिसेफ)	10,401.00		4,36,803.00	
4 कैप-रस परियोजना अग्रिम	--		20,691.00	
5 बैंक प्रभार	88.50		1,213.69	
6 देय खर्चे	7,17,602.00	49,52,199.50	--	66,82,764.69
अंतिम शेष				
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (सीएपी-आरईएस परियोजना)	32,7,061.00	--		
एसबीआई बैंक खाता संख्या 5043	36,65,128.09	68,72,189.09	66,60,159.59	66,60,159.59
कुल		**2,15,82,938.59**		**2,51,90,622.28**

सम तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

कृते एच के कोटवालिया एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 015187N

हस्ताक्षर/-
राजेश खुराना
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 095946
यूडीआईएन: 23095946BGYADW5807

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-
राजेन्द्र रत्नू
कार्यकारी निदेशक

हस्ताक्षर/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16.10.2023

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान)
(गृह मंत्रालय)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (पीएलए)

(राशि रुपये में)

अनुसूची 1: संचित/पूंजीनिधि

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अथशेष	731,560.00	731,560.00
कुल	**731,560.00**	**731,560.00**

अनुसूची 2: निर्धारित निधि

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से प्राप्त राशि		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्ति	6,01,205.00	9,85,004.36
	6,01,205.00	9,85,004.36
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	11,682.00	1,46,000.00
घटा: सरकारी कोष में देय बचत	5,89,523.00	8,89,004.36
	--	--
2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त राशि (सीएपी-आरईएस परियोजना)		
अथशेष	10,88,412.97	18,51,225.97
वर्ष के दौरान प्राप्ति	34,53,088.00	15,00,000.00
	45,41,500.97	**33,51,225.97**
	--	--
घटा: सरकारी कोष में देय बचत		
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	14,70,970.00	22,62,813.00
	30,70,530.97	**10,88,412.97**
3 यूनिसेफ से प्राप्त राशि (सीसीडीआरआर परियोजना)		
अथशेष	2,42,697.00	3,22,346.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	75,95,400.00	59,33,000.00
	78,38,097.00	**62,55,346.00**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
घटा: यूनिसेफ को लौटाई गई अव्ययित राशि	9,23,814.00	8,32,479.00
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	57,67,021.00	51,80,170.00
	11,47,262.00	**2,42,697.00**
4 एमओसीएंडएफ से प्राप्त राशि (सीपीसीबी-सीएमपी परियोजना)		
अथशेष	1,29,754.00	19,754.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	1,00,000.00	2,00,000.00
	2,29,754.00	**2,19,754.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	1,15,900.00	90,000.00
	1,13,854.00	**1,29,754.00**
5 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्राप्त राशि (एनएडीएमपी परियोजना)		
अथशेष	--	18,105.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	--	--
	--	**18,105.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	--	18,105.00
	--	--
6 एमओसीएंडएफ से प्राप्त राशि (एनसीपीसी-डीएमपी परियोजना)		
अथशेष	46,505.00	5,00,000.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	--	6,82,000.00
	46,505.00	11,82,000.00
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	5,900.00	11,35,495.00
	40,605.00	46,505.00
7 एमओईएफएंडसीसी से प्राप्त राशि (एनईएफसी-डीएमपी परियोजना)		
अथशेष	3,68,781.00	26,30,400.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	--	--
	3,68,781.00	**26,30,400.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	3,61,038.00	22,61,619.00
	7,743.00	**3,68,781.00**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
8 एमओएचएंडएफडब्ल्यू से प्राप्त राशि (सीडीएच परियोजना)		
अथशेष	5,00,000.00	--
वर्ष के दौरान प्राप्ति	--	5,00,000.00
	5,00,000.00	**5,00,000.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	5,00,000.00	--
	--	5,00,000.00
9 आयुष मंत्रालय से प्राप्त राशि (एनडीएमपी-आयुष)		
अथशेष	15,58,200.00	--
वर्ष के दौरान प्राप्ति	--	15,58,200.00
	15,58,200.00	**15,58,200.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	8,28,393.00	--
	7,29,807.00	**15,58,200.00**
कुल	**51,09,801.97**	**39,34,349.97**

अनुसूची 3: चालू देयताएं और प्रावधान

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
सरकारी खाते में देय परियोजना बचत	9,17,524.50	1 2,24,107.62
परियोजना कर्मचारी (यूनिसेफ)	--	10,401.00
देय व्यय	69,850.00	7,17,602.00
एनआईडीएम (मुख्य खाता)	45,081.00	45,081.00
कुल	**10,32,455.00**	**19,97,191.62**

अनुसूची: 4 चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
(क) **चालू आस्तियां**		
बैंक शेष:		
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (पीएफएमएस)	32,07,061.00	--
एसबीआई बैंक खाता संख्या 5043	36,65,128.09	66,60,159.59
अर्जित ब्याज	1,628.00	2,942.00
कुल	**68,73,817.09**	**66,63,101.59**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

अध्याय 8

अनुलग्नक

अनुलग्नक

अनुलग्नक की सूची	
8.1	अनुलग्नक-I संस्थान के सदस्य
8.2	अनुलग्नक-II संस्थान के शासी निकाय के सदस्य
8.3	अनुलग्नक-III आमने-सामने कार्यक्रम
8.4	अनुलग्नक-IV ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
8.5	अनुलग्नक-V वेबिनार

अनुलग्नक-I: संस्थान के सदस्यों की सूची

क्र.सं	सदस्य	
1	केंद्रीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3	सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
4	केंद्रीय गृह सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
5	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
6	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7	सचिव, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
8	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
9	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	सदस्य
10	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
11	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य
12	सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, महासागर भवन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य
13	सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
14	अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य

क्र.सं	सदस्य	
15	सचिव/अपर सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
16	महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-66	सदस्य
17	एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख, सिद्धांत संगठन एवं प्रशिक्षण (डीओटी), आईडीएस, मुख्यालय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, 23 साउथ हटमेंट्स, कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
18	सचिव (आपदा प्रबंधन), गुजरात सरकार, राजस्व विभाग, ब्लॉक-11, तीसरी मंजिल, नया सचिवालय, गांधीनगर-382010.	सदस्य
19	सचिव (आपदा प्रबंधन), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना-800015	सदस्य
20	कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006	सदस्य
21	निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी-248 179	सदस्य
22	निदेशक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, शिवरामपल्ली, हैदराबाद-500052	सदस्य
23	महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
24	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, जोका, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता-700104	सदस्य
25	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, उत्तराखंड	सदस्य
26	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
27	निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
28	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
29	महानिदेशक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी, राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030	सदस्य
30	महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वी. रामलिंगस्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029	सदस्य
31	अध्यक्ष, उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग, 159 श्रद्धा कुंज, वसंत विहार, चकराता रोड, देहरादून	सदस्य
32	राष्ट्रीय भूकंपीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
33	सीएमडी, सामान्य बीमा निगम, सुरक्षा, जे टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020	सदस्य
34	सीएमडी, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 2, एन.एस. रोड, कोलकाता-700 001	सदस्य
35	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली	सदस्य
36	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), कोर 4-ए, चौथी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003	सदस्य
37	निदेशक, अखिल भारतीय आपदा न्यूनीकरण संस्थान, 411, साकार पांच, नटराज सिनेमा के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9	सदस्य
38	महासचिव, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, 1 रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली	सदस्य

क्र.सं	सदस्य	
39	निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, उप्पल रोड, हैदराबाद-500 007	सदस्य
40	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
41	प्रोफेसर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, प्लॉट नंबर 15, प,केट 3, ब्लॉक बी, सेक्टर 29, रोहिणी, नई दिल्ली-110042	सदस्य
42	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, प्लॉट नंबर 15, पॉकेट 3, ब्लॉक बी, सेक्टर 29, रोहिणी, नई दिल्ली-110042	सदस्य सचिव

अनुलग्नक-II: संस्थान के शासी निकाय के सदस्य

क्र.सं	सदस्य	
1	उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3	अपर सचिव एवं प्रभारी आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
4	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
5	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	सदस्य
6	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7	सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
8	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
9	प्रधान सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, असम सरकार, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम	सदस्य
10	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, 315, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
11	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, डायमंड हार्बर रोड, पीओ जोका, कोलकाता-700104	सदस्य
12	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, उत्तराखंड-267667	सदस्य
13	निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, उप्पल रोड, हैदराबाद-500007	सदस्य
14	कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर-16सी, द्वारका, दिल्ली-110078	सदस्य
15	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, प्लॉट नंबर 15, पॉकेट 3, ब्लॉक बी, सेक्टर 29, रोहिणी, नई दिल्ली-110042	सदस्य सचिव

अनुलग्नक–III: एनआईडीएम द्वारा 01.04.2022 से 31.3.2023 तक आयोजित आमने–सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
1.	पीएम एजेंडा नंबर 4 और 9: एसएफडीआरआर, एसडीजी, सीसीए के एकीकरण और मुख्यधारा में लाने के लिए क्षमता वृद्धि पर टीओटी/पीडीपी	डीएमआई, भोपाल	04–08 अप्रैल, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	39
2.	पीएम एजेंडा 10 आइटम 1 और 8, नीति नियोजन, बहु–खतरे, भूकंप, बाढ़, सूखा, गर्मी और ठंड, महामारी, आदि। जलवायु परिवर्तन और जिला स्तरीय योजनाओं में आपदा जोखिम में कमी	डीडीयू–एसआईआरडी, लखनऊ (यूपी)	04–08 अप्रैल, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	118
3.	प्रधानमंत्री एजेंडा संख्या 1,2,8 और 9: दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए आपदा पश्चात आवश्यकताओं के आगलन पर टीओटी/पीडीपी	ओएसडीएमए, ओडिशा	04–08 अप्रैल, 2022	प्रो संतोष कुमार	37
4.	शहरी समुत्थानशीलता–नागरिक सुरक्षा की भूमिका के लिए शमन उपायों को समझने पर पीएम एजेंडा नंबर 1 और 8 टीओटी	डीडीएमए, दिल्ली	05–09 अप्रैल, 2022	डॉ. गरिमा अग्रवाल	100
5.	पीएम एजेंडा 10 आइटम 1 और 8: उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में नदी आपदा प्रतिरोधी विकास और योजना (भूकंप, भूस्खलन, अचानक बाढ़, कटाव और जलवायु जोखिमों के लिए)	कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोल, जी गंगटोक, सिक्किम	18–22 अप्रैल, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	54
6.	डीआरआर पर पीएम एजेंडा नंबर 8: आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण, बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर टीओटी कार्यक्रम	राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद संस्थान	18–22 अप्रैल, 2022	डॉ. बालू आई एवं श्री रंजन कुमार	85
7.	डीआरआर पर पीएम एजेंडा नंबर 8: आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने में स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण, बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर टीओटी कार्यक्रम	एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़	18–22 अप्रैल, 2022	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	105
8.	पीएम एजेंडा नंबर 1, 4 और 9: सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिक्षेत्रों का संरक्षण और बचाव	बीएसडीएमए, बिहार	18–22 अप्रैल, 2022	प्रो संतोष कुमार	84

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
9.	पीएम एजेंडा नंबर 1,2,8 और 9: दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए आपदा पश्चात आवश्यकताओँ के आकलन पर टीओटी/पीडीपी	एनआईडीएम, नई दिल्ली	25-29 अप्रैल, 2022	प्रो संतोष कुमार	69
10.	डीआरआर पर पीएम एजेंडा नंबर 8: आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण, बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर टीओटी कार्यक्रम	सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	25-29 अप्रैल, 2022	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	45
11.	पीएम एजेंडा नंबर 10: आकस्मिक प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): बुनियादी एवं मध्यवर्ती	एचसीएम-आरआईपीए, राजस्थान	25-29 अप्रैल, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	61
कुल					**797**
मई 2022					
12.	दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए आपदा पश्चात आवश्यकताओं के आकलन पर टीओटी/पीडीपी	एमजीएसआईपीए, पंजाब	09-13 मई, 2022	प्रो संतोष कुमार	100
13.	प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा नंबर-1,8 और 9: रासायनिक और औद्योगिक डीआरआर पर विशेष जोर के साथ बहु-खतरा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता पर टीओटी	जीवीएमसी, विशाखापत्तनम	09-13 मई, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	143
14.	स्कूल सुरक्षा पर टीओटी	विज्ञान प्रसार, नोएडा	09-13 मई, 2022	डॉ. अजिंदर वालिया	41
15.	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तमिलनाडु	17-20 मई, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	45
16.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मस्तिष्क को प्रेरित करने पर भारत के दक्षिण क्षेत्र के शिक्षाविदों के लिए क्षेत्रीय क्षमता निर्माण टीओटी कार्यक्रम	दक्षिण क्षेत्र, एनआईआरडी, हैदराबाद	17-21 मई, 2022	ड,. प्रीति सोनी	40
17.	आपदा प्रतिरोधी कृषि के लिए जलवायु सूचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईसीएआर-आईआई एसएस, भोपाल मध्य प्रदेश	18-20 मई, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	51
18.	पुलिस के लिए आकस्मिक प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)।	यशदा, पुणे	23-27 मई, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	56
19.	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर टीओटी कार्यक्रम	डॉ. मेरी चन्ना रेड्डी मानव संसाधन विकास संस्थान	23-27 मई, 2022	डॉ. बालू आई	33

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
20.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	23–27 मई, 2022	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	88
21.	ग्राम पंचायत (जीपीडीपी) के साथ ग्राम आपदा प्रबंधन योजना के एकीकरण पर टीओटी, पीएम एजेंडा 8 और 9	यूआईआरडी, रुद्रपुर, उत्तराखंड	25–27 मई, 2022	डॉ. सुषमा गुलेरिया	59
22.	'आपदा प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएसएसटीए कैंपस, ग्रेटर नोएडा, यूपी	30–03 जून, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	59
23.	दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण रणनीतियाँ	एमएसडीएमए, मेघालय	30–03 जून, 2022	डॉ. आमिर अली खान	60
			कुल		**775**
			जून 2022		
24.	स्मार्ट सिटी समन्वयकों (डीएम) के लिए शहरी बाढ़ प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	01–03 जून, 2022	डॉ. रजनीश रंजन	31
25.	सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के लिए आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया पर फाउंडेशन कोर्स	एनसीडीसी, भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार	02–04 जून, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	45
26.	व्यापक आपदा प्रबंधन पर टीओटी	भूमि एवं आपदा प्रबंधन संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल	06–10 जून, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	75
27.	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर टीओटी कार्यक्रम	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान-मैसूरु, कर्नाटक	06–10 जून, 2022	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	53
28.	पीएम एजेंडा नंबर 1, 4 और 8: सुरक्षित पहाड़ी क्षेत्र विकास	हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद् (एचआईएमसीओएस टीई), हिमाचल प्रदेश	15–17 जून, 2022	डॉ. आमिर अली खान	50
29.	पीएम एजेंडा नंबर 4 और 1: वन अग्नि जोखिम शमन पर टीओटी कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, हिमाचल प्रदेश	15–17 जून, 2022	डॉ. गरिमा अग्रवाल	42
30.	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर टीओटी कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा विभाग, पांडिचेरी	20–24 जून, 2022	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	71
31.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	एटीआई, नैनीताल, उत्तराखंड	20–24 जून, 2022	डॉ. अजिंदर वालिया	51

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
32.	पीएम एजेंडा नंबर-1,5,8 और 9: जंगल की आग, भूस्खलन, हिमस्खलन, बिजली, भूकंप, बादल फटना, बाढ़, सूखा और चरम मौसम को कवर करते हुए सुरक्षित टिकाऊ पहाड़ी क्षेत्र विकास के लिए आपदा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को संबोधित करने पर टीओटी/पीडीपी/ एफडीपी आयोजन	एफआरआई देहरादून, उत्तराखंड	22-24 जून, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	38
33.	आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी और व्यवसाय निरंतरता पर ध्यान देने के साथ आपदा प्रबंधन की बुनियादी बातों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश	27-29 जून, 2022	डॉ. सुषमा गुलेरिया	60
		कुल			**516**
		जुलाई 2022			
34.	राज्यों को तकनीकी सहायता: बाल केंद्रित संकट का समाधान, क्षमता में वृद्धि एवं प्रतिरोध को प्रोत्साहन	राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी)	04-08 जुलाई, 2022	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	82
35.	शहरी बाढ़ और शमन पर टीओटी/पीडीपी	नेताजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिम बंगाल सरकार	11-15 जुलाई, 2022	प्रो संतोष कुमार	25
36.	स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (यूआईआरडीपीआर)	11-15 जुलाई, 2022	डॉ. बालू आई और श्री रंजन कुमार	46
37.	पीएम एजेंडा नंबर 1,7,8 और 9: आपदा प्रतिरोधी स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर एफडीपी	एसपीए, दिल्ली	11-15 जुलाई, 2022	डॉ. आमिर अली खान	34
38.	ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएम एजेंडा 8 और 9	एचआईआरडी, निकोलखेड़ी, करनाल	18-20 जुलाई, 2022	डॉ. सुषमा गुलेरिया	52
39.	आपदाओं और आपातकाल में बच्चों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	लद्दाख विश्वविद्यालय	18-22 जुलाई, 2022	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	47

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
40.	दूरसंचार क्षेत्र के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान	18-22 जुलाई, 2022	डॉ. आमिर अली खान	22
41.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (एचपीआईपीए)	25-29 जुलाई, 2022	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	53
42.	जैव-इंजीनियरिंग उपायों द्वारा चक्रवात जोखिम शमन और कटाव नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	भूगोल विभाग, विद्यासागर विश्वविद्यालय	25-29 जुलाई, 2022	प्रोफेसर चंदन घोष	120
43.	पीएम एजेंडा नंबर 4 और 1: विकास योजना/रासायनिक आपदा प्रबंधन योजना/ शहरी जोखिम शमन/अपशिष्ट प्रबंधन में डीआरआर और सीसीए को मुख्यधारा में लाना	ओएसडीएमए, यूएनडीपी/गोपबंधु प्रशासन अकादमी, ओडिशा/त्रिपुरा	26-29 जुलाई, 2022	डॉ. गरिमा अग्रवाल	33
44.	सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन पर फाउंडेशन कोर्स	एनसीडीसी, एमओएच एफडब्ल्यू, सीडीसी भारत और उत्तराखंड सरकार	28-30 जुलाई, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	35
		कुल			**549**
		अगस्त 2022			
45.	राज्यों को तकनीकी सहायता: बाल केंद्रित संकट का समाधान, क्षमता में वृद्धि एवं प्रतिरोध को प्रोत्साहन	भूमि एवं आपदा प्रबंधन संस्थान	01-05 अगस्त, 2022	डॉ. बालू आई एवं श्री रंजन कुमार	70
46.	पीएम एजेंडा नंबर 4,5 और 6: आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संकाय विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	जेएमआई, नई दिल्ली	01-05 अगस्त, 2022	डॉ. आमिर अली खान	50
47.	पर्यावरण क्षेत्र एवं आपदा प्रबंधन पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	तारुथांग परिसर, लद्दाख विश्वविद्यालय	02-04 अगस्त, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	115
48.	आपदाओं और आपातकाल में बच्चों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	यशदा, पुणे	08-12 अगस्त, 2022	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	26
49.	आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर टीओटी	मेघालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शिलांग	16-18 अगस्त, 2022	डॉ. अजिंदर वालिया	56
50.	व्यापक आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	नवोदय विद्यालय	22-26 अगस्त, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	37

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
51.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर टीओटी कार्यक्रम	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	22–26 अगस्त, 2022	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	75
52.	पीएम एजेंडा नंबर 1,3 और 6: आपदा प्रबंधन पर संकाय विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़	22–26 अगस्त, 2022	डॉ. आमिर अली खान	62
53.	प्रकृति आधारित समाधानों का उपयोग करके बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	नेहु, शिलांग	23–27 अगस्त, 2022	प्रोफेसर चंदन घोष	112
54.	पीएम एजेंडा नंबर 1: आपदा के दौरान और उसके बाद जल संसाधन प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), नई दिल्ली	29–31 अगस्त, 2022	डॉ. सुषमा गुलेरिया	50
55.	पीएम एजेंडा नंबर 1: भवन जोखिम आकलन और आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: भूकंप और आग पर ध्यान केंद्रित	डीडीएमए, दिल्ली	29 अगस्त–02 सितम्बर, 2022	डॉ. गरिमा अग्रवाल	102
कुल					**755**
सितम्बर 2022					
56.	स्कूल आपदा प्रबंधन योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	जम्मू और कश्मीर प्रबंधन संस्थान, लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	12–15 सितम्बर, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	28
57.	आईआरएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: बेसिक और इंटरमीडिएट	भूमि एवं आपदा प्रबंधन संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल	19–23 सितम्बर, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	76
58.	पीएम एजेंडा नंबर 1 और 8: जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं पर टीओटी कार्यक्रम	एचसीएम–आरआईपीए, राजस्थान	20–23 सितम्बर, 2022	डॉ. गरिमा अग्रवाल	49
59.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर टीओटी कार्यक्रम	कश्मीर विश्वविद्यालय	26–30 सितम्बर, 2022	डॉ. बालू आई एवं श्री रंजन कुमार	75
60.	दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए आपदा पश्चात आवश्यकताओं का मूल्यांकन	सीडीएम, एटीआई, मैसूरु	26–30 सितम्बर, 2022	प्रो संतोष कुमार	61

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
61.	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में डीआरआर के एकीकरण पर टीओटी पीएम एजेंडा 8 और 9	डीडीयूएसआईआरडी, उत्तर प्रदेश	26-30 सितम्बर, 2022	डॉ. सुषमा गुलेरिया	38
62.	शहरों, उद्योगों और व्यापार के लिए बहु जोखिम प्रबंधन समाधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईआईटी इंदौर, मध्य प्रदेश	26-30 सितम्बर, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	88
63.	आपदाओं पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों के लिए आपदा पश्चात तनाव प्रबंधन	बैंगलोर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	27-29 सितम्बर, 2022	डॉ. अजिंदर वालिया	70
64.	पीएम एजेंडा नंबर 4, 7 और 8: स्कूल सुरक्षा योजना और ऑडिटिंग पर टीओटी	एमसीएचआरडीआई, तेलंगाना	27-29 सितम्बर, 2022	डॉ. आमिर अली खान	38
कुल					**523**
अक्टूबर 2022					
65.	कोविड-19 सुरक्षा पर जोर देने के साथ आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राकांपा गाजियाबाद	29-30 सितम्बर और 03- अक्टूबर, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	22
66.	ग्राम आपदा प्रबंधन योजना का ग्राम पंचायत (जीपीडीपी) के साथ एकीकरण	रीपा, राजस्थान	17-19 अक्टूबर, 2022	डॉ. सुषमा गुलेरिया	59
67.	नदी पुनर्जीवन, जलवायु समुत्थानशीलता और डीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: योजनाएं, परिप्रेक्ष्य और नीतियां	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	17-21 अक्टूबर, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	147
68.	श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंधित संगठनों/कार्यालयों द्वारा डीएमपीएस विकसित करने पर संवेदीकरण कार्यक्रम	श्रम और रोजगार मंत्रालय	17-21 अक्टूबर, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	46
69.	पीएम एजेंडा नंबर 6,8 और 9: भूकंप जोखिम शमन और प्रबंधन	कश्मीर विश्वविद्यालय	17-21 अक्टूबर, 2022	डॉ. आमिर अली खान	70
70.	विकास योजना में आपदा समुत्थानशील उपायों को मुख्यधारा में लाने पर पीएम एजेंडा नंबर 1 पर टीओटी कार्यक्रम	आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास निदेशालय मिजोरम सरकार, मिजोरम: आइजोल	19-21 अक्टूबर, 2022	डॉ. गरिमा अग्रवाल	49
71.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	गोवा लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गोवा	26-28 अक्टूबर, 2022	डॉ. अजिंदर वालिया	42
72.	राज्यों को तकनीकी सहायता: बाल केंद्रित संकट का समाधान, क्षमता में वृद्धि एवं प्रतिरोध को प्रोत्साहन	महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान	31 अक्टूबर-04 नवंबर, 2022	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	82

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
73.	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): आईसी और पीएससी	एनआईडीएम, नई दिल्ली	31 अक्टूबर-04 नवंबर, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	20
74.	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) का एकीकरण	एसआईआरडी लखनऊ, यूपी	31 अक्टूबर-04 नवंबर 2022	डॉ. सुषमा गुलेरिया	41
कुल					**578**
नवंबर 2022					
75.	जैव-इंजीनियरिंग उपायों द्वारा तटीय कटाव नियंत्रण पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला	गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, (जीसीई), फार्मागुडी, गोवा	03-05 नवंबर, 2022	प्रोफेसर चंदन घोष	141
76.	दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए आपदा पश्चात आवश्यकताओं का आकलन	जम्मू एवं कश्मीर आईएमपीएरडी, मुख्य परिसर श्रीनगर	07-11 नवंबर, 2022	प्रो संतोष कुमार	29
77.	आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास में उपग्रह पृथ्वी अवलोकन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम (ईओएआईडीआरआई)	एमएनएनआईटी, इलाहाबाद	11-13 नवंबर, 2022	प्रोफेसर चंदन घोष	55
78.	पीएम एजेंडा नंबर 1 और 9: भूकंप जोखिम शमन और जागरूकता पर टीओटी: एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण	विज्ञान प्रसार, दिल्ली	14-18 नवंबर, 2022	डॉ. आमिर अली खान	48
79.	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)	महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़, पंजाब	14-18 नवंबर, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	117
80.	राज्यों को तकनीकी सहायता: बाल केंद्रित संकट का समाधान, क्षमता वृद्धि एवं प्रतिरोध को प्रोत्साहन	एचसीएम-आरआईपीए, राजस्थान	14-18 नवंबर, 2022	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	51
81.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर टीओटी कार्यक्रम	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	14-18 नवंबर, 2022	डॉ. बालू आई एवं श्री रंजन कुमार	86
82.	स्कूल सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	केन्द्रीय विद्यालय	14-18 नवंबर, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	25
83.	शहरी समुत्थानशीलता के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	14-18 नवंबर, 2022	डॉ. गरिमा अग्रवाल	98
84.	आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	15-17 नवंबर, 2022	डॉ. अजिंदर वालिया	23

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
85.	प्रधानमंत्री एजेंडा 8 और 9 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और सीएसआर पहल के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के एकीकरण पर राष्ट्रीय टीओटी	एनआईआरडीपीआर, नई दिल्ली	21-25 नवंबर, 2022	डॉ. सुषमा गुलेरिया	20
86.	लैंगिक एवं आपदा प्रबंधन पर टीओटी	विज्ञान प्रसार, नोएडा	21-25 नवंबर, 2022	डॉ. अजिंदर वालिया	35
87.	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य प्रशिक्षण अकादमी मणिपुर	21-25 नवंबर, 2022	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	62
88.	भारतीय रेलवे के सेवारत अधिकारियों के लिए सामान्य आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान (आईआरआईडीएम)	21-25 नवंबर, 2022	प्रो संतोष कुमार	163
89.	आपदा प्रबंधन और उसके शमन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय	22-24 नवंबर, 2022	प्रोफेसर चंदन घोष	91
90.	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली के विशेष संदर्भ में अस्पताल एवं डॉक्टर	गोवा लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गोवा	29-01 नवंबर, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	36
कुल					**1080**
दिसंबर 2022					
91.	प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं के लिए आपदा पश्चात तनाव प्रबंधन	तमिलनाडु डॉ अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई	06-08 दिसंबर, 2022	डॉ. अजिंदर वालिया	107
92.	प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा नंबर-1,8 और 9: रासायनिक रिसाव और औद्योगिक डीआरआर पर टीओटी/ पीडीपी/एफडीपी	ओएनजीसी-आईपीएस एचईएम,गोवा	12-16 दिसंबर, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	22
93.	प्रधानमंत्री एजेंडा 8 और 9 ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और सीएसआर पहल के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के एकीकरण पर राष्ट्रीय टीओटी	एनआईआरडीपीआर, नई दिल्ली	12-16 दिसंबर, 2022	डॉ. सुषमा गुलेरिया	20
94.	आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	13-15 दिसंबर, 2022	डॉ. अजिंदर वालिया	26
95.	सुंदरबन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए प्रकृति-आधारित शमन उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	जादवपुर विश्वविद्यालय	15-17 दिसंबर, 2022	प्रोफेसर चंदन घोष	55

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
96.	आपदाओं के प्रति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की समुत्थानशीलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	यशदा, पुणे	19–23 दिसंबर, 2022	डॉ. गरिमा अग्रवाल	67
97.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	केंद्रीय विश्वविद्यालय पांडिचेरी	19–23 दिसंबर, 2022	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	104
98.	तटीय समुदाय की समुत्थानशीलता पर टीओटी कार्यक्रम	विज्ञान प्रसार, पुडुचेरी	27–29 दिसंबर, 2022	डॉ. आमिर अली खान	58
99.	बड़ी सभाओं में भीड़ के प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीडीएमए, ऊना	27–29 दिसंबर, 2022	श्री शेखर चतुर्वेदी	52
कुल					**511**
जनवरी 2023					
100.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	02–06 जनवरी, 2023	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	98
101.	सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएलडीएम, केरल	09–13 जनवरी, 2023	डॉ. बालू आई एवं श्री रंजन कुमार	62
102.	पीएम एजेंडा नंबर 2 और 8: ग्रामीण संदर्भ में आपदा जोखिम न्यूनीकरण	डीडीयू ग्रामीण विकास संस्थान, आगरा विश्वविद्यालय	11–13 जनवरी, 2023	डॉ. आमिर अली खान	72
103.	आपदाओं के प्रति महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की समुत्थानशीलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एटीआई, मैसूरु	16–20 जनवरी, 2023	प्रोफेसर चंदन घोष	24
104.	दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति के लिए आपदा पश्चात आवश्यकताओं के आकलन पर टीओटी/पीडीपी	एचसीएम-आरआईपीए, राजस्थान	16–20 जनवरी, 2023	प्रो संतोष कुमार	45
105.	सतत् पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति ढांचे पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएलडीएम, केरल	23–25 जनवरी, 2023	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	62
106.	आपदा प्रबंधन के लिए संकाय विकास कार्यक्रम	एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़, पंजाब	30–03 जनवरी, 2023	डॉ. सुषमा गुलेरिया	101
107.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	30–03 जनवरी, 2023	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	60
कुल					**524**

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
फरवरी 2023					
108.	रासायनिक जैविक रेडियोलॉजिकल परमाणु (सीबीआरएन) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीडीएमए बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश	06-08 फरवरी, 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	54
109.	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): ओएससी और एसओ	एनआईडीएम, नई दिल्ली	06-10 फरवरी, 2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	12
110.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी (डीआरएसटी यूएओए) नैनीताल	06-10 फरवरी, 2023	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	60
111.	संकाय विकास कार्यक्रम (क्षमता निर्माण) श्रृंखला 2-आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मस्तिष्क की प्रेरणा	गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) उत्तर प्रदेश	06-10 फरवरी, 2023	डॉ. प्रीति सोनी	91
112.	आपदाओं पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों के लिए आपदा पश्चात तनाव प्रबंधन	एमसीएचआरडीआई, तेलंगाना	07-06 फरवरी, 2023	डॉ. अजिंदर वालिया	20
113.	पीएम एजेंडा नंबर 4,7 और 8: स्कूल सुरक्षा योजना और ऑडिटिंग	जीआईपीएआरडी, गोवा गिपार्ड गोवा	07-09 फरवरी, 2023	डॉ. आमिर अली खान	38
114.	आपदा पश्चात आवश्यकताओं का आकलन	एपीएचआरडीआई, आंध्र प्रदेश	13-17 फरवरी, 2023	प्रो संतोष कुमार	44
115.	सीसीए-डीआरआर पर क्षेत्रीय स्तर की टीओटी को मुख्यधारा की शहरी योजनाओं से जोड़ना	एमजीएसआईपीए, चंडीगढ़, पंजाब	20-24 फरवरी, 2023	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	184
116.	आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी और व्यवसाय निरंतरता पर ध्यान देने के साथ आपदा प्रबंधन की मूल बातें	राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नोएडा, दिल्ली	22-24 फरवरी, 2023	डॉ. सुषमा गुलेरिया	75
117.	आपातकालीन संचालन केंद्र: स्थापना और संचालन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	22-24 फरवरी, 2023	श्री शेखर चतुर्वेदी	27
118.	संकाय विकास कार्यक्रम	एनईआरआईएसटी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	22-24 फरवरी, 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	52
कुल					**657**

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
मार्च 2023					
119.	ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में डीआरआर के एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए)	13–15 मार्च, 2023	डॉ. सुषमा गुलेरिया	81
120.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	असम विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय)	13–17 मार्च, 2023	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	66
121.	आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर टीओटी कार्यक्रम	एमजीएसआईपीए, पंजाब	13–17, मार्च, 2023	डॉ. अजिंदर वालिया	39
122.	श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंधित संगठनों/कार्यालयों द्वारा डीएमपीएस विकसित करने पर संवेदीकरण कार्यक्रम	श्रम और रोजगार मंत्रालय	13–17, मार्च, 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	42
123.	मौसम पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी और अंतिम मील कनेक्टिविटी में तकनीकी नवाचार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एसडीएमए मेघालय	14–16, मार्च 2023	डॉ. रजनीश रंजन	49
124.	'राज्य और जिला योजनाओं में सीसीए-डीआरआर एकीकरण' पर क्षेत्रीय स्तर की टीओटी	एटीआई, नैनीताल	20–22, मार्च, 2023	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	29
125.	सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	पोर्ट ब्लेयर परिसर, पांडिचेरी विश्वविद्यालय	20–24 मार्च, 2023	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	78
126.	सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (टीएनएसडीएमए)	27–31, मार्च, 2023	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	51
कुल					**435**
कुल योग					**7700**

अनुलग्नक-IV: एनआईडीएम द्वारा 01.04.2022 से 31.03.2023 तक आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
1.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशील आवास की चुनौतियों पर दो दिवसीय आभासी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	05-06 अप्रैल, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	128
2.	आपदा जोखिम जलवायु परिवर्तन और समुत्थानशील विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीटीयू, दिल्ली	05-07 अप्रैल, 2022	डॉ श्वेता बैद्य	116
3.	सूखा एवं बाढ़ विश्लेषण एवं उनके प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमएनएनआईटी, इलाहाबाद, प्रयागराज	14-18 अप्रैल, 2022	डॉ. हरजीत कौर	131
4.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	मद्रास विश्वविद्यालय गिंडी परिसर गिंडी चेन्नई	19-21 अप्रैल, 2022	डॉ. ए एल हलदर	261
5.	आपदा प्रबंधन में पृथ्वी अवलोकन प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	27-29 अप्रैल, 2022	श्री गौतम कृष्ण	163
6.	आपदा के प्रति कृषि-प्रणाली और बुनियादी ढांचे के समुत्थानशील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	कृषि अभियांत्रिकी विभाग, असम विश्वविद्यालय, सिलचर	28-30 अप्रैल, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	160
7.	डीआरएम में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	28-30 अप्रैल, 2022	सुश्री नाजिया शेख	306
8.	स्वास्थ्य मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग प्रणाली के निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम और राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी अकादमी, भारत सरकार	28-30 अप्रैल, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	125
कुल					**1390**
मई 2022					
9.	डीआरआर और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	नागालैंड विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)	04-06 मई, 2022	सुश्री नाजिया शेख	321
10.	औद्योगिक जोखिम और आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान	09-11 मई, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	156
11.	आपदा जोखिम प्रबंधन पर क्षमता संवर्धन को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम	लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	17-19 मई, 2022	डॉ. ए एल हलदर	321
12.	सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	मणिपुर विश्वविद्यालय	18-20 मई, 2022	सुश्री नाजिया शेख	411
13.	भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से तटीय आपदाओं को समझने पर प्रशिक्षण	राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, पृथ्वी विज्ञान	18-20 मई, 2022	श्री गौतम कृष्ण	147

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
	कार्यक्रम	मंत्रालय (एमओईएस) भारत सरकार, हैदराबाद:			
14.	हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन और अग्निशमन में युवा पुलिस और समुदायों की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय	18-20 मई, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	129
15.	प्रशिक्षण कार्यक्रम: भारतीय शहरों को उत्तरदायी और कार्रवाई योग्य शहरी योजना, नीति और विकास की दिशा में आपदा प्रतिरोधी बनाना	आईएमपीआरआई, नई दिल्ली	23-25 मई, 2022	डॉ श्वेता बैद्य	601
16.	तटीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	30 मई-01 जून, 2022	डॉ. हरजीत कौर	118
कुल					**2204**
जून 2022					
17.	जोखिम और सुरक्षा प्रबंधन में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एफआईसीसीआई नई दिल्ली	01 मई-03 जून, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	332
18.	सतत् विकास लक्ष्यों के लिए आपदा समुत्थानशीलता और हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान में प्रगति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, यूपी	06-10 जून, 2021	डॉ. श्वेता बैद्य	100
19.	प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, बिहार	08-10 जून, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	207
20.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	08-10 जून, 2022	सुश्री नाजिया शेख	325
21.	औद्योगिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एफआईसीसीआई, नई दिल्ली	14-16 जून, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	321
22.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात	14-16 जून, 2022	डॉ. ए एल हलदर	279
23.	संस्थानों के आपदा प्रतिरोधी निर्मित बुनियादी ढांचे पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: भूकंप और आग पर विशेष ध्यान	पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन केंद्र (सीईएसडीएम) मिरांडा हाउस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	14-16 जून, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	324

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
24.	आपदा जोखिम प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	20-22 जून, 2022	श्री गौतम कृष्ण	162
25.	आपदा प्रतिरोधी निर्माण की दिशा में महिलाओं की आजीविका, खाद्य और पोषण की सुरक्षा के लिए अंतर्विभागीय दृष्टिकोण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: एपीएमसीडीआरआर के लिए एजेंडा	एआईडीएमआई, गुजरात	28-30 जून, 2022	डॉ. हरजीत कौर	144
कुल					**2194**
जुलाई 2022					
26.	पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और आपदा प्रबंधन के क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	05-07 जुलाई, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	198
27.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	14-16 जुलाई, 2022	सुश्री नम्रता शर्मा	218
28.	प्राकृतिक खतरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ, यूपी	16-20 जुलाई, 2022	डॉ. हरजीत कौर	140
29.	आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु जनभागीदारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड, रांची	18-20 जुलाई, 2022	डॉ. ए एल हलदर	271
30.	एक सतत-समुत्थानशील आपदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च, दिल्ली	19-21 जुलाई, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	431
31.	आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम	20-22 जुलाई, 2022	सुश्री नाजिया शेख	300
32.	बाढ़ और चक्रवातों के विशेष संदर्भ में इमारतों की मजबूती के उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान, पश्चिम बंगाल, (भूगोल विभाग)	20-22 जुलाई, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	166
33.	अंतरिक्ष से भू-खतरों का अवलोकन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	25-27 जुलाई, 2022	श्री गौतम कृष्ण	199
34.	आवर्ती गर्म लहरें: जोखिम, प्रभाव और समुत्थानशीलता के लिए आगे का रास्ता	आईएमपीआरआई, नई दिल्ली	26-28 जुलाई, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	295
कुल					**2218**

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
अगस्त 2022					
35.	प्रशिक्षण कार्यक्रम: 'वर्षा जल संरक्षण को लागू करना' वर्षा जल संचयन और कुशल स्थानीय जल प्रशासन और समुत्थानशीलता पर चिकित्सकों का दृष्टिकोण	आईएमपीआरआई, नई दिल्ली	02-04 अगस्त, 2022	डॉ श्वेता बैद्य	260
36.	डीआरएम और सीसीए में युवाओं और किशोरों को शामिल करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	03-05 अगस्त, 2022	सुश्री नम्रता शर्मा	165
37.	प्रतिक्रिया और समुत्थानशीलता के लिए बहु-हितधारक-बहुक्षेत्रीय समन्वय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: असम	स्फीयर इंडिया, नई दिल्ली	22-24 अगस्त, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	147
38.	आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन पर संकायों के लिए टीओटी कार्यक्रम	विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु	22-24 अगस्त, 2022	डॉ. प्रीति सोनी	250
39.	आपदा प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	23-25 अगस्त, 2022	श्री गौतम कृष्ण	427
40.	बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	हिन्दुस्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, चेन्नई तमिलनाडु	23-25 अगस्त, 2022	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	213
41.	भारत में ग्रामीण और जनजातीय समुदायों में बुनियादी ढांचे की मजबूती के संचार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन	23-25 अगस्त, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	223
42.	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	असम केंद्रीय विश्वविद्यालय	24-26 अगस्त, 2022	सुश्री नाजिया शेख	201
43.	आपदा जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला	29-31 अगस्त, 2022	डॉ. ए एल हलदर	345
कुल					**2231**
सितम्बर 2022					
44.	आपद प्रबंधन की अवधारणा और शहरी समुत्थानशीलता पर जीआईजेड के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	13-15 सितम्बर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	26

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
45.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता के निर्माण के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में महिलाएं	बीएल अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स	14-16 सितम्बर, 2022	श्री अली हैदर	382
46.	तमिलनाडु राज्य के लिए प्रतिक्रिया और मजबूत निर्माण के लिए बहुक्षेत्रीय समन्वय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्फीयर इंडिया, नई दिल्ली	14-16 सितम्बर, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	539
47.	आपदा प्रबंधन की बुनियादी बातों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रिलायंस रिटेल लिमिटेड मुंबई	19-21 सितम्बर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	1547
48.	प्रतिक्रिया और मजबूत निर्माण के लिए बहुक्षेत्रीय समन्वय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्फीयर इंडिया, नई दिल्ली	20-22 सितम्बर, 2022	डॉ श्वेता बैद्य	145
49.	प्रशिक्षण-आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण	केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू और कश्मीर, जम्मू	21-23 सितम्बर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	335
50.	शहरों में आर्द्रभूमि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम-आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए स्थानीय योजना	एसपीए, भोपाल	27-29 सितम्बर, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	149
कुल					**3123**
अक्टूबर 2022					
51.	निर्मित पर्यावरण के लिए आपदा पूर्व और पश्चात प्रबंधन रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमिटी यूनिवर्सिटी, जयपुर	06-10 अक्टूबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	228
52.	सीसीडीआरआर पर 03 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	नागालैंड विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)	12-14 अक्टूबर, 2022	सुश्री नाजिया शेख	279
53.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशील रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एक अंतर-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण	इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल काजी नजरूल यूनिवर्सिटी आसनसोल पश्चिम बंगाल	17-19 अक्टूबर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	237
54.	उत्तराखंड के लिए प्रतिक्रिया एवं मजबूत निर्माण के लिए बहुक्षेत्रीय समन्वय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	स्फीयर इंडिया, नई दिल्ली	17-19 अक्टूबर, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	109
55.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर ऑलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	26-28 अक्टूबर, 2022	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	74
56.	व्यावसायिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन	एसआरएम इंस्टीट्यूट	27-29 अक्टूबर, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	624

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
	पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई			
57.	शैक्षणिक संस्थागत भवनों की मजबूती को बढ़ाने के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं की भूमिका पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	संगम विश्वविद्यालय	27-29 अक्टूबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	212
कुल					**1763**
नवंबर 2022					
58.	वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: आपदा प्रबंधन	एमिटी यूनिवर्सिटी	02-04 नवंबर, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	216
59.	स्वास्थ्य सुविधाओं के समुत्थानशील निर्माण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	जियो हैजर्ड सोसायटी	09-11 नवंबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	491
60.	गणेश मैदानों में संवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर बिहार	16-18 नवंबर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	223
61.	व्यवसाय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और आपदा समुत्थानशीलता पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	केईएस श्रॉफ कॉलेज मुंबई	21-23 नवंबर, 2022	डॉ श्वेता बैद्य	376
62.	सांस्कृतिक धरोहर आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	लोक जागृति केंद्र विश्वविद्यालय (एलजेकेयू)	23-25 नवंबर, 2022	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	383
63.	बार-बार आने वाली आपदाओं के कारण भारत के सुंदरबन में बुनियादी ढांचे, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	रेजिलिएंस इनोवेशन नॉलेज एकेडमी (आरआईकेए) इंडिया प्रा. लिमिटेड	28-30 नवंबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	84
64.	आपदा जोखिम प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग	एनआईडीएम, नई दिल्ली	28-30 नवंबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	104
कुल					**1877**
दिसंबर 2022					
65.	बेहतर नीति, योजना और टिकाऊ शहरों के लिए आपदा प्रतिरोधी आवास और निर्मित पर्यावरण अनिवार्यताओं पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएमपीआरआई, नई दिल्ली	13-15 दिसंबर, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	312

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
66.	औद्योगिक सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का प्रयोग	एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु	20–22 दिसंबर, 2022	डॉ श्वेता बैद्य	621
67.	समुदाय आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवंतिका विश्वविद्यालय, लेकोडा गांव	20–22 दिसंबर, 2022	श्री अली हैदर, जूनियर सलाहकार	382
68.	बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, नलगोंडा, तेलंगाना	21–23 दिसंबर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	233
69.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता	एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश	27–29 दिसंबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	172
		कुल			**1720**
		जनवरी 2023			
70.	आपदा प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम: एंबेडेड सिस्टम के साथ जलवायु प्रौद्योगिकी, पूर्वानुमान और शमन	इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर, राजस्थान	09–11 जनवरी, 2023	डॉ. श्वेता बैद्य	294
71.	शैक्षणिक, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के डोमेन विशेषज्ञों को आमंत्रित करने वाली 3-दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण-उन्मुख परामर्शदात्री कार्यशाला	बाल अधिकार और आप	23–25 जनवरी, 2023	सुश्री नाजिया शेख	612
72.	डीआरआर नीतियों और रणनीतियों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की (एसटीआई) भूमिका पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़	30–01 जनवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	134
		कुल			**1040**
		फरवरी 2023			
73.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	15–17 फरवरी, 2023	श्री गौतम कृष्ण	255
74.	शहरी जोखिम- धुआं और धूल के खतरे पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	15–17 फरवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	111
75.	तकनीकी दुनिया के बदलते परिदृश्य में युवाओं के शारीरिक और मानसिक कल्याण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान (आईआईटीई), गुजरात	20–22 फरवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	225

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
76.	तटीय क्षेत्रों में जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	गोवा विश्वविद्यालय	22–24 फरवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	205
77.	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	महिलाओं के लिए गृह विज्ञान और उच्च शिक्षा के लिए अविनाशीलिंगम संस्थान, कोयंबटूर	27 फरवरी–01 मार्च, 2023	सुश्री नाजिया शेख	365
कुल					**1161**
मार्च 2023					
78.	शिक्षा जगत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	नागालैंड विश्वविद्यालय (एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)	13–15 मार्च, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	253
79.	तीव्र शहरीकरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय	27–29 मार्च, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	270
80.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	अलगप्पा विश्वविद्यालय	29–31 मार्च, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	273
कुल					**796**
कुल योग					**21717**

अनुलग्नक-V: एनआईडीएम द्वारा 01.04.2022 से 31.03.2023 तक आयोजित वेबिनार

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
1.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित हीट वेव और स्वास्थ्य प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	04 अप्रैल, 2022	डॉ. हरजीत कौर	191
2.	एनआईडीएम द्वारा बेसिक ऑनलाइन कोर्स (व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क) के लिए ओरिएंटेशन का आयोजन किया गया	एनआईडीएम, नई दिल्ली	04 अप्रैल, 2022	डॉ. रजनीश रंजन	96
3.	शून्य भूख की दिशा में व्यापार निरंतरता के लिए डीआरआर	गठबंधन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा	05 अप्रैल, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	72
4.	जंगल की आग का प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	05 अप्रैल, 2022	डॉ. ए एल हलदर	104
5.	नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) और यूएस यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) कंट्री ऑफिस इंडिया, कंट्री ऑफिस भारत के सहयोग से कोविड-19 में बहुस्तरीय, बहु-क्षेत्रीय और बहु-एजेंसी समन्वय	एनसीडीसी और सीडीसी, भारत	06 अप्रैल, 2022	डॉ. हरजीत कौर	224
6.	हमारा ग्रह, हमारा स्वास्थ्य: एबीवीआईएमए और आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली के सहयोग से स्वच्छ जल, वायु और भोजन-स्वास्थ्य आपात स्थिति और आपदाओं की रोकथाम	एबीवीआईएमए और आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	07 अप्रैल, 2022	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	109
7.	जलवायु परिवर्तन 2022: प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता-चुनौतियाँ और समाधान एनआईडीएम द्वारा आयोजित	एनआईडीएम, नई दिल्ली	12 अप्रैल, 2022	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	364
8.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), भारत में अमेरिकी कार्यालय के सहयोग से आपदा और स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए कानून और नीति ढांचा	एनसीडीसी और सीडीसी, भारत	13 अप्रैल, 2022	डॉ. हरजीत कौर	144
9.	प्रधानमंत्री 10 भाग एजेंडा संख्या 1,3 और 9: एसडीजी: 3,4 और 5) विचार	दिल्ली	15 अप्रैल, 2022	श्री रंजन कुमार	175

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
	के सहयोग से आपात स्थिति में बाल संरक्षण				
10.	गर्मी की लहरों के प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचालन केंद्र की भूमिका	एनआईडीएम, नई दिल्ली	20 अप्रैल 2022	श्री गौतम कृष्ण	68
11.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), भारतीय कार्यालय के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन (पीएचईएम) और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र (पीएचईओसी) भारत	एनसीडीसी और सीडीसी, भारत	20 अप्रैल 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	144
12.	प्राकृतिक खतरों और शमन रणनीतियों को समझने के लिए एनआईडीएम द्वारा आयोजित सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग	एनआईडीएम, नई दिल्ली	25 अप्रैल 2022	श्री गौतम कृष्ण	100
13.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ), कारण और परिणाम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26 अप्रैल, 2022	डॉ. ए एल हलदर	120
14.	प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए लोरा टेक्नोलॉजी: एक व्यावहारिक प्रदर्शन पर एनआईडीएम द्वारा आयोजित वेबिनार	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26 अप्रैल, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	73
15.	पीएम 10 सूत्री एजेंडा नं. 1, 5 और 9: एसडीजी: 13, 15 और 17 यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन का आयोजन एनआईडीएम द्वारा किया गया	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26 अप्रैल, 2022	डॉ. बालू आई	748
16.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), भारत में अमेरिकी कार्यालय के सहयोग से डब्ल्यूएचओ के पीएचईओसी ढांचे और वैश्विक सामान्य न्यूनतम मानक का अवलोकन	एनसीडीसी और सीडीसी, भारत	27 अप्रैल, 2022	डॉ. हरजीत कौर	220
17.	''रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन- भाग I''	एनआईडीएम, नई दिल्ली	28 अप्रैल, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	47
18.	कृषि और शमन रणनीतियों पर जलवायु परिवर्तन और आपदा का प्रभाव	एनआईडीएम, नई दिल्ली	29 अप्रैल, 2022	डॉ श्वेता बैद्य	63

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
19.	रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन – भाग II	एनआईडीएम, नई दिल्ली	29 अप्रैल, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	40
20.	औद्योगिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	30 अप्रैल 2022	डॉ श्वेता बैद्य	90
कुल					**3192**
मई 2022					
21.	पीएचईओसी-सूचना प्रौद्योगिकी: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के भारतीय कार्यालय के सहयोग से आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रबंधन, सुरक्षा और बुनियादी ढांचा	एनसीडीसी और सीडीसी, भारत	04 मई, 2022	डॉ. हरजीत कौर	120
22.	केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष-आधारित प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	केएसडीएमए, केरल	10 मई, 2022	श्री गौतम कृष्ण	99
23.	स्फीयर इंडिया के सहयोग से एसडीएमपी और डीडीएमपी पर विचार-मंथन सत्र सह वेबिनार	स्फीयर इंडिया, दिल्ली	10 मई, 2022	डॉ श्वेता बैद्य	12
24.	एकीकृत सूचना प्रबंधन: आईएचआईपी (मीडिया स्कैनिंग, अफवाह रजिस्टर आदि)-(पीएचईओसी में सूचना और डेटा प्रबंधन का एकीकरण): राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र भारत में अमेरिकी कार्यालय के सहयोग से दैनिक स्थितिजन्य जागरूकता रिपोर्ट (सीडीसी)	एनसीडीसी और सीडीसी, भारत	11 मई, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	427
25.	एनआईडीएम द्वारा हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) का आयोजन किया गया	एनआईडीएम, नई दिल्ली	13 मई, 2022	डॉ. ए एल हलदर	173
26.	एनआईडीएम ऑनलाइन पाठ्यक्रम और स्व अध्ययन कार्यक्रम: एनआईडीएम द्वारा आयोजित भाग कैसे लें	एनआईडीएम, नई दिल्ली	17 मई, 2022	डॉ. रजनीश रंजन	140
27.	घटना प्रबंधन प्रणाली/घटना प्रतिक्रिया प्रणाली का अवलोकन: संरचना, कार्य और लाभ और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिकी रोग नियंत्रण	एनसीडीसी और सीडीसी, भारत	18 मई, 2022	डॉ. हरजीत कौर	495

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
	और भारत में अमेरिकी कार्यालय के रोकथाम केंद्र सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली में आईएमएस का विस्तार कैसे करें (सीडीसी)				
28.	स्फीयर इंडिया के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय परामर्श	स्फीयर इंडिया, दिल्ली	20 मई, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	91
29.	आपातकाल के दौरान हैम रेडियो संचार एनआईडीएम द्वारा आयोजित	एनआईडीएम, नई दिल्ली	29 मई, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	203
30.	बुनियादी ढांचे पर चक्रवात का प्रभाव	एनआईडीएम, नई दिल्ली	23 मई, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	245
31.	आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग	एनआईडीएम, नई दिल्ली	24 मई, 2022	श्री गौतम कृष्ण	125
32.	घटना कार्य योजना का अवलोकन: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), भारत में अमेरिकी कार्यालय के सहयोग से उद्देश्य एवं रूपरेखा	एनसीडीसी और सीडीसी, भारत	25 मई, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	343
33.	एनआईडीएम द्वारा शहरी बाढ़ और उसका प्रभाव पर वेबिनार का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26 मई, 2022	डॉ. ए एल हलदर	250
34.	आपदा प्रतिरोधी कृषि के लिए संभावित खेती: एनआईडीएम द्वारा आयोजित जमीनी अनुभव	एनआईडीएम, नई दिल्ली	27 मई, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	123
35.	डीडीएमए, यूपी के सहयोग से आपदा जोखिम में कमी में गर्मी की लहरें और सूखा	डीडीएमए, यूपी	27 मई, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	95
36.	गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के सहयोग से आपदा प्रतिरोधी कृषि के लिए प्रौद्योगिकी	गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, बिहार	30 मई, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	145
37.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित हीट वेव जोखिम प्रबंधन पर वेबिनार	एनआईडीएम, नई दिल्ली	31 मई, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	130
38.	कोविड के बाद बच्चों का घर से स्कूलों तक संक्रमण: दादा रामचंद बखरू सिंधु महाविद्यालय, नागपुर के सहयोग से	दादा रामचंद बखरू सिंधु महाविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र	31 मई, 2022	श्री रंजन कुमार	293

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
	एक मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर वेबिनार का आयोजन				
कुल					**3509**
जून 2022					
39.	आईएचआर और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), भारत में अमेरिकी कार्यालय के सहयोग से कोविड-19 महामारी प्रबंधन पर विशेष जोर	एनसीडीसी और सीडीसी	01 जून, 2022	डॉ. हरजीत कौर	333
40.	एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ के सहयोग से प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन स्थिरता	एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश	05 जून, 2022	डॉ. हरजीत कौर	162
41.	पीएम 10 सूत्री एजेंडा नं. 5 और 8 लाइटनिंड और थंडरस्ट, मर्रू यूपीएसडीएमए के साथ सहयोग से जोखिम में कमी और सुरक्षा उपाय	यूपीएसडीएमए, उत्तर प्रदेश	06 जून, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	359
42.	एनआईडीएम द्वारा बिजली और शमन उपायों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	08 जून, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	44
43.	एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एन्वायर्नमेंटल टॉक्सिकोल,जी, सेफ्टी एंड मैनेजमेंट (एआईईटीएसएम), एमिटी यूनिवर्सिटी क सहयोग से महासागर जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन	एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एन्वायर्नमेंटल टॉक्सिकोलजी, सेफ्टी एंड मैनेजमेंट (एआईईटीएसएम), एमिटी यूनिवर्सिटी	08 जून, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	199
44.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और यू.एस. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), भारत में अमेरिकी कार्यालय के सहयोग से महामारी की तैयारी के लिए रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी)	एनसीडीसी और सीडीसी	08 जून, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	297
45.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित औद्योगिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता	एनआईडीएम, नई दिल्ली	10 जून, 2022	डॉ. ए एल हलदर	113

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
46.	पीएम 10 सूत्री एजेंडा नं. 05 डीडीएमए, मथुरा, यूपी के सहयोग से डीआरआर बाढ़ आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता	डीडीएमए, मथुरा, यूपी	14 जून, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	138
47.	नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी), कंट्री ऑफिस भारत के सहयोग से कोविड-19 के संदर्भ में जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव (आरसीसीई)	एनसीडीसी और सीडीसी	15 जून, 2022	डॉ. हरजीत कौर	338
48.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित आपदा प्रबंधन में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना	एनआईडीएम, नई दिल्ली	17 जून, 2022	श्री गौतम कृष्ण	126
49.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और यू.एस. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), कंट्री ऑफिस भारत के सहयोग से सुरक्षित, टिकाऊ और समुत्थानशील स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, सिस्टम और सेवाएं	एनसीडीसी और सीडीसी	22 जून, 2022	डॉ. हरजीत कौर	310
50.	डीएसपीएसआर दिल्ली के सहयोग से सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को उच्च शिक्षा में एकीकृत करना	डीएसपीएसआर दिल्ली	28 जून, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	244
51.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित कृषि और खाद्य सुरक्षा के प्रति हाइड्रोलॉजिकल समुत्थानशीलता	एनआईडीएम, नई दिल्ली	28 जून, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	100
52.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और यू.एस. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), भारत में अमेरिकी कार्यालय के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी	एनसीडीसी और सीडीसी	29 जून, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	575
53.	एनआईडीएम द्वारा भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	30 जून, 2022	श्री गौतम कृष्ण	110
		कुल			**3448**

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
			जुलाई 2022		
54.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित लाइटवेट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज	एनआईडीएम, नई दिल्ली	05 जुलाई, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	93
55.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और यू.एस. रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केन्द्र (सीडीसी), भारतीय कार्यालय के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन कार्यबल का निर्माण	एनसीडीसी, सीडीसी, भारत	17 जुलाई, 2022	डॉ. हरजीत कौर	303
56.	एनआईडीएम द्वारा बाढ़ आपदा और जोखिम न्यूनीकरण पर वेबिनार का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	12 जुलाई, 2022	डॉ. ए एल हलदर	152
57.	एनआईडीएम के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	12 जुलाई, 2022	डॉ. रजनीश रंजन	196
58.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर बाढ़ निगरानी और प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	13 जुलाई, 2022	श्री गौतम कृष्ण	119
59.	नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी), भारतीय कार्यालय के सहयोग से स्वास्थ्य संपोषण के लिए वॉश एडवोकेसी का समर्थन	एनसीडीसी, सीडीसी, भारत	13 जुलाई, 2022	डॉ. हरजीत कौर	267
60.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित पृथ्वी अवलोकन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके चक्रवात निगरानी और पूर्वानुमान	एनआईडीएम, नई दिल्ली	15 जुलाई, 2022	श्री गौतम कृष्ण	91
61.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और यू.एस. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के भारतीय कार्यालय के सहयोग से जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं की स्वास्थ्य आपात स्थिति पर वेबिनार	एनसीडीसी, सीडीसी, भारत	20 जुलाई, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	325
62.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित महामारी के दौरान मास्क के उपयोग के फायदे और नुकसान	एनआईडीएम, नई दिल्ली	22 जुलाई, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	77

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
63.	केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ के सहयोग से बागवानी फसलों में आपदा प्रबंधन	केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ	26 जुलाई, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	108
64.	सतत् समुत्थानशील विकास एनआईडीएम द्वारा आयोजित	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26 जुलाई, 2022	प्रो. संतोष कुमार	178
65.	नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी), भारतीय कार्यालय के सहयोग से कोविड-19 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रशिक्षण और मनोसामाजिक प्रभाव	एनसीडीसी, सीडीसी, भारत	26 जुलाई, 2022	डॉ. हरजीत कौर	252
66.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित बिजनेस स्टार्टअप्स में आपदा समुत्थानशीलता और स्थिरता	एनआईडीएम, नई दिल्ली	27 जुलाई, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	65
67.	एनआईडीएम द्वारा आकस्मिक सूखा: जोखिम को समझने एवं समुत्थानशीलता के विकास पर वेबिनार का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	27 जुलाई, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	94
68.	एनआईडीएम द्वारा प्रतिक्रिया और राहत में हितधारकों की भूमिका और समन्वय पर वेबिनार का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	28 जुलाई, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	100
69.	कोविड-19 प्रतिक्रिया में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका पर गोलमेज सम्मेलन: अखिल भारतीय आपदा न्यूनीकरण संस्थान के सहयोग से दीर्घकालिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण सबक	एआईडीएमआई, गुजरात	29 जुलाई, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	85
कुल					**2505**
अगस्त 2022					
70.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के भारतीय कार्यालय के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और रणनीतियों को एकीकृत करने पर वेबिनार	एनसीडीसी, सीडीसी, भारत	03 अगस्त, 2022	डॉ. हरजीत कौर	226

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
71.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और यू.एस. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के भारतीय कार्यालय के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन क्षमता का विकास	एनसीडीसी, सीडीसी, भारत	10 अगस्त, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	224
72.	सौर वृक्ष और सुनामी बेल्ट में नवाचार	एनआईडीएम, नई दिल्ली	12 अगस्त, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	75
73.	वी.वी. वन्नियापेरुमल महिला कॉलेज के सहयोग से यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन पर वेबिनार	वी.वी. वन्नियापेरुमल महिला कॉलेज, विरुधुनगर, तमिलनाडु	17 अगस्त, 2022	डॉ. बालू आई	286
74.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण में वित्त पोषण:	15वां वित्त आयोग और दिशानिर्देश (राहत, शमन और पुनर्निर्माण) एनआईडीएम, नई दिल्ली	17 अगस्त, 2022	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	201
75.	हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) खतरे का आकलन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	17 अगस्त, 2022	डॉ. ए एल हलदर	150
76.	शहरी अग्नि जोखिम शमन: अनुभव और पहल	एनआईडीएम, नई दिल्ली	17 अगस्त, 2022	डॉ. आमिर अली खान	105
77.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और यू.एस. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के भारतीय कार्यालय के सहयोग से सीबीआरएन अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम अभ्यास	एनसीडीसी, सीडीसी, भारत	17 अगस्त, 2022	डॉ. हरजीत कौर	177
78.	भारत के पॉन्डमैन श्री रामवीर तंवर के साथ एक बातचीत और अनुभव साझा करने का सत्र	एनआईडीएम, नई दिल्ली	24 अगस्त, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	69
79.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी), भारतीय कार्यालय के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन में उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ	एनसीडीसी, सीडीसी, भारत	24 अगस्त, 2022	डॉ. हरजीत कौर	352
80.	आरआर में आपदा प्रबंधन योजनाओं का महत्व	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26 अगस्त, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	94

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
81.	आपातकालीन परिचालन केंद्र	एनआईडीएम, नई दिल्ली	29 अगस्त, 2022	श्री गौतम कृष्ण	147
82.	शहरी समुत्थानशीलता: डीआरआर के लिए एक मार्ग	एनआईडीएम, नई दिल्ली	29 अगस्त, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	88
83.	मानसिक स्वास्थ्य और आपदाएं	एनआईडीएम, नई दिल्ली	31 अगस्त, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	85
84.	भूस्खलन प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक तरीके और उपकरण	एनआईडीएम, नई दिल्ली	31 अगस्त, 2022	श्री गौतम कृष्ण	104
85.	समुदाय और जलवायु परिवर्तन: प्रभाव, अनुकूलन और संवेदनशीलता-चुनौतियाँ और समाधान	एनआईडीएम, नई दिल्ली	31 अगस्त, 2022	श्री अली हैदर	240
86.	कांगसबाती रिवरसाइड कटाव के लिए जैव-इंजीनियरिंग	एनआईडीएम, नई दिल्ली	31 अगस्त, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	151
87.	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) और अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) का भारत स्थित कार्यालय के सहयोग से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में एक स्वास्थ्य अवधारणा को समझने का प्रयास	एनसीडीसी, सीडीसी, भारत	31 अगस्त, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	194
कुल					**2968**
सितम्बर 2022					
88.	एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, लखनऊ के सहयोग से 'प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए डिजाइनिंग और प्रबंधन तकनीक' पर वेबिनार	एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, लखनऊ	01 सितंबर, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	145
89.	बाढ़ आपदा प्रबंधन पर वेबिनार	एनआईडीएम, नई दिल्ली	05 सितंबर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	216
90.	'नकद और वाउचर सहायता' पर प्रशिक्षण कार्यशाला सह वेबिनार	स्फीयर इंडिया, नई दिल्ली	10 सितंबर, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	104
91.	रासायनिक उद्योगों में आपदा-कारण और प्रभाव	एनआईडीएम, नई दिल्ली	14 सितंबर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	210
92.	जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन और आगे बढ़ने पर वेबिनार श्रृंखला'	एनसीडीसी, सीडीसी, भारत	14 सितंबर, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	278

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
93.	आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए पृथ्वी अवलोकन डेटा के अनुप्रयोग पर वेबिनार	एनआईडीएम, नई दिल्ली	17 सितंबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	134
94.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विरासत संरक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के विषय पर वेबिनार	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए)	20 सितंबर, 2022	श्री अली हैदर	105
95.	सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (ए), विशाखापत्तनम और इंडियन जियोटेक्निकल सोसाइटी विशाखापत्तनम चैप्टर के सहयोग से 'भारत में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम: बेहतर निर्माण के लिए अनुभव और पहल' पर वेबिनार	सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (ए), विशाखापत्तनम और इंडियन जियोटेक्निकल सोसाइटी विशाखापत्तनम चैप्टर	20 सितंबर, 2022	डॉ. आमिर अली खान	130
96.	'मेट्रोलॉजिकल खतरों में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की भूमिका'	एनआईडीएम, नई दिल्ली	23 सितंबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	238
97.	'आपदा प्रतिरोधी कृषि'	एनआईडीएम, नई दिल्ली	23 सितंबर, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	36
98.	'2047: आपदा जोखिम न्यूनीकरण'	एनआईडीएम, नई दिल्ली	23 सितंबर, 2022	श्री अली हैदर,	72
99.	'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रकृति-आधारित समाधान'	एनआईडीएम, नई दिल्ली	23 सितंबर, 2022	डॉ. कोपल वर्मा	72
100.	'आपदा प्रबंधन में प्रारंभिक चेतावनी और संचार की भूमिका'	एनआईडीएम, नई दिल्ली	30 सितंबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	132
101.	स्कूल सुरक्षा आपदा जोखिम न्यूनीकरण	एनआईडीएम, नई दिल्ली	30 सितंबर, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	69
102.	भूस्खलन शमन के लिए जैव-इंजीनियरिंग विधि: कार्यक्षेत्र का एक अनुभव	एनआईडीएम, नई दिल्ली	30 सितंबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	76
कुल					**2017**
अक्टूबर 2022					
103.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित भारतीय हिमालय में हिमपात और हिमस्खलन संबंधी खतरे	एनआईडीएम, नई दिल्ली	12 अक्टूबर, 2022	डॉ. ए एल हलधर	128
104.	इंडिया रेजिलिएशन डायलॉग 2022 पर	स्फीयर इंडिया,	28 अक्टूबर, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	143

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
	हाइब्रिड कार्यक्रम: स्फीयर इंडिया, नई दिल्ली के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण की पुनर्कल्पना	नई दिल्ली			
105.	अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस-2022 के अवसर पर सीडीसी और आईएपीजी भारत के सहयोग से 'सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई' विषय पर विशेषज्ञ संवाद का आयोजन	सीडीसी और आईएपीजी भारत	28 अक्टूबर, 2022	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	182
106.	इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्रमोशन जियोएथिक्स-आईएपीजी और एडमास यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल के सहयोग से 'एसएफडीआरआर, एसडीजी और सीसीए के लिए जियोएथिक्स की वकालत' विषय पर वेबिनार	जियोएथिक्स-आईएपीजी और एडमास यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ	13 अक्टूबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	131
107.	मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय के सहयोग से निर्मित धरोहर का आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर)	मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय	17 अक्टूबर, 2022	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	175
108.	एनआईडीएम द्वारा बढ़ते शहरी जोखिमों के लिए शहरी नियोजन का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	17 अक्टूबर, 2022	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	71
109.	भारत में आपदा न्यूनीकरण: 15वें वित्त आयोग के तहत एक वित्तीय दृष्टिकोण	एनआईडीएम, नई दिल्ली	21 अक्टूबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	98
110.	एनआईडीएम द्वारा एनआईडीएम के ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26 अक्टूबर, 2022	डॉ. रजनीश रंजन	110
111.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित रासायनिक आपदा सुरक्षा और रोकथाम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	28 अक्टूबर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	116
112.	एनआईडीएम द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का स्वास्थ्य मूल्यांकन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	28 अक्टूबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	99
113.	एनआईडीएम द्वारा भूस्खलन शमन और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी और नवाचार के फायदे का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	28 अक्टूबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	41
114.	आईएमपीआरआई के सहयोग से 15वां वित्त आयोग और आपदा जोखिम प्रबंधन का आयोजन	आईएमपीआरआई, नई दिल्ली	28 अक्टूबर, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	261
कुल					**1555**

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
नवंबर 2022					
115.	समुत्थानशीलता के लिए चिंतन और रोड मैप	एनआईडीएम, नई दिल्ली	04 नवंबर, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	68
116.	एनआईडीएम द्वारा साइबर हमला आपदा प्रबंधन का आयोजन	एनआईडीएम द्वारा आयोजित	04 नवंबर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	66
117.	भारद्वाज शिक्षा संस्थान (बीएसएस) के सहयोग से डीआरआर (लैंगिक, बुजुर्ग, दिव्यांग) में समावेशी भागीदारी	भारद्वाज शिक्षा संस्थान (बीएसएस)	15 नवंबर, 2022	श्री अली हैदर,	141
118.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामुदायिक रेडियो प्रौद्योगिकी	एनआईडीएम, नई दिल्ली	22 नवंबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	119
119.	फिक्की के सहयोग से आपदा प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी	एफआईसीसीआई नई दिल्ली	25 नवंबर, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	104
120.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित आपातकालीन संचालन केंद्र	एनआईडीएम द्वारा आयोजित	25 नवंबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	76
121.	भारत में आपदा प्रबंधन का कानूनी ढांचा	एनआईडीएम, नई दिल्ली	25 नवंबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	102
122.	एनआईडीएम द्वारा वन खतरों का आयोजन	एनआईडीएम द्वारा आयोजित	29 नवंबर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	112
123.	स्वदेशी ज्ञान और आपदा जोखिम प्रबंधन	आरएटीएच (रेकग्नाइज अवैल ट्रांसफॉर्म हेरिटेज)	30 नवंबर, 2022	श्री अली हैदर	142
124.	आपदा प्रबंधन में आपातकालीन संचार	एनआईडीएम, नई दिल्ली	30 नवंबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	89
कुल					**1019**
दिसंबर 2022					
125.	एनआईडीएम द्वारा हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और डीआरआर का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	07 दिसंबर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	102
126.	सांस्कृतिक धरोहर आपदा जोखिम न्यूनीकरण	हेरिटेज सिनर्जीज इंडिया (एचएसआई) मुंबई	07 दिसंबर, 2022	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	138
127.	आईएमपीआरआई, नई दिल्ली के सहयोग से 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुकाबला'	आईएमपीआरआई, नई दिल्ली	07 दिसंबर, 2022	डॉ. श्वेता बैद्य	285
128.	पीएम एजेंडा नंबर 2-आपदाओं के खिलाफ वित्तीय समुत्थानशीलता	एनआईडीएम, नई दिल्ली	14 दिसंबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	71

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
129.	एनआईडीएम द्वारा सुरंगों में सुरक्षा और डीआरआर का आयोजन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	15 दिसंबर, 2022	डॉ. ए एल हलदर	121
130.	सांस्कृतिक धरोहर पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव	मिरासी हेरिटेज मैनेजमेंट मुंबई	16 दिसंबर, 2022	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	143
131.	सामुदायिक समुत्थानशीलता के निर्माण के लिए मिशन जीवन का वैश्विक आउटरीच कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	23 दिसंबर, 2022	श्री श्रेयश द्विवेदी	160
132.	सुनामी जागरूकता और तैयारी	भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना श्रृंखला केंद्र	26 दिसंबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	81
133.	भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26 दिसंबर, 2022	श्री गौतम कृष्ण	105
		कुल			**1206**
		जनवरी 2023			
134.	आपदा प्रबंधन में ड्रोन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	12 जनवरी, 2023	श्री श्रेयश द्विवेदी	111
135.	श्रीमा महिला समिति, पश्चिम बंगाल के सहयोग से सुंदरबन हेरिटेज डेल्टा, इसकी संवेदनशीलता और तैयारी के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण	श्रीमा महिला समिति, पश्चिम बंगाल	13 जनवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	68
136.	सुंदरबन में असंतुलन और आपदा चुनौतियों से निपटने के लिए इसकी संभावित रणनीतियाँ	श्रीमा महिला समिति, पश्चिम बंगाल	16 जनवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	176
137.	हेरिटेज प्रिजर्वेशन एटेलियर (एचपीए) चंडीगढ़ के सहयोग से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संग्रहालय का निर्माण	हेरिटेज प्रिजर्वेशन एटेलियर (एचपीए) चंडीगढ़	17 जनवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	210
138.	हेरिटेज प्रिजर्वेशन एटेलियर (एचपीए) प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से संग्रहालयों और विरासत स्थलों के लिए डीआरआर	हेरिटेज प्रिजर्वेशन एटेलियर (एचपीए) प्रा. लिमिटेड	25 जनवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	130
139.	'आपदा जोखिम प्रबंधन: अधिक जिम्मेदार सहयोगात्मक समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता'	एनआईडीएम, नई दिल्ली	25 जनवरी, 2023	डॉ. श्वेता बैद्य	70
140.	आपदा प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी	एनआईडीएम, नई दिल्ली	31 जनवरी, 2023	श्री गौतम कृष्ण	104
141.	आपातकालीन परिचालन केंद्र	एनआईडीएम, नई दिल्ली	31 जनवरी, 2023	श्री गौतम कृष्ण	116
		कुल			**985**

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
फरवरी 2023					
142.	आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का अनुप्रयोग	एनआईडीएम, नई दिल्ली	01 फरवरी, 2023	श्री गौतम कृष्ण	146
143.	आपदा प्रबंधन में 3डी सांस्कृतिक धरोहर दस्तावेजीकरण का महत्व	केयर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, त्रिची	13 फरवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	145
144.	धरोहर भवन और संग्रहालयों के लिए जोखिम न्यूनीकरण प्रथाएँ या तकनीकें	त्रिची कंसल्टेंसी प्रा0 लिमिटेड, नई दिल्ली	14 फरवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	141
145.	आपदा प्रबंधन में पूर्व चेतावनी प्रणाली की भूमिका	एनआईडीएम, नई दिल्ली	15 फरवरी, 2023	श्री गौतम कृष्ण	124
146.	धरोहर पर शहरीकरण का खतरा: इंटेक बैंगलोर के सहयोग से प्रभाव और आकलन को समझना	इंटेक बेंगलुरु	17 फरवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	117
147.	मिथिला अस्मिता ट्रस्ट दिल्ली के सहयोग से डीआरआर के लिए ग्रामीण महिला कारीगरों की आजीविका कार्यक्रमों को मुख्यधारा से जोड़ना	मिथिला अस्मिता ट्रस्ट, दिल्ली	20 फरवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	167
148.	रूफटॉप, मुंबई के सहयोग से भारत की पारंपरिक कला और शिल्प के लिए डीआरआर	रूफटॉप, मुंबई	21 फरवरी, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	121
कुल					**961**
मार्च 2023					
149.	ड्रोहाग फाउंडेशन, गुरुग्राम के सहयोग से भारत में ऐतिहासिक जिलों की सांस्कृतिक धरोहरों के आपदा जोखिम में कमी	द्रोह फाउंडेशन, गुरूग्राम	13 मार्च, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	105
150.	खतरे में धरोहररू पुरातात्विक स्थलों के लिए पर्यावरणीय और मानव खतरों का समाधान	सांस्कृतिक विरासत अनुसंधान केंद्र और केएलई लॉ कालेज, बेंगलुरु, कर्नाटक	15 मार्च, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	140
151.	इतिहास का संरक्षणरू सांस्कृतिक विरासत जोखिम न्यूनीकरण के लिए सर्वोत्तम अभ्यास	सांस्कृतिक विरासत अनुसंधान केंद्र और केएलई लॉ कॉलेज, बेंगलुरु, कर्नाटक	16 मार्च, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	179
152.	पारिस्थितिकी म्यूजियम और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए एसियाटिक सोसायटी के साथ सहयोग में बदलती प्रवृत्तियाँ	सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए (एएसएसएसआर)	17 मार्च, 2023	श्री अली हैदर, कनिष्ठ सलाहकार	146

क्र.सं	पाठयक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
153.	साइबर खतरे और संवेदनशीलताएं	एनआईडीएम द्वारा आयोजित	23 मार्च, 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	86
154.	एनआईडीएम द्वारा आयोजित औद्योगिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं समुत्थानशीलता	एनआईडीएम द्वारा आयोजित	24 मार्च, 2023	प्रोफेसर सूर्य प्रकाश	133
		कुल			**789**
महायोग					**24154**



nidm

समुत्थानशील भारत - आपदा मुक्त भारत

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

प्लॉट नं. 15, पॉकेट 3, ब्लॉक–बी, सेक्टर–29, रोहिणी, दिल्ली–110042
ईमेलः ed.nidm@nic.in | वेबसाईटः https://nidm.gov.in